दैनिक जागरण

परिकल्पना विचार का आधार है

हिमालय की निगरानी

नेपाल में आई विनाशकारी आपदा केवल इस देश के लिए ही आघातकारी नहीं है। यह भारत के लिए भी दुख और चिंता का कारण बनी है। एक तो इसलिए, क्योंकि इस आपदा में बड़ी संख्या में भारतीयों ने भी अपनी जान गंवाई है और दूसरे इसलिए कि नेपाल की नदियां जब भी उफनाती हैं तो वे बिहार और उत्तर प्रदेश के एक हिस्से में भी बाढ़ का कारण बनती हैं। इन स्थितियों में यह आवश्यक हो जाता है कि भारत और नेपाल आपस में मिलकर ऐसे किसी तंत्र की स्थापना करें, जिससे हिमालय में होने वाले हिमस्खलन और भूस्खलन की सतत निगरानी की जा सके। इस निगरानी की आवश्यकता केवल इसलिए नहीं है कि हिमालय एक नाजुक पर्वतीय संरचना है, बल्कि इस कारण भी है कि यह वह क्षेत्र है जो ग्लोबल वार्मिंग के चलते ग्लेशियरों को लगातार पिघलता हुआ देख रहा है। वैसे तो ये ग्लेशियर कई नदियों के उद्गम स्थल हैं, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के चलते जब वे अचानक तेजी से पिघलते हैं तो पर्वतीय नदियों में विनाशकारी बाढ़ का कारण बनते हैं। ऐसी बाढ़ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से लेकर पूर्वोत्तर में भी देखने को मिल चुकी है। ग्लेशियरों में टूट-फूट का सिलसिला तेज होने के कारण वैसी आपदाओं की आशंका बढ़ गई है, जैसी पिछले दिनों तिब्बत और नेपाल में देखने को मिली। ग्लेशियरों के टूटने-पिघलने से पर्वतीय नदियों में अचानक आने वाली बाढ़ इसलिए कहीं अधिक विनाशकारी हो जाती है, क्योंकि उनके तटों पर आबादी की बसाहट बढ़ती जा रही है। आबादी की यह बसाहट नदियों के किनारों पर अतिक्रमण का कारण भी बनती है। स्पष्ट है कि पर्वतीय क्षेत्रों में नदियों किनारे होने वाली बसाहट पर सख्ती से रोक लगाई जानी चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो आने वाले समय में हिमालय क्षेत्र की पर्वतीय नदियों में अचानक आने वाली बाढ़ कहीं अधिक जन-धन हानि का कारण बनेगी।

वैसे तो आवश्यकता इस बात की है कि हिमालयी क्षेत्र के सभी देश ग्लेशियरों की निगरानी के लिए कोई साझा तंत्र विकसित करें, लेकिन इसमें संदेह है कि सभी देश और विशेष रूप से चीन इसमें स्वेच्छा से शामिल होने के लिए आगे आए। ऐसे में कम से कम भारत, नेपाल और भूटान को तो एकजुट होना ही चाहिए। हिमालय क्षेत्र में होने वाली दुर्घटनाएं लगातार यह संकेत कर रही हैं कि हिमालयी आपदाओं को किसी राष्ट्र विशेष की सीमा में नहीं सीमित किया जा सकता। हिंदूकुश-हिमालय क्षेत्र में हजारों ग्लेशियर और झीलें हैं। इन सभी की निगरानी की आवश्यकता कहीं अधिक बढ़ गई है। एक समय हिमालय की चोटियों पर होने वाले बदलाव की निगरानी करना कठिन था, लेकिन आज ऐसी तकनीक उपलब्ध है, जिससे यह काम कहीं अधिक आसानी से किया जा सकता है। अब इसे किया ही जाना चाहिए।

रेवड़ी न बने बिजली

बिजली उपभोग की कीमत वसूलने में हीलाहवाली से बोझ उन उपभोक्ताओं पर पड़ता है जो ईमानदारी से अपना बिल जमा करते हैं। हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश में कई ऐसी जगहों की पहचान की गई है, जहां बिजली वितरण व्यय का भार अंततः यही ईमानदार उपभोक्ता उठाते हैं, जबकि बिजली चोरी करने वाले बेफ्रिक रहते हैं। व्यक्तिगत नैतिकता इतनी छीज गई है कि मुरादाबाद में चोरी रोकने में परेशान हो बिजली विभाग ने अंततः वहां ऐसे क्षेत्र चिह्नित किए, जहां अब घरों से मीटर उखाड़कर बिजली के खंभों पर लगाए जाएंगे, ताकि मीटर में छेड़छाड़ न हो सके। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में लाया गया दूसरा घटनाक्रम तो और भी चौंकाने वाला है। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के आपूर्ति क्षेत्र वाले गौतमबुद्ध नगर में बड़े हिस्सों में हजारों घरों में अवैध बिजली कनेक्शन से ठेकेदार करोड़ों की वसूली कर रहे हैं। यहां वैध कनेक्शन देने में निगम के हाथ डूब क्षेत्र के नियमों और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के निर्देशों के कारण बंधे हैं। सक्षम प्राधिकारी के स्तर से नियमों में संशोधन होना चाहिए। जब डूब क्षेत्र में दो वर्ष पूर्व अचल संपत्ति की रजिस्ट्री का प्रविधान कर दिया गया तो न सही बिजली के स्थायी किंतु अस्थायी कनेक्शन के लिए तो रास्ता तय होना चाहिए। हर यूनिट की खपत का मूल्य वसूला जाना चाहिए ताकि बिजली चोरी का बोझ ईमानदार उपभोक्ता पर न पड़े।

हर यूनिट की खपत का मूल्य वसूला जाना चाहिए ताकि बिजली चोरी का बोझ ईमानदार उपभोक्ताओं पर न पड़े

एससीओ का तीसरा स्तंभ बने भारत

श्रीराम चौलिया

भारत जब शंघाई सहयोग संगठन का पूर्ण सदस्य बना तो मध्य एशियाई देशों की अपेक्षा थी कि वह इस संगठन में रूस और चीन के सापेक्ष तीसरे स्तंभ के तौर पर शक्ति संतुलन लाएगा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की बैठक में भाग लेने जा रहे हैं। भौगोलिक आकार और सदस्य देशों की जनसंख्या के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संस्थान एससीओ अपनी स्थापना की रजत जयंती मना रहा है। इस उपलक्ष्य में आशा है कि भारत अधिक सक्रिय भूमिका निभाते हुए अपने हितों को आगे बढ़ाएगा। भारत वर्ष 2017 से इस संस्था का स्थायी सदस्य है और अपनी अलग पहचान बनाने के लिए प्रयासरत है। चीन और रूस जैसे दिग्गज आरंभ से ही इस संगठन का हिस्सा रहे हैं। जबकि कजाखस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान जैसे छोटे मध्य एशियाई देश भी संगठन के सह-संस्थापक थे, जो इन दो महारथी देशों के बीच अपने हितों को संतुलित करते आ रहे हैं। वर्ष 2017 से भारत जब पूर्ण सदस्य बना तो मध्य एशियाई देशों की अपेक्षा थी कि वह रूस और चीन के सापेक्ष तीसरे स्तंभ के तौर पर शक्ति संतुलन लाएगा। भारतीय सोच से यह अपेक्षा मेल भी खाती है, क्योंकि मध्य एशिया को नई दिल्ली में 'विस्तारित पड़ोस' माना जाता है और वहां पैठ बनाना आर्थिक और भूराजनीतिक दृष्टिकोण से लाभदायी है। एससीओ में आकर भारत ने एशिया को ही संगठन के केंद्रबिंदु के रूप में रखने के सिद्धांत को बल दिया है, ताकि छोटे देशों को दबदबे में रहने पर विवश न होना पड़े।

देखा जाए तो यूरेशिया की भूराजनीति और प्रतिस्पर्धा के कारण एससीओ में भारत अब तक उतना प्रभावशाली नहीं हो पाया है। भारत के प्रमुख हितैषी रूस ने जब एससीओ में उसकी पूर्ण सदस्यता का प्रस्ताव रखा तो चीन ने उस पहल को रोकने के बजाय एक सौदेबाजी के तहत अपने करीबी मित्र पाकिस्तान को भी सदस्यता दिलाई, ताकि भारत 'संतुलन बनाने वाले' के बजाय 'संतुलित' होकर रह जाए। पाकिस्तान 2017 से ही चीन के कनिष्ठ साझेदार के रूप में एससीओ में भारत के लिए बाधाएं खड़ी करता आया है। सुरक्षा के मुद्दों पर भारत ने एससीओ में जब भी आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद के विरुद्ध दोहरे मापदंड को त्यागकर सख्त कदम उठाने की मांग की और साझा रणनीति बनाने का प्रस्ताव रखा तो पाकिस्तान ने चीनी मदद से उसमें अवरोध ही खड़े किए। जैसे 2025 में एससीओ रक्षा मंत्रियों के घोषणापत्र के मसौदे में पाकिस्तान के भीतर बलूचिस्तान में जफर एक्सप्रेस रेल हमले की तो निंदा की गई, लेकिन भारत के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का उल्लेख नहीं किया गया। इससे पहले 2023 में जब भारत ने एससीओ की अध्यक्षता के दौरान सीमापार आतंकवाद और आतंकी ठिकानों को खत्म करने के लिए संयुक्त घोषणापत्र में ठोस कार्रवाई वाली भाषा को शामिल करना चाहा तो चीन, पाकिस्तान ने उसे कमजोर कर दिया। एससीओ मूलतः प्रांतीय सुरक्षा को कायम करने के उद्देश्य से बनाया गया था, पर चीन और पाकिस्तान ने इस मोर्चे पर अपेक्षित प्रगति होने ही नहीं दी।

अवधेश राजपूत

जहां तक भारत की बात है तो उसने आतंकवाद के सभी स्वरूपों से लड़ने की प्रतिबद्धता के अलावा एससीओ में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान को भी प्राथमिकता दी है। इसका परोक्ष निशाना एक तरह से चीन ही है, जिसने अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी बीआरआइ के तहत गुलाम जम्मू-कश्मीर के इलाकों पर पाकिस्तान के अवैध कब्जे को मान्यता दी है और छोटे विकासशील देशों को कर्ज में डुबोया है। दिल्ली संयुक्त बयान (2023) में भारत ने चीनी परियोजना बीआरआइ का समर्थन करने से इन्कार कर दिया था और इन विषयों पर असहमति के कारण उस वर्ष की शिखर बैठक को केवल तीन घंटों से कम अवधि में आनलाइन सम्मलेन कराकर निपटा दिया था। एससीओ की भारतीय अध्यक्षता के दौरान निराशा के चलते भले ही इस संगठन की अहमियत पर सवाल उठे, लेकिन भारत मैदान छोड़कर भागने वालों में से नहीं है। खासकर जब वह मध्य एशिया के साथ व्यापार और रक्षा संबंध मजबूत करना चाहता है। इसी क्रम में भारत ने 2022 में मध्य एशिया के सभी पांच देशों के साथ पहली बार संयुक्त शिखर बैठक आयोजित की। इन देशों के साथ भारत के आर्थिक संबंध भी धीरे-धीरे प्रगाढ़ हो रहे हैं। पाकिस्तान द्वारा मध्य एशिया से सीधे जमीनी संपर्क रोके जाने के बावजूद भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह और खासकर एयर फ्रेट कारिडोर का इस्तेमाल करके इन देशों को दवाइयां, मेडिकल उपकरण और मशीनरी का निर्यात बढ़ाया है। चीन और रूस की तुलना में भारत अब भी मध्य एशियाई देशों का बहुत बड़ा व्यापारिक साझेदार नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के सापेक्ष अफगानिस्तान का रणनीतिक कायापलट और भारतीय सामान को मध्य एशिया तक पहुंचाने के लिए अफगानिस्तान का उत्साह व्यापार बढ़ाने के नए रास्ते खोल रहा है। अफगानिस्तान को एससीओ का पूर्ण सदस्य बनाने के लिए तो भारत को पैरवी करनी चाहिए।

इसमें संदेह नहीं कि सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर में भारत चीन से आगे है और इन सेवाओं के लिए भौगोलिक कनेक्टिविटी की भी जरूरत नहीं है। भारत मध्य एशिया में प्रौद्योगिकी के मोर्चे पर नेतृत्वकर्ता बनने की स्थिति में है और वह एससीओ को इस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने में प्रयासरत भी है। एससीओ का इतिहास भी देखें तो रूस ने यूरेशिया में चीन के आर्थिक वर्चस्व पर लगाम देने का प्रयास किया है। एससीओ में भारत के उत्थान से रूस आश्वस्त हो सकता है कि संगठन में आर्थिक मुद्दों को प्राथमिकता देने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि भारत उनमें विविधीकरण ला सकता है। ऐसे में एससीओ के अंदर रूस-भारत तालमेल को नए अंदाज से आगे ले जाना अनिवार्य होगा। किर्गिस्तान में एससीओ सम्मलेन से इतर प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की द्विपक्षीय बैठक इस संदर्भ में अहम होने वाली है। कुल मिलाकर, एससीओ से भारत को मिले-जुले परिणाम प्राप्त हुए हैं, लेकिन अगर भारत अपनी निजी क्षमताओं और बदलते भूराजनीतिक समीकरणों के आधार पर इस संगठन में टिक कर अपनी स्थिति बेहतर बना लेता है, तो यूरेशिया में तीसरा ध्रुव बनने की आकांक्षा को पूरा कर सकेगा।

(लेखक जिंदल स्कूल आफ इंटरनेशनल अफेयर्स में प्रोफेसर और डीन हैं)
response@jagran.com

हर मिनट का हिसाब दे संसद

संसद में विधेयक या तो अटकते हैं या पर्याप्त पड़ताल के बिना पारित हो जाते हैं। यह अब आदत बनती जा रही हैं

प्रो. गौरव वल्लभ

पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के संसदीय उत्पादकता डैशबोर्ड के अनुसार संसद के मानसून सत्र में लोकसभा ने 17.5 घंटे यानी निर्धारित समय का 15 प्रतिशत काम किया, जबकि राज्यसभा ने 37.37 घंटे यानी 33 प्रतिशत काम किया। पूरे सत्र में प्रत्येक सदन के लिए लगभग 114 घंटे निर्धारित थे। इस हिसाब से लोकसभा में करीब 96.5 घंटे और राज्यसभा में 76.6 घंटे का काम नहीं हो सका। दोनों सदनों को जोड़ें तो कुल 173.1 सदन-घंटे का काम नहीं हुआ। आम तौर पर बताए जाने वाले प्रति सदन प्रति मिनट 1.25 लाख रुपये को 173.1 घंटे की कमी पर लागू करें तो पूरे सत्र की संकेतात्मक अवसर लागत करीब 130 करोड़ रुपये बैठती है। यह ऐसी धनराशि नहीं है, जिसे वापस पाया जा सकता था। कर्मचारियों, सुरक्षा, प्रसारण और बुनियादी ढांचे पर खर्च चलता ही रहता है। यह करदाताओं के पैसे से उपलब्ध उस क्षमता का पैमाना है, जो संसदीय काम में नहीं रूपांतरित हो सकी। वित्तीय लागत तो समस्या का केवल दिखाई देने वाला सिरा है। जब प्रश्नकाल नहीं चलता तो मंत्री उन सवालों से बच जाते हैं, जिन्हें पूछने के लिए करदाता संसद का खर्च उठाते हैं। जब शून्यकाल शोर में डूब जाता है तो निर्वाचन क्षेत्रों की चिंताओं का राष्ट्रीय मंच छिन जाता है। जब विधायी समय सिकुड़ता है तो विधेयक या तो अटकते हैं या पर्याप्त पड़ताल के बिना पारित हो जाते हैं। यह अब अपवाद नहीं, आदत बनती जा रही है। संसद तब काम करती है, जब राजनीतिक पक्ष तमाशे की जगह विचार-विमर्श को चुनते हैं। जेन-जी और मिलेनियल्स गतिविधि और उपलब्धि का फर्क अच्छी तरह समझते हैं। उनकी पेशेवर और नागरिक जिंदगी रियल-टाइम डैशबोर्ड, सेवा रेटिंग, डिलीवरी की समयसीमा और सामने दिखते परिणामों से जुड़ी है। वे पूछते हैं, 'आपकी मौजूदगी से बदला क्या?' सर्वोच्च विचार-विमर्श संस्था के लिए वे इस पुराने मानक को स्वीकार नहीं करेंगे।

चिंतित करती संसद की घटती उत्पादकता। फाइल

संसद कोई कंपनी नहीं है और सांसद कार्यपालिका के कर्मचारी नहीं हैं। असहमति भी एक पक्ष है। एक तीखा सवाल काम है। किसी विधेयक के विरुद्ध तर्कपूर्ण भाषण काम है। विरोध भी संसद का वैध साधन है, लेकिन बार-बार नारेबाजी करके सदन स्थगित कराना अलग बात है। इससे एक समूह का विरोध हर दूसरे सदस्य और मतदाता के अधिकार पर वीटो बन जाता है। संसद को सुचारु रूप से चलाने की जिम्मेदारी साझा है। कामकाज की सूची पारदर्शी ढंग से रखना, पर्याप्त समय पहले सूचना देना, विपक्ष के जायज मुद्दों के लिए स्थान देना और मंत्रियों से जवाब सुनिश्चित करना सरकार का पहला दायित्व है, लेकिन संस्थागत कामकाज में विपक्ष कोई दर्शक नहीं है। जिस मंच से वह कार्यपालिका की जांच करता है, उसे बचाए रखने की उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी उसकी भी है। सदन चलाने की जिम्मेदारी एक दल को सौंपकर दूसरा दल व्यवधान को अपनी मुख्य उपलब्धि नहीं बना सकता। संसद में जिस मंत्री से जवाब मांगा जा रहा हो, वह हर आरोप सुनकर सदन में उत्तर देने को तैयार हो, तो संसदीय मंच से इन्कार क्यों?

जो विपक्ष जवाबदेही की मांग करता है, उसका मूल्यांकन उसके सवालों, विकल्पों और हस्तक्षेपों की गुणवत्ता से होना चाहिए, न कि उसके कारण हुए स्थगनों की संख्या से। उपस्थिति और भत्ते की व्यवस्था इस प्रतीकात्मक समस्या को सामने लाती है। वर्तमान दैनिक भत्ता 2,500 रुपये है और संसद की बैठक वाले दिन सदस्य इस भत्ते की पात्रता प्रक्रिया के तहत उपस्थिति रजिस्टर पर हस्ताक्षर करता है। यात्रा भत्ता एक अलग वैधानिक अधिकार है और उसे इन हस्ताक्षरों से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए।

भारत को सरकार, विपक्ष और पीठासीन अधिकारियों की सहमति से एक 'संसदीय कार्य-निष्पादन संकल्प' चाहिए। इसका पहला नियम सरल होना चाहिए: बिना भरपाई के कोई घंटा बर्बाद नहीं होगा। यदि व्यवधान के कारण निर्धारित काम नहीं हो पाता, तो सदन देर तक बैठे, एक अतिरिक्त दिन काम करे या उसी सत्र में उस समय की भरपाई करे। राजनीतिक असहमति कार्यसूची का क्रम बदल सकती है, लेकिन वह कुल संसदीय काम को कम नहीं कर सकती। दूसरा, विरोध के अधिकार के साथ बहस की सुनिश्चित राह भी होनी चाहिए। राजनीतिक दलों को यह संकल्प लेना चाहिए कि एक बार समय आवंटित होने पर बहस अवश्य होगी। सरकार जवाब दे, विपक्ष सुने, प्रतिवाद करे और मतदान करे। जवाबदेही संसद की दोतरफा प्रक्रिया है, टेलीविजन का एकतरफा प्रदर्शन नहीं। तीसरा, संसद को एक समान रियल-टाइम डैशबोर्ड प्रकाशित करना चाहिए। इसमें सत्यापित उपस्थिति, सदन में मौजूद रहने की अवधि, पूछे गए प्रश्न, बहस में भागीदारी, समिति का काम, गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य, जांच के लिए भेजे गए विधेयक, गंवाया गया समय और उसकी भरपाई का ब्योरा हो। संसद, विचार-विमर्श और समाधान के लिए है, ठहराव को तात्कालिक राजनीतिक लाभ में बदलने के लिए नहीं।

(लेखक प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

ईश्वर की योजना

मनुष्य किसी दुखद घटना को लेकर इतना व्याकुल रहता है कि उसे अपना दुख सबसे कष्टदायी लगता है। पीड़ा आती है, कोई संबंध टूटता है, कोई प्रिय वस्तु हाथ से चली जाती है, कोई स्वप्न अधूरा रह जाता है और जीवन अचानक उस अनजानी दिशा में मुड़ जाता है, जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी। तब मन के भीतर सबसे पहले एक प्रश्न उठता है, 'ईश्वर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया?' इस प्रश्न के भीतर मनुष्य का समूचा अहंकार छिपा हुआ है। इसमें एक सूक्ष्म हठ है कि जीवन वैसा ही होना चाहिए, जैसा हमने सोचा है। परिस्थितियां हमारी इच्छा के अनुसार चलनी चाहिए। सुख हमें मिलना ही चाहिए। हालांकि जीवन का अस्तित्व मनुष्य की इच्छाओं से संचालित नहीं होता। जीवन केवल घटनाओं का क्रम नहीं, चेतना के जागरण की यात्रा है। हम ईश्वर से सुख मांगते हैं, सुरक्षा मांगते हैं, सफलता मांगते हैं, परंतु ईश्वर यदि हमारे जीवन को केवल हमारी इच्छाओं के अनुसार चलाए, तो हमारी चेतना का विस्तार कैसे होगा?

बालक को माता-पिता की गोद प्रिय होती है, किंतु माता-पिता उसे सदैव गोद में नहीं रखते। वे उसे गिरने देते हैं, स्वयं उठने देते हैं। जो हमें अंत प्रतीत होता है, वह किसी गहरी यात्रा का प्रथम चरण हो सकता है। जीवन का सबसे गहरा प्रश्न यह नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ, बल्कि यह है कि उसके बाद मेरे भीतर क्या घटित हुआ। वस्तुतः 'यह मेरे साथ ही क्यों हुआ?' के स्थान पर पूछना चाहिए 'इस घटना के माध्यम से मुझे क्या समझना है?' पहला प्रश्न हमें पीड़ित बनाता है, दूसरा हमें साधक बनाता है। जब आर्तनाद साधना में बदलता है, तब दुख पीड़ा नहीं रह जाता। वह सत्य का द्वार बन जाता है। आध्यात्मिकता का अर्थ है, जब जीवन हमारी समझ से बाहर हो जाए, तब भी हम ईश्वर की योजना पर भरोसा रखें।

ट्विंकल तोमर सिंह

रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण निर्णय

सुनीता मिश्रा

रक्षा उत्पादन में सार्वजनिक क्षेत्र की 76 प्रतिशत हिस्सेदारी बताती हैं कि निजी क्षेत्र को अभी लंबा रास्ता तय करना हैं

देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए डीआरडीओ द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की तकनीक भारतीय उद्योगों को हस्तांतरित करने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य मिसाइलों का बड़े पैमाने पर उत्पादन बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना, सेना को समय पर हथियार उपलब्ध कराना और रक्षा क्षेत्र में घरेलू कंपनियों की भूमिका का विस्तार करना है।

भारत की रक्षा जरूरतें बड़ी हैं और सुरक्षा वातावरण लगातार जटिल हो रहा है। ऐसे में केवल अत्याधुनिक हथियार विकसित करना पर्याप्त नहीं है। युद्ध जैसी स्थिति में हथियारों की तेजी से भरपाई और लंबे समय तक उत्पादन जारी रखने की क्षमता भी सैन्य शक्ति का अहम हिस्सा है। रूस-यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया के संघर्षों ने दिखाया है कि आधुनिक युद्ध में मिसाइलों और अन्य सटीक हथियारों की खपत कितनी तेजी से बढ़ सकती है।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में देश का रक्षा उत्पादन बढ़कर रिकार्ड 1.78 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया, जो 2024-25 के 1.54 लाख करोड़ रुपये से 15.6 प्रतिशत अधिक है। वहीं, कुल उत्पादन में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़कर 24 प्रतिशत यानी करीब 42,000 करोड़ रुपये हो गई है। रक्षा निर्यात भी 2025-26 में रिकार्ड 38,424 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। डीआरडीओ और उद्योग के बीच सहयोग का आधार भी पहले से तैयार हो चुका है। मार्च 2026 तक 134 कंपनियां डीआरडीओ के विकास-सह-उत्पादन भागीदार के रूप में जुड़ चुकी थीं। इस दौरान 2,180 तकनीक हस्तांतरण समझौते किए गए और 2,780 से अधिक बौद्धिक संपदा अधिकार उद्योगों के उपयोग के लिए उपलब्ध कराए गए। पिछले एक दशक में भारत ने निवेश में वृद्धि, नीतिगत सुधारों, तकनीकी नवाचार और वैश्विक साझेदारियों के माध्यम से अपनी रक्षा क्षमताओं में उल्लेखनीय विस्तार किया है। इस फैसले से निजी कंपनियों, एमएसएमई और अन्य तकनीकी भागीदारों की भूमिका बढ़ेगी।

हालांकि, इसे केवल निजी कंपनियों के लिए कारोबारी अवसर के रूप में देखना भूल होगी। मिसाइल अत्यंत संवेदनशील रक्षा प्रणालियां हैं। तकनीक हस्तांतरण के साथ गुणवत्ता नियंत्रण, साइबर सुरक्षा, बौद्धिक संपदा की रक्षा, परीक्षण और उत्पादन की निगरानी भी उतनी ही जरूरी होगी। इसके अलावा वास्तविक आत्मनिर्भरता तब होगी, जब भारतीय कंपनियां हस्तांतरित तकनीकों को आगे विकसित कर नई पीढ़ी की मिसाइलों, प्रणोदन, गाइडेंस और सेंसर प्रणालियों में अपनी डिजाइन व अनुसंधान क्षमता बढ़ाएं। इसके लिए निजी उद्योग, डीआरडीओ, विश्वविद्यालयों और स्टार्टअप के बीच दीर्घकालीन अनुसंधान सहयोग जरूरी है।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

रोजगार से जुड़े शिक्षा

रविवार को प्रकाशित 'रोजगारपरक शिक्षा का अभाव' शीर्षक लेख के तहत संजय गुप्त ने बिल्कुल सही कहा कि शिक्षा का उद्देश्य रोजगारपरक होना चाहिए। हर युवा का पढ़ लिखकर सरकारी नौकरी पाने का ही सपना होता है, क्योंकि सरकारी नौकरी में इन्हें अपना आज ही नहीं, बल्कि अपना कल भी सुरक्षित नजर आता है, और तो और सरकारी नौकरी में तो बुढ़ापा भी सुरक्षित हो जाता है, क्योंकि सरकारी विभागों में रिटायरमेंट के बाद अच्छी खासी पेंशन भी मिल जाती है। जबकि प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं होता है और न ही स्वरोजगार में। शिक्षा का उद्देश्य केवल अफसर या बाबू बनने का सपना नहीं होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को हर उस काम के लिए तैयार करना भी होना चाहिए जिससे वो किसी भी काम को छोटा समझकर अपने रोजगार के अवसर को ठुकरा दें और बाबू या अफसर बनने के चक्कर में अपना कीमती समय बर्बाद कर दें। जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए यदि अभी से उपाय नहीं किए गए तो भविष्य में बेरोजगारी विकट समस्या इतना विकराल रूप धारण कर लेगी कि इससे हमारे देश में बहुत ही गलत माहौल, जैसे कि अराजकता, लूटपाट, चोरी-डकैती और अपराध में बढ़ोतरी हो सकती है। स्वरोजगार को बढ़ावा देकर भी देश में रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं। अगर सरकारें कृषि, मत्स्य पालन और लगभग हर गांव में छोटी-बड़ी दूध की डेरी खोलने के लिए लोगों को विशेष पैकेज जारी किए जाएं तो इससे सरकारों को भी काफी कमाई हो सकती है।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

मेलबाक्स

शोक में शामिल होने का मामला

कांग्रेस के नेता रहे सज्जन कुमार के निधन पर तीन भाजपा सांसदों को उनके परिजनों के बीच जाकर संवेदना व्यक्त करना और उसके लिए पार्टी नेतृत्व की नाराजगी झेलना निश्चित रूप से विचारणीय है। दरअसल सज्जन कुमार 1984 के सिख-विरोधी दंगों के मामले में दोषी ठहराए गए थे और उम्रकैद की सजा भुगत रहे थे; इसलिए उनके अपराधों को भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन यह भी सच है कि शोक व्यक्त करना अपराध का समर्थन करना नहीं होता। मृत्यु के बाद किसी परिवार के दुख में शामिल होना भारतीय संस्कृति की सहज मानवीय परंपरा है। भाजपा स्वयं भारतीय संस्कृति, क्षमा, करुणा और 'मृत्यु के बाद वैर समाप्त' जैसे मूल्यों की बात करती है। फिर किसी दिवंगत व्यक्ति के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करने को राजनीतिक अपराध बना देना कितना उचित है? राजनीति की कठोरता के बीच संवेदना के लिए भी थोड़ी जगह बची रहनी चाहिए।

ओपी चौधरी, सन सिटी, रतलाम, एमपी

डिग्री की उपयोगिता का सवाल

यह सही है कि आज बीए, बीकाम और बीएससी जैसी पारंपरिक डिग्रियां बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार की दुनिया में प्रवेश दिलाने में असमर्थ दिखाई देती हैं। समस्या डिग्री की उपयोगिता से अधिक उस शिक्षा-दृष्टि की है, जो विद्यार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करना तो सिखाती है, लेकिन समस्या हल करना, संवाद करना, तकनीक का उपयोग करना, निर्णय लेना और स्वयं रोजगार पैदा करना नहीं सिखाती। जब 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के करोड़ों युवा न शिक्षा में हैं, न रोजगार में और न किसी प्रशिक्षण से जुड़े हैं, तो यह केवल बेरोजगारी का आंकड़ा नहीं, बल्कि हमारी मानव पूंजी के क्षरण की गंभीर चेतावनी है। हम वर्षों से 'स्किल डेवलपमेंट' की बात कर रहे हैं, लेकिन कौशल को रोजगार से जोड़ने वाली पूरी शृंखला अभी भी कमजोर है। केवल प्रमाणपत्र बांट देने से किसी युवा के हाथ में हुनर नहीं आता और न ही उसके भविष्य में रोजगार की गारंटी जुड़ती है। चुनौती यह नहीं कि हमारे पास युवाशक्ति कितनी है, क्या हमारे पास उस युवाशक्ति को उत्पादक शक्ति में बदलने की व्यवस्था है? यदि शिक्षा और रोजगार के बीच की खाई यूं ही बढ़ती रही, तो हमारा जनसांख्यिकीय लाभांश जनसांख्यिकीय दबाव में बदल सकता है।

बिमलेश कुमार सिंह चौहान, लखनऊ

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें:
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: response@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व. नरेन्द्र मोहन. नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा-201309 से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष: नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

160 किलोमीटर की दूरी है नेपाल के रसुवा जिले की, भारत-नेपाल सीमा से, जहां बुधवार को भयावह त्रासदी हुई थी। जबकि काठमांडू से इस स्थान की दूरी 120 किलोमीटर है, जो नेपाल-तिब्बत सीमा के पास स्थित है।

आजकल

हिमालय की चेतावनी को सुनने का समय

नेपाल और तिब्बत की सीमा पर एक बार फिर ऐसी त्रासदी घटित हुई है, जिसे केवल 'प्राकृतिक आपदा' कहकर भुला देना शायद इस आपदा से मिलने वाली सबसे बड़ी चेतावनी को अनसुना करना होगा। इस त्रासदी का सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह नहीं है कि कितना नुकसान हुआ, बल्कि यह है कि क्या इसे कम किया जा सकता था? अभी जो शुरुआती वैज्ञानिक आकलन आ रहे हैं, वे एक चिंताजनक घटनाक्रम की तरफ इशारा करते हैं। लिहाजा हमें हिमालय की चेतावनी को गंभीरता से लेना होगा और उसी अनुरूप नीतियों में बदलाव करने होंगे

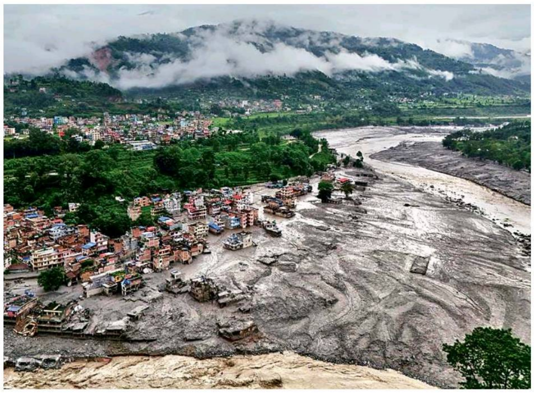

अभिषेक कुमार सिंह
संस्था टेली परफारमेंसेज से संबद्ध

नेपाल के रसुवा जिले में भोटेकोशी और आगे त्रिशूली नदी तंत्र में 26 अगस्त को अचानक पानी, बर्फ, चट्टानों और मलबे का विकराल प्रवाह आया। पहाड़ियों के बीच नदी किनारे की बस्तियां, सड़कें, पुल और दूसरे बुनियादी ढांचे इसकी चपेट में आ गए। बड़ी संख्या में लोग मारे गए हैं और लापता हैं, जिनमें नेपाल के अलावा भारतीय, तिब्बती और अन्य विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। नेपाल के जल विज्ञान एवं मौसम विज्ञान विभाग से जुड़े विशेषज्ञों के अनुसार ऊंचाई पर बर्फ और चट्टानों का विशाल हिस्सा ल्हेंदे नदी की घाटी में गिरा। इससे नदी का स्वाभाविक रास्ता लगभग 20 किमी ऊपर अवरुद्ध हो गया। माना जा रहा है कि इस रुकावट के कारण वहां संभवतः एक बड़ी अस्थायी झील बन गई। पानी, बर्फीली चट्टानों का दबाव बढ़ने पर झील रूपी प्राकृतिक बांध टूट गया और पानी, पत्थर, बर्फ तथा तलछट का विशाल प्रवाह नीचे की ओर दौड़ पड़ा। इस तरह यह बाढ़ नदी का साधारण तेज प्रवाह भर नहीं रहा, बल्कि ऐसी त्रासदी बन गया, जिसमें एक प्राकृतिक प्रक्रिया ने दूसरी त्रासदी को जन्म दिया और देखते-देखते जोखिम कई गुना बढ़ गया। यही वह बिंदु है जहां नेपाल की त्रासदी सिर्फ नेपाल की नहीं रहती। वह पूरे हिमालय की कहानी बन जाती है। नेपाल से भारत, भूटान और पाकिस्तान तक फैले उस पर्वतीय भूभाग की कहानी बन जाती है, जहां जलवायु परिवर्तन अब भविष्य की आशंका नहीं बल्कि वर्तमान का भूगोल बदल रहा है।

दरकने लगे हैं पहाड़ : हिंदूकुश-हिमालय क्षेत्र को अक्सर एशिया का 'वाटर टावर' कहा जाता है। इस इलाके में ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर बर्फ और हिमनदों का सबसे बड़ा भंडार स्थित है। इन हिमनदों (ग्लेशियरों) से निकलने वाली नदी प्रणालियों पर पहाड़ों में रहने वाले लगभग 27 करोड़ और निचले मैदानी इलाकों में निवासित दो अरब से अधिक लोगों का जीवन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्भर है। लेकिन इसी हिमालयी इलाके में ग्लेशियर, बर्फ और स्थायी रूप से जमी हुई बर्फीली भूमि अर्थात पर्माफास्ट तेजी से बदल रहा है। इस बारे में हिंदूकुश हिमालयी क्षेत्र की सुरक्षा और विकास के लिए काम करने वाले एक अंतर्सरकारी अनुसंधान केंद्र-इंटरनेशनल सेंटर फार इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट (आइसीआइएमओडी) की एक चेतावनी है। इसी वर्ष आइसीआइएमओडी की ओर से जारी की गई क्षेत्रीय रणनीति, 2026 में चेताया जा चुका है कि हिमनदों (ग्लेशियरों) के क्षय, बर्फ के पैटर्न में बदलावों और पर्माफास्ट के कमजोर पड़ने से भूस्खलन और मलबे के तेज प्रवाह के खतरे बढ़ सकते हैं। हिंदूकुश-हिमालय क्षेत्र में हिमनदों के बर्फ खोने (गलने) की दर वर्ष 2000 के बाद लगभग दोगुनी हो गई है। वर्ष 1990 से 2020 के बीच क्षेत्र के हिमनदों ने लगभग 12 प्रतिशत क्षेत्रफल और अनुमानित नौ प्रतिशत बर्फ भंडार की कमी आई थी।

यहां एक विरोधाभास समझना जरूरी है। ग्लेशियर का पिघलना केवल भविष्य में 'पानी कम होने' की समस्या नहीं है। ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने की शुरुआती चरण में उनसे बहुत अधिक मात्रा में अचानक पानी बढ़ जाने की समस्या भी पैदा हो सकती है। बर्फ पिघलते चले जाने के कारण अपने स्थान से पीछे हटते ग्लेशियर झीलें बनाते हैं; गर्म होती चट्टानें और कमजोर होता पर्माफास्ट पर्वतीय ढलानों को अस्थिर करते हैं। इससे बर्फ या चट्टानों के विशाल हिस्से झील अथवा नदी में गिर सकते हैं और कुछ ही मिनटों में सामान्य जलधारा विनाशकारी सैलाब में बदल सकती है। इसलिए जलवायु परिवर्तन का हिमालयी अर्थ केवल तापमान बढ़ना नहीं है। उसका अर्थ है पहाड़ की स्थिरता में तेजी से परिवर्तन आना।

जलवायु परिवर्तन का नया जोखिम : आइसीआइएमओडी ने इसी के साथ चेतावनी दी थी कि अधिक तापमान और थोड़े समय में होने वाली अत्यधिक बारिश फ्लैश फ्लड, भूस्खलन और ग्लेशियरों से संबंधित मलबा पैदा कर सकती है। यही नहीं, जुलाई में उसने फिर कहा था कि औसत से कमजोर मानसून का मतलब सुरक्षित मानसून नहीं है। इसका अर्थ यह था कि बारिश के लंबे सूखे अंतराल के बीच अचानक बहुत तीव्र वर्षा नई जलवायु वास्तविकता बन सकती है। इसका मतलब है कि हमें मानसून को केवल इस सवाल से मापना छोड़ना होगा कि पूरे मौसम में कितने मिलीमीटर बारिश हुई। ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि बारिश कब, कहां और कितनी तेजी से हुई। यही जलवायु परिवर्तन का नया जोखिम है, यानी औसत कभी-कभी सामान्य दिखाई दे सकता है, लेकिन चरम घटना असामान्य होती जाती है।

एक और महत्वपूर्ण बात समझने की जरूरत है। जरूरी नहीं कि जो नदी विदेश से बहकर आती है, उसके बहाव आदि में आपके क्षेत्र में कोई बदलाव आया हो। हो सकता है कि कोई ग्लेशियर या झील पड़ोसी देश में फटी हो, लेकिन उसका असर आपके देश में हो सकता है। ध्यान रखना होगा कि सीमा नदी की हो सकती है, उससे पैदा होने वाले खतरे की नहीं। हालिया नेपाल त्रासदी ने इसी कमजोर कड़ी को उजागर किया है। घटना की उत्पत्ति तिब्बत की ओर हुई और उसका विनाशकारी प्रभाव नेपाल में पहुंचा। इसमें दक्षिण एशिया के लिए बहुत बड़ा संदेश है। हिमालयी आपदाएं पासपोर्ट नहीं देखतीं। कोई हिमझील तिब्बत में टूट सकती है, उसका सैलाब नेपाल में आ सकता है और नीचे उसका असर भारत तक महसूस किया जा सकता है। नेपाल की कोसी, गंडक व अन्य नदियों में परिवर्तन भारतीय मैदानी क्षेत्रों को प्रभावित करता है।

इसलिए भारत, नेपाल, चीन, भूटान और पाकिस्तान को जलवायु तथा हिमनद संबंधी वैज्ञानिक डाटा को केवल सामरिक सूचना समझने के बजाय उसे साझा जीवन-रक्षक संपदा मानना होगा। उपग्रह के चित्रों, नदी प्रवाह, ग्लेशियरों और झीलों के स्तर, भूकंपीय संकेतों और मौसमी बदलावों से संबंधित डाटा का रीयल-टाइम आदान-प्रदान के लिए हिमालयी देशों के बीच साझा प्रोटोकाल बनाना चाहिए। कह सकते हैं कि वैज्ञानिक सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए एक क्लाइमेट डिप्लोमेसी को अजेंडे में लाना चाहिए।

हिमालयी क्षेत्र में निरंतर होने वाली गतिविधियों के प्रति आसपास के सभी देशों को सतर्क रहना होगा। फाइल

जोखिम को अनदेखा करने का दुष्परिणाम

नेपाल की मौजूदा त्रासदी इसलिए भी विचलित करती है, क्योंकि हिमालय हमें बार-बार लगभग एक ही संदेश दे रहा है। वर्ष 2013 में केदारनाथ की आपदा के बाद भी चोराबाड़ी क्षेत्र, हिमनदों, अत्यधिक वर्षा, झील और अचानक आए सैलाब की भूमिका पर लंबी बहस हुई थी। उस समय भी मुख्य प्रश्न यही था कि हिमालयी ग्लेशियरों और झीलों की वास्तविक समय में निगरानी क्यों नहीं हो रही और उपलब्ध वैज्ञानिक संकेत अंतिम व्यक्ति तक समय रहते क्यों नहीं पहुंचते। केदारनाथ त्रासदी के बाद इसी कमी को प्रमुख चिंता के रूप में चिह्नित किया गया था। इसके बाद वर्ष 2021 में चमोली, 2023 में सिक्किम की दक्षिण ल्होनक झील, 2024 में नेपाल के थामे और 2025 में ही उत्तराखंड के धराली जैसी आपदाओं ने अलग-अलग रूपों में हिमालयी आपदा-जोखिम का संकेत दिया। विडंबना यह है कि नेपाल के जिस रसुवा-केरुंग क्षेत्र में मौजूदा आपदा आई है, वहां पिछले ही साल जुलाई 2025 में भी अचानक आई बाढ़ ने जानें ली थीं और नेपाल-तिब्बत को जोड़ने वाला पुल बह गया था। यानी प्रकृति पहले ही खतरे के स्पष्ट संकेत दे चुकी थी। इसलिए यह सवाल और गंभीर हो जाता है कि किसी क्षेत्र को कितनी बार तबाह होना पड़ेगा, इससे पहले कि चेतावनी स्थायी नीति में बदले?

अर्ली वार्निंग सिस्टम : बदलता मौसम लोगों के मोबाइल पर कोई एसएमएस (संदेश) नहीं भेजता। यह काम सरकारों का होता है कि वे पुख्ता 'अर्ली वार्निंग सिस्टम' विकसित करें। लेकिन 'अर्ली वार्निंग सिस्टम' बनाने का अर्थ अक्सर बहुत सीमित समझ लिया जाता है। मोबाइल पर भारी बारिश का संदेश भेज देना पर्याप्त अर्ली वार्निंग नहीं है। हिमालयी इलाकों में हो रहे तेज बदलावों को समझने हुए जरूरत मल्टी-हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाने की है। यह केवल जमीनी निगरानी से संभव नहीं है। इसे कायम करने की पहली परत अंतरिक्ष में होनी चाहिए, जहां बेहद ऊंचे रिजोल्यूशन वाली फोटोग्राफी करने वाले उपग्रह निरंतर ग्लेशियर, हिमझील, ढलानों और नदी अवरोधों पर नजर रखें। दूसरी परत जमीन पर होनी चाहिए, जिसमें आटोमैटिक वेदर स्टेशन, जीपीएस, सीस्मिक सेंसर, स्नो तथा ग्लेशियर मानिटरिंग स्टेशन और झीलों के बढ़ते-घटते स्तर का नियमित मापन करने वाले सेंसरों का सटीक और सक्रिय नेटवर्क शामिल हो। इसकी तीसरी परत में वैज्ञानिक विश्लेषण शामिल है, जिसमें एआइ की मदद से कई मौसमी माडलों से अलग-अलग डाटा लेकर असामान्य बदलावों को तुरंत पहचाना जा सके। चौथी परत संचार की है। यानी ऐसी चेतावनियां सरकारी सुस्ती का शिकार न बनें, बल्कि सायरन, मोबाइल ब्राडकास्ट, रेडियो, स्थानीय प्रशासन और समुदायों तक तत्काल पहुंचे। इसकी आखिरी पांचवीं और सबसे महत्वपूर्ण परत है पूर्व निर्धारित कार्रवाई किया जाना। खतरे का स्तर ऊंचा होते ही किस गांव-कस्बे को कौन-से रास्ते से खाली कराया जाएगा, बसें कहां मिलेंगी, बुजुर्गों और पर्यटकों को कौन निकालेगा, इसका निर्धारण तत्काल यानी आपदा के आने से पहले होना चाहिए। यानी समस्या केवल पूर्वानुमान की नहीं, बल्कि चेतावनियों को सही समय पर सटीकता से और प्रभावित होने वाले इलाकों और लोगों तक तुरंत पहुंचाने की भी है।

(अभिषेक सिंह)

खरी-खरी

इनबाक्स के योद्धा

मनीषा मंजरी

इंटरनेट मीडिया बड़ा लोकतांत्रिक नगर है। यहां सबको बोलने की आजादी है, पर कुछ लोगों ने इस आजादी को ऐसा निजी भूखंड समझ रखा है कि सार्वजनिक चौपाल पर मौन व्रत रखते हैं और सीधे इनबाक्स की पिछली गली में दस्तक देने लगते हैं। मानो कमेंट बाक्स कोई सरकारी दफ्तर हो, जहां बोलने पर स्टांप शुल्क लगता हो और इनबाक्स पुश्तैनी बैठक, जहां बिना बुलाए भी चप्पल उतारकर बैठा जा सकता है।

इनबाक्स आजकल किसी बरसाती नाले जैसा हो गया है। ऊपर से देखने पर शांत, भीतर तरह-तरह की जलचर प्रजातियां तैरती हुई। कोई साहित्य के कांटे पर दोस्ती का चारा बांधकर बैठा है, तो कोई प्रशंसा की रुई में जिज्ञासा की सुई छिपाकर भेजता है। सबसे मनोरंजक दृश्य तब बना, जब एक वरिष्ठ लेखक का संदेश आया- "मुझे उस न्यूजपेपर की ईमेल आइडी चाहिए।" मैं चौंकी। जिस न्यूजपेपर में वे स्वयं कई बार छप चुके थे, उसका ईमेल मुझसे पूछ रहे थे! मुझे लगा, शायद साहित्य में भी स्मृतिलोप का नया पुरस्कार शुरू हो गया है। फिर ध्यान आया कि यह ईमेल नहीं, संवाद का बहाना है।

देखा जाए तो इंटरनेट मीडिया का यह इनबाक्स अब एक अदृश्य वन है। बाहर मोर नाचते दिखाई देते हैं, भीतर झाड़ियों में संदेशों के शिकारी दुबके रहते हैं। सार्वजनिक मंच पर उनके शब्दों को घुटनों का दर्द हो जाता है, पर निजी संदेशों में वे ओलिंपिक धावक बन जाते हैं। आखिरकार मैंने समाधान खोज लिया। अब जो भी इनबाक्स में लिखता है- "आपकी कहानी बहुत अच्छी लगी" तो मैं मुस्कराकर उत्तर देती हूं- "धन्यवाद! यही बात कमेंट बाक्स में भी लिख दीजिए। वहां साहित्य आक्सीजन पर है।"

बस, उसके बाद ऐसा मौन छा जाता है कि लगता है मेरे संदेश ने नहीं, किसी जादूगर ने इनबाक्स पर ताला जड़ दिया हो। तब समझ में आता है कि कुछ लोग कहानी पढ़ने नहीं आते, वे तो केवल इनबाक्स में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने आते हैं। साहित्य उनके लिए बहाना है और इनबाक्स उनका प्रिय पर्यटन स्थल। बेचारा कमेंट बाक्स अब भी दरवाजे पर दीपक जलाए बैठा है, किसी सच्चे पाठक की प्रतीक्षा में।

पोस्ट

हर साल मानसून आता है और मुंबई, दिल्ली, गुरुग्राम जैसे विकसित आधुनिक शहरों से जलभराव से दुर्दशा की तस्वीरें भी आती हैं। विडंबना है कि 5,000 साल पहले प्राचीन भारत के धौलावीरा में नगर नियोजन, जल प्रबंधन, वाटर चैनल्स और जलाशयों में अभियांत्रिकी का कौशल चकित करता है।

राजेश शुक्ला@astroraj

राहुल जी का 'प्लास्टिक कप' वाला बयान दिखाता है कि वे जमीनी हकीकत से कितने दूर हैं। पेपर कप का इस्तेमाल सुविधा और साफ-सफाई के लिए होता है, न कि भेदभाव के लिए। राहुल जी देश आगे बढ़ चुका है, लेकिन आपकी राजनीति आज भी सिर्फ समाज को बांटने और पुरानी रूढ़ियों को जबरन जिंदा रखने पर टिकी है।

अमित यादव@amityadavamit

संघ प्रमुख मोहन भागवत ने न्यूयार्क में कहा, 'भारत में कोई मुस्लिम न रहे, ऐसा सोचने वाला हिंदू हो ही नहीं सकता।' उन्होंने स्पष्ट किया कि यहां दोनों का साझा अस्तित्व है व धर्म-मजहब अलग हो सकते हैं, पर सभी रास्ते एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। इन बातों से ममदानी जैसों को झटका लगा होगा।

दीपक चौरसिया@DChaurasia2312

जागरण जनमत — कल का परिणाम

भाजपा सांसदों का सज्जन कुमार की शोक सभा में जाने से पार्टी को नुकसान होगा?

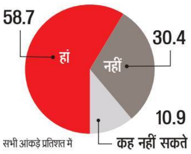

सभी आंकड़े प्रतिशत में

आज का सवाल

क्या बीए, बीएससी और बीकाम जैसी पारंपरिक डिग्रियों का पाठ्यक्रम एवं संरचना बदलना आवश्यक हो गया है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है

जनपथ

बंदी बन कर हैं पड़े उधर मियां इमरान,
चिंतित हैं उनके लिए कई पूर्व कप्तान।
कई पूर्व कप्तान कह रहे उन्हें बचाओ,
बहुत हो चुकी जेल उन्हें अब बाहर लाओ।
पर मुनीर की चाल बहुत दिखती है गंदी,
जिसकी सीधी रीढ़ उसे रक्खे वह बंदी!

-ओम प्रकाश तिवारी

भारतीय बसंत कुमार
वरिष्ठ समाचार संपादक, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश डायरी

लाभार्थी राजनीति का 'रक्षा-बंधन'

राज्य परिवहन निगम की बस में सवार होकर जब मुख्यमंत्री स्टैंडिंग पोज में सेल्फी का फ्रेम गढ़ते हैं, तो उसके चतुर्दिक उन महिलाओं की बस यात्री के रूप में उपस्थिति रहती है, जिनके लिए रक्षाबंधन के दिन की यात्रा अब जीवन भर के लिए यादगार बन जाएगी। रक्षाबंधन के दिन तो सभी महिलाओं को निश्शुल्क यात्रा पहले से ही मिल रही थी, अबकी वरिष्ठ महिला नागरिकों को जीवन पर्यंत सभी राजकीय बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा शुरू की गई है। ऐसी महिलाओं की संख्या प्रदेश में करीब एक करोड़ है। ज्यों-ज्यों उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, योगी आदित्यनाथ सरकार की घोषणाओं में लाभार्थी समूह के रूप में महिलाओं, युवाओं पर फोकस बढ़ता जा रहा है। यूपी की राजनीतिक धरा पर सपा प्रमुख के रूप में अखिलेश यादव भी 'तू डाल-डाल तो मैं पात-पात' का दांव चल रहे हैं। महिला आरक्षण के ओज के बीच कांग्रेस में प्रियंका गांधी की सतत सक्रियता, सपा में डिंपल यादव का अखिलेश यादव के साथ प्रेस कान्फ्रेंस और अन्य पार्टी कार्यक्रम में लगातार साझीदार होना और भाजपा में स्मृति ईरानी का उत्तर प्रदेश में संगठनात्मक नव प्रभुत्व अनायास नहीं है। सबके अपने-अपने निहितार्थ हैं।

यूजीसी विवाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लंबे समय तक मौन रहकर प्रदेश की राजनीति में उफान मारती प्रतिकूलता साधने में सफल रहे। दिल्ली के जंतर-मंतर के आंदोलन की आग उत्तर प्रदेश में नहीं पसरी। चंदा चोरी की आग में भी योगी आदित्यनाथ की शासकीय छवि नहीं झुलसी। युवाओं की बड़ी संख्या वाले उत्तर प्रदेश में जेन-जी का आंदोलन भले ही जोर न पकड़ा हो, पर योगी सरकार का वर्तमान फोकस 'कानून-व्यवस्था और हिंदुत्व' वाले पारंपरिक भाजपा नैरेटिव से आगे बढ़कर लाभार्थी, जेन-जी को संबोधित रोजगार के अवसर और महिलाओं के बीच भरोसे की ओर बढ़ता दिख रहा है। छह माह में एक लाख युवाओं को नौकरी देने का खांचा अस्पष्ट है, पर यह तय है कि जेन-जी को संतुष्ट करने के लिए सीएम की घोषणा के अनुरूप नियुक्ति पत्र बांटने के शिविर लगाने ही होंगे।

वर्ष 2027 में भाजपा के सामने मुख्य चुनौती केवल अपने समर्थक आधार को बनाए रखना नहीं, बल्कि महिलाओं, युवाओं और पहली बार के युवा मतदाताओं में सरकार के प्रति भरोसे को बनाए रखना होगी। अपने-अपने आधार वोटों की 'रक्षा' और उनको अपने सापेक्ष 'बंधन' में कसे रखना ही 2027 के चुनाव की अग्निपरीक्षा में सफल होने का मंत्र होगा, यह भाजपा भी जानती है और मुख्य प्रतिद्वंद्वी सपा भी। एक ओर दस साल के शासन के प्रति उपजा विक्षोभ भाजपा के लिए चुनौती हो सकती है, तो दूसरी ओर लाभार्थी समूह के बीच पैठ उसकी शक्ति।

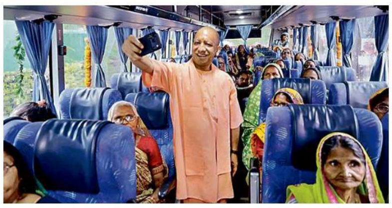

महिलाओं को बस से रवाना करने के दौरान सेल्फी लेते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सूचना विभाग

पचास हजार पढ़ाकू बेटियों को स्कूटर बांटने, मिड-डे-मील की रसोइयों का मानदेय बढ़ा देने, सेविका-सहायिका की पगार बढ़ाने, साठ साल उम्र की महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा जैसी घोषणाओं के सापेक्ष अखिलेश यादव भी महिलाओं को 40 हजार एकमुश्त देने, टैबलेट बांटने और आंगनबाड़ी में काम करने वालों की पगार तीन गुना कर देने के आश्वासन में नहीं चूकते हैं।

चुनाव भले चंद माह दूर है, पर घोषणा पत्र के नए-नए पन्ने रोज दलों की ओर से लिखे-भरे जा रहे हैं। नोएडा में जब श्रमिक आंदोलन जोर पकड़ा, उपद्रव बढ़ा तो सरकार ने कानूनी सख्ती के साथ श्रमिक हित की भी चिंता की। यह कड़ी बढ़ रही है। अब नई घोषणा श्रमिकों को पांच से दस रुपये में भरपेट भोजन कराने की है। लगभग पौने दो करोड़ पंजीकृत मजदूरों की संख्या वाले प्रदेश में इस योजना के अभी घोषित होने के सीधे राजनीतिक निहितार्थ हैं। भाजपा के लिए महिला मतदाता पहले से महत्वपूर्ण आधार हैं। इसलिए स्कूटर जैसी दिखने वाली और सीधे लाभ पहुंचाने वाली योजना का राजनीतिक असर नकद सहायता से इसलिए अलग हो सकता है, चूंकि यह कहीं न कहीं लड़कियों को स्वयं के प्रति भरोसा जगाने का उपकरण भी है। बेटियों को साधने के साथ ही बुजुर्ग महिला वोटरों को यात्रा का लाभ केवल आर्थिक राहत नहीं है।

सरकार का जोर केवल सरकारी नौकरी पर नहीं, बल्कि स्टार्टअप और उद्यमिता पर भी है। भाजपा यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि युवा केवल सरकारी नौकरी के पीछे न रहें। प्रांतीय रक्षा दल के जवानों को चिकित्सा सुविधा, स्कूल-कालेज के शिक्षकों और शिक्षामित्रों को हेल्थ कार्ड व उनका बढ़ा मानदेय जैसे बंधन पहले ही बांधे गए हैं। राजनीति में 'चवन्नी' उछल रही है। परिवार में पांच सांसदों के मजबूत गठजोड़ का अखिलेश का गर्व और योगी आदित्यनाथ की ओर से इस गर्व को जनता पार्टी जैसा हश्र हो जाने की जिद्दी भविष्यवाणी के बीच जो तय है, वह यह कि यूपी की सियासी जमीन पर पाशा उछालने की गति और तेज होगी।

मंथन

डा. मीना कुमारी
लोक नीति विश्लेषक

भविष्य के भारत का स्वरूप

पिछले कुछ माह से जेन-जी और जेन-अल्फा को लेकर नए सिरे से चर्चा हो रही है। ऐसे में भविष्य के भारत के स्वरूप के निर्धारण में उनकी भूमिका भी समझी जानी चाहिए

नई पीढ़ी को लेकर चिंता नई नहीं है। लगभग हर दौर में बड़ों को लगता रहा है कि अगली पीढ़ी की भाषा बदल गई है, संस्कार बदल गए हैं, प्राथमिकताएं बदल गई हैं और वह पहले जैसी नहीं रही। आज जेन-जी और जेन-अल्फा ऐसे ही नए नाम हैं, जिनके माध्यम से युवाओं के व्यवहार, आकांक्षाओं, भाषा, तकनीक-निर्भरता और सामाजिक दृष्टिकोण को समझने की कोशिश की जा रही है।

हालांकि नई पीढ़ी को लेकर चिंता करनेवाली पीढ़ी को ये सब सवाल पूछते समय खुद से भी सवाल करना चाहिए कि यह बदलाव उनमें हुआ है, तो क्या इसके लिए उनकी भी कोई जिम्मेदारी है या नहीं? हर नई पीढ़ी को गढ़ने का काम तो ठीक उसके पहले की पीढ़ी ही करती है। बदलाव एक शाश्वत प्रक्रिया भी है। इसके नाम पर बनाव हो रहा है या बिगड़ाव, यह सवाल जरूर अहम हो जाता है। लेकिन भारत के संदर्भ में एक बुनियादी प्रश्न पूछा जाना चाहिए- क्या पश्चिमी समाज में विकसित पीढ़ीगत वर्गीकरण भारतीय समाज की जटिलता और उसकी सांस्कृतिक निरंतरता समझ सकते हैं?

भारत में मनुष्य की पहचान को केवल उसके जन्म-वर्ष से परिभाषित करने की परंपरा नहीं रही। भारतीय चिंतन ने जीवन को ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास जैसे आश्रमों तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जैसे पुरुषार्थों के व्यापक संदर्भ में देखा। यहां जीवन केवल उम्र का क्रम नहीं, बल्कि दायित्व, अनुभव, आत्मविकास और सामाजिक उत्तरदायित्व की यात्रा है। इसलिए जेन-जी या जेन-अल्फा जैसे शब्द उपयोगी सामाजिक संकेतक हो सकते हैं, लेकिन उन्हें भारतीय युवा की संपूर्ण पहचान मान लेना हमारी दृष्टि को सीमित कर सकता है।

वस्तुतः युवा हमेशा बदलता है। हर युग की परिस्थितियां उसे नए अनुभव देती हैं, इसलिए उसकी भाषा, ऊर्जा, प्राथमिकताएं और संघर्ष के तरीके भी बदलते हैं। लेकिन भारतीय समाज की विशिष्टता यह रही है कि परिवर्तन के बावजूद पीढ़ियों के बीच संबंध और सामाजिक निरंतरता बनी रही। तकनीकी विकास इसका एक दिलचस्प उदाहरण है। कंप्यूटर की प्रत्येक नई पीढ़ी पिछली पीढ़ी से अधिक तेज, अधिक सक्षम और अपेक्षाकृत अधिक हल्की हुई। लेकिन उसने अपनी पिछली पीढ़ी के अनुभव और उपलब्धियों को मिटाकर अपनी पहचान नहीं बनाई। विकास का अर्थ केवल पुराने को छोड़ देना नहीं, बल्कि उससे सीखकर नया गढ़ना भी है। युवा बदला है, लेकिन समाज से उसका रिश्ता नहीं टूटना चाहिए।

सूचना आज जिस अभूतपूर्व गति से प्रसारित हो रही है, उसमें किसी भी सामाजिक नामकरण और उसकी व्याख्या को गंभीरता तथा धैर्य से करना पहले से अधिक जरूरी हो गया है। यदि हम कहते हैं कि आज का युवा स्क्रीन पर अधिक निर्भर है, परिवार से संवाद कम करता है, धैर्य खो रहा है या परंपराओं से दूर जा रहा है, तो हमें यह भी पूछना होगा- इस वातावरण का निर्माण किसने किया? बच्चे के हाथ में स्मार्टफोन किसने दिया? उसके खाली समय को डिजिटल मनोरंजन से किसने भर दिया? बातचीत की जगह स्क्रीन ने क्यों ले ली? परिवार में संवाद का समय क्यों कम हुआ?

जिस दुनिया को हमने बनाया है, उसी दुनिया में पली-पीढ़ी के व्यवहार पर केवल उसी को दोष देना आत्ममंथन से बचना होगा। शिक्षा में डिजिटल साक्षरता के साथ डिजिटल विवेक, रोजगार में कौशल के साथ मानवीय क्षमता और युवा कार्यक्रमों में अवसरों के साथ नागरिक उत्तरदायित्व को समान महत्व दिया जाना चाहिए। विद्यालय और विश्वविद्यालय केवल रोजगार की तैयारी के केंद्र नहीं, बल्कि ऐसे स्थान होने चाहिए, जहां युवा प्रश्न पूछना, असहमति व्यक्त करना, संवाद करना और जिम्मेदारी के साथ निर्णय लेना सीखें।

युवा को समझने का सबसे प्रभावी रास्ता उसके बारे में अनुमान लगाना नहीं, बल्कि उससे संवाद करना है। उसकी बात सुनना, उसके अनुभवों को समझना और उसकी ऊर्जा को राष्ट्र निर्माण के अवसरों से जोड़ना ही आने वाली पीढ़ी के साथ सार्थक संबंध की आधारशिला बन सकता है। इस पूरी प्रक्रिया में परिवार की भूमिका सबसे बुनियादी है। बच्चों को स्क्रीन से दूर करने का सबसे प्रभावी उपाय केवल स्क्रीन-टाइम की सीमा तय करना नहीं, बल्कि ऐसा पारिवारिक वातावरण बनाना है जिसमें बातचीत, पुस्तक, खेल, कला, प्रकृति और साथ रहने का आनंद मौजूद हो।

नई पीढ़ी को केवल यह बताना पर्याप्त नहीं कि उसे क्या नहीं करना चाहिए। उसे यह अनुभव भी देना होगा कि क्या करना सार्थक है। आज भारत के सामने असली चुनौती यह नहीं है कि जेन-जी कैसी है या जेन-अल्फा कैसी होगी। असली चुनौती यह है कि हम अपनी अगली पीढ़ी को केवल आधुनिक और तकनीकी रूप से सक्षम बनाएंगे, या आधुनिकता के साथ मानवीय, उत्तरदायी और अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ा हुआ भी बनाएंगे। यही प्रश्न आने वाले भारत का स्वरूप तय करेगा।

भारतीय समाज में होने वाले परितर्वन के बीच सभी पीढ़ियों को बिठाना होगा तालमेल। फाइल

चिली के साथ इसी वर्ष पूरी हो जाएगी व्यापार वार्ता

नई दिल्ली : वाणिज्य मंत्रालय ने रविवार को कहा कि इस वर्ष चिली के साथ एक व्यापक व्यापार समझौते से जुड़ी वार्ता पूरी हो जाएगी। इससे दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूती मिलेगी। व्यापार सचिव राजेश अग्रवाल व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा के लिए इन समय चिली में ही हैं। मंत्रालय ने कहा कि प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (सीईपीए) से व्यापार और निवेश के नए अवसर खुलने की उम्मीद है। (प्रेट्र)

हमें उम्मीद है कि इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक वाहनों की मांग मजबूत बनी रहेगी और सभी सेगमेंट में मजबूत आर्डर बुक के साथ इसमें बढ़ोतरी जारी रहेगी।
– गिरीश वाघ, सीईओ, टाटा मोटर्स लिमिटेड

पीएमएस या म्यूचुअल फंड : निवेश से पहले टैक्स-लागत जैसी बातों का रखें ध्यान

म्यूचुअल फंड और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज (पीएमएस) ऐसी निवेश योजनाएं हैं जो निवेशकों को विभिन्न फंडों या एसेट्स में निवेश का अवसर देती हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि म्यूचुअल फंड सभी प्रकार के, खासतौर पर छोटे निवेशकों के लिए बेहतर है, जबकि पीएमएस बड़े निवेशकों के लिए सही है। ऐसे में निवेश के लिए म्यूचुअल फंड या पीएमएस का चुनाव करते समय टैक्स और लागत संबंधी बातों का ध्यान रखना चाहिए। म्यूचुअल फंड और पीएमएस का चयन करते समय ध्यान रखने वाली बातें बता रहे हैं
मनोज कुमार

लेनदेन पर टैक्स

म्यूचुअल फंड निवेश में आपका फंड मैनेजर स्टाक खरीदने-बेचने का काम करता है। इसमें आपको प्रत्येक लेनदेन पर टैक्स नहीं देना होता है। इसका असर केवल आपकी नेट एसेट वैल्यू (एनएवी) पर दिखता है। पीएमएस में हर बार लाभ होने पर टैक्स आपको देना होता है। म्यूचुअल फंड में शार्ट टर्म या लांग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ सकता है। यदि म्यूचुअल फंड के सभी लेनदेन पर टैक्स का हिसाब निवेशक के स्तर पर लगाया जाए तो रिटर्न में 10 प्रतिशत तक की कमी आ सकती है। पीएमएस में टैक्स का यह नुकसान सीधे आपकी जेब से जाता है।

पोर्टफोलियो मैनेजर का चयन

पीएमएस में फंड मैनेजर का चयन निवेशकों को खुद करना पड़ता है। इन मैनेजर्स के प्रदर्शन का डाटा एसोसिएशन आफ पोर्टफोलियो मैनेजर्स इन इंडिया (एपीएमआइ) की वेबसाइट पर उपलब्ध है। पीएमएस में निवेश से पहले इस वेबसाइट पर जाकर मैनेजर्स के अनुसार रिटर्न के डाटा की जांच की जा सकती है। म्यूचुअल फंड में हर फंड हाउस अपने सबसे अनुभवी लोगों को लगाता है। फंड अच्छा प्रदर्शन करता है तो ज्यादा पैसा आता है। इससे कंपनी और निवेशक दोनों को फायदा होता है।

सत्यापन की समस्या

म्यूचुअल फंड में हर दिन की एनएवी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होती है और निवेशक उसकी कीमत पर पैसा लगाते हैं। पीएमएस में पारदर्शिता की कमी है और बताए गए रिटर्न का म्यूचुअल फंड की तुलना में सख्ती से सत्यापन नहीं हो पाता है। पीएमएस का रेग्युलेशन ढीला है, जबकि म्यूचुअल फंड कहीं ज्यादा कड़ी निगरानी में काम करते हैं। जानकारों का कहना है कि एक अच्छा, सरल और कम लागत वाला म्यूचुअल फंड भी लंबी अवधि में पीएमएस जैसा या उससे बेहतर रिटर्न दे सकता है।

निवेश लागत व जोखिम

म्यूचुअल फंड निवेश में लागत काफी कम होती है। इसके सापेक्ष पीएमएस में निवेश की लागत काफी ज्यादा होती है। पीएमएस में आमतौर पर म्यूचुअल फंड की तुलना में ज्यादा मैनेजमेंट और परफार्मेंस फीस लगती है। इसमें जोखिम भी ज्यादा है। म्यूचुअल फंड निवेश में जोखिम कम होता है। वहीं, पीएमएस में ज्यादा रिटर्न की संभावना के बीच जोखिम भी अधिक होता है। ऐसे में पीएमएस में बेहतर रिटर्न पाने के लंबे समय तक निवेश करना जरूरी है।

म्यूचुअल फंड और पीएमएस के बारे में

- पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज यानी पीएमएस एक ऐसी निवेश सेवा है जिसमें पोर्टफोलियो मैनेजर किसी व्यक्ति के निवेश का प्रबंधन उनके वित्तीय लक्ष्यों के हिसाब से करते हैं। म्यूचुअल फंड को खासतौर पर छोटे निवेशकों के लिए बनाया गया है।
- म्यूचुअल फंड में मासिक या एकमुश्त निवेश किया जा सकता है। इस पैसे को पोर्टफोलियो मैनेजर अलग-अलग फंडों में निवेश करते हैं। म्यूचुअल फंड के उलट पीएमएस में पैसा एक साझा फंड में जमा किया जाता है।
- म्यूचुअल फंड में निवेशकों को यूनिट आवंटित की जाती हैं। पीएमएस में निवेशक को स्टाक और दूसरे एसेट्स का सीधा मालिकाना हक मिलता है।
- पीएमएस में निवेशक की जोखिम लेने की क्षमता, पसंद और लक्ष्यों के अनुसार निवेश का तरीका पूरी तरह से कस्टमाइज किया जा सकता है, जबकि म्यूचुअल फंड में मैनेजर ज्यादा से ज्यादा रिटर्न के लिए निवेश करते हैं।
- पीएमएस में कम से कम 50 लाख रुपये का निवेश किया जाता है। यह अमीर निवेशकों के लिए है जो इससे जुड़े जोखिमों को संभाल सकते हैं। म्यूचुअल फंड में 100 या 500 रुपये जैसी छोटी राशि से भी निवेश किया जा सकता है।
- पीएमएस में पोर्टफोलियो मैनेजर निवेशक की तरफ से निवेश फैसले ले सकता है। फंड मैनेजर सलाह देता है और निवेशक अंतिम फैसला करता है या मैनेजर सलाह देता है और निवेशक खुद लेनदेन करता है। म्यूचुअल फंड में निवेशक केवल पैसा देता है और फंड मैनेजर सारे फैसले करता है।

जागरण इन्फो

एनएसई का एक प्रतिशत हिस्सा बेचेंगे एसबीआइ व सब्सिडियरी

- आइपीओ में एसबीआइ 0.65% व एसबीआइ कैपिटल मार्केट्स 0.35% हिस्सेदारी बेचेंगे
- एसबीआइ, एसबीआइ कैपिटल मार्केट्स के पास एनएसई की 7.56 प्रतिशत हिस्सेदारी

नई दिल्ली, प्रेट्र: नेशनल स्टाक एक्सचेंज (एनएसई) के प्रस्तावित 30 हजार करोड़ रुपये के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आइपीओ) में एसबीआइ और इसकी सब्सिडियरी अपनी एक प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेंगे। एसबीआइ के चेयरमैन सीएस शेट्टी ने एक साक्षात्कार में बताया कि बैंक इस आइपीओ में अपनी 0.65 प्रतिशत हिस्सेदारी कम करेगी। इसी प्रकार, एसबीआइ कैपिटल मार्केट्स की ओर से 0.35 प्रतिशत हिस्सेदारी बेची जाएगी।

अभी एसबीआइ और एसबीआइ कैपिटल मार्केट्स के पास एनएसई की क्रमशः 3.23 प्रतिशत व 4.33 प्रतिशत हिस्सेदारी है। यानी इन दोनों के पास एनएसई की कुल 7.56 प्रतिशत हिस्सेदारी है। शेट्टी ने स्पष्ट किया कि निकट भविष्य में अन्य सहायक कंपनियों के लिए कोई मुद्रीकरण योजना नहीं है। एसबीआइ ने पिछले महीने अपने विदेशी साझेदार अमुंडी के साथ मिलकर एसबीआइ म्यूचुअल फंड में लगभग 10 प्रतिशत हिस्सेदारी कम की थी। इस बिक्री के बाद एसबीआइ की हिस्सेदारी 61.76 प्रतिशत से घटकर 55.46 प्रतिशत हो गई। उन्होंने बताया कि पिछले वित्त वर्ष में एसबीआइ का होम लोन पोर्टफोलियो नौ लाख करोड़ रुपये का पार कर चुका है और चालू तिमाही में 10 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार जाएंगे। एसबीआइ के पास होम लोन श्रेणी में करीब 28 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी है। शेट्टी ने कहा कि मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता और ग्राहकों का बैंक की प्रक्रियाओं में विश्वास ऐसे प्रमुख कारक हैं जो ग्राहकों को एसबीआइ की ओर आकर्षित करते हैं।

लगातार दूसरे महीने शुद्ध खरीदार रहे एफपीआइ

अगस्त में अब तक विदेशी निवेशकों ने शेयरों में 30,919 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश किया

नई दिल्ली, प्रेट्र: विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआइ) अगस्त में लगातार दूसरे महीने शुद्ध खरीदार रहे हैं। सेंट्रल डिपाजिटरी सिक्योरिटीज लिमिटेड (सीडीएसएल) के डाटा के अनुसार, 30 अगस्त तक एफपीआइ भारतीय शेयरों में 30,919 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश कर चुके हैं। कारपोरेट कमाई में सुधार, मजबूत आर्थिक गतिविधियों, रुपये में स्थिरता और भू-राजनीतिक चिंताओं में कमी के कारण विदेशी निवेशकों की गतिविधियों में यह बदलाव आया है।

इससे पहले जुलाई में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने शेयरों में 20,200 करोड़ रुपये का निवेश आया था, जो लगातार चार महीने की भारी बिकवाली के बाद एक तेज बदलाव था। एफपीआइ ने इस वर्ष जून में 49,340 करोड़ रुपये, मई में 32,963 करोड़ रुपये, अप्रैल में 60,847 करोड़ रुपये और मार्च में 1.17 लाख करोड़ रुपये की भारी निकासी की थी। हालांकि, कैलेंडर वर्ष 2026 में एफपीआइ शुद्ध विक्रेता बने हुए हैं और अब तक 2.23 लाख करोड़ रुपये की निकासी कर चुके हैं। यह कैलेंडर वर्ष 2025 की कुल निकासी 1.66 लाख करोड़ रुपये से अधिक है।

2.23 लाख करोड़ रुपये हुई 2026 में अब तक एफपीआइ निकासी, 20,200 करोड़ का निवेश किया था जुलाई में

बीते सप्ताह एफपीआइ निवेश	
24 अगस्त	1974.45
25 अगस्त	1667.85
26 अगस्त	डाटा उपलब्ध नहीं
27 अगस्त	2857.96
28 अगस्त	874.93

जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के मुख्य निवेश रणनीतिकार वीके विजयकुमार का कहना है कि भारत में एफपीआइ प्रवाह को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक रुपये में स्थिरता और सबसे महत्वपूर्ण कारपोरेट कमाई में सुधार है।

उन्होंने कहा कि वैश्विक कारक भी महीने के कुछ हिस्सों में अपेक्षाकृत सहायक बने रहे। भू-राजनीतिक चिंताओं में कमी ने जोखिम भावना को बढ़ावा दिया, जबकि अमेरिका में नरम ब्याज दरों की उम्मीदें और कोरिया व ताइवान जैसे बाजारों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ)-सेमीकंडक्टर शेयरों से वैश्विक पूंजी का रोटेशन भारत की ओर बढ़ने के लिए जगह बना रहा है। हालांकि, पश्चिम एशिया में तनाव और कच्चे तेल की कीमतों पर अनिश्चितता अभी भी एक चिंता का विषय बनी हुई है।

> आने वाले समय में निवेशक ब्रेंट क्रूड की कीमतों में उतार-चढ़ाव और अमेरिका-ईरान तनाव से जुड़े घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखेंगे। अमेरिका-कनाडा व्यापार तनाव में वृद्धि भी बाजार की अनिश्चितता को और बढ़ा सकती है और निवेशकों को सतर्क रख सकती है। – **पवित्रो मुखर्जी**, उपाध्यक्ष-शोध, बजाज ब्रोकिंग

डेट बाजार में मिला-जुला प्रदर्शन: शेयरों के उलट डेट बाजार में एफपीआइ का प्रदर्शन मिला-जुला रहा है। सीडीएसएल के डाटा के अनुसार, अगस्त में अब तक एफपीआइ ने सामान्य सीमा वाले डेट बाजार से 2318 करोड़ रुपये की निकासी है। हालांकि, इस श्रेणी में 2026 में अब तक एफपीआइ 54,119 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश कर चुके हैं। वहीं, वालेंट्री रिटेंशन रूट वाले डेट (डेट-वीआरआर) में अगस्त में एफपीआइ ने 289 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश किया है, जबकि 2026 में अब तक शुद्ध निकासी 13,001 करोड़ रुपये हो गई है।

फुली एक्सेसेबल रूट वाले डेट (डेट-एफएआर) में एफपीआइ ने अगस्त में 627 करोड़ रुपये का निवेश किया है और 2026 में कुल निवेश 39,925 करोड़ रुपये हो गया है। डेट-एफएआर में एफपीआइ लगातार चौथे महीने शुद्ध निवेश बने हुए हैं।

रूस को प्रमुख पेट्रोल आपूर्तिकर्ता बना भारत

- रिफाइनरियों पर यूक्रेन के ड्रोन हमले से रूस में पेट्रोल-डीजल की किल्लत
- पिछले दो महीनों में भारत ने रूस को 10 लाख बैरल पेट्रोल का निर्यात किया

नई दिल्ली, प्रेट्र: यूक्रेन के ड्रोन हमलों के कारण रूस में पेट्रोल की किल्लत हो गई है। इस बीच भारत रूस को एक प्रमुख पेट्रोल आपूर्तिकर्ता बनकर उभरा है। ऊर्जा विश्लेषण फर्म वोर्टेक्सा के डाटा के अनुसार, अगस्त में रूस का समुद्री पेट्रोल आयात 1.25 लाख बैरल प्रतिदिन के रिकार्ड स्तर पर पहुंच गया है।

सूत्रों के अनुसार, पिछले दो महीनों में भारतीय रिफाइनरियां रूस को करीब 10 लाख बैरल पेट्रोल की आपूर्ति कर चुकी हैं। यह आपूर्ति मुख्य रूप से गुजरात की वडिनार रिफाइनरी से की गई है। इस रिफाइनरी का संचालन नायरा एनर्जी करती है और इसमें रूस की कंपनी रोसनेफ्ट की आधी हिस्सेदारी है। 2022 से भारत ने अपने कच्चे तेल की जरूरतों के लिए रूस का रुख किया है, जो पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों के निर्माण के लिए कच्चा माल है।

भारत के रूस से कच्चे तेल की खरीद ने रिकार्ड उच्च स्तर को छू लिया है और खाड़ी में संघर्ष ने अन्य स्रोतों से आपूर्ति को सीमित कर दिया है। भारत ने जून और जुलाई में रूस से 26 लाख बैरल प्रतिदिन से अधिक कच्चा तेल आयात किया, जो देश के कच्चे तेल आयात का करीब आधा हिस्सा है। संभावना है कि रूस को निर्यात किया गया ईंधन संभवतः इसी रूसी कच्चे तेल से बनाया गया है।

रूस कच्चे तेल का एक बड़ा निर्यातक है और अपने ऊर्जा इन्फ्रास्ट्रक्चर पर यूक्रेनी ड्रोन हमलों के कारण उसे पेट्रोल आयात करना पड़ रहा है। इन हमलों के कारण रूस के घरेलू उत्पादन में 70 प्रतिशत तक की गिरावट आई है। भारत, तुर्किये और मोरक्को ने अगस्त में रूस को पेट्रोल की आपूर्ति की है। रूस ने इसी वर्ष जुलाई पेट्रोल निर्यात पर प्रतिबंध को बढ़ाकर जनवरी 2027 तक कर दिया था। वोर्टेक्सा के अनुसार, उत्पादन में कमी के कारण रूस आगे भी पेट्रोल का आयात जारी रख सकता है।

बिजनेस से जुड़ी खबरों और अपडेट के लिए स्कैन करें या विजिट करें jagran.com

अंतरराष्ट्रीय

रक्षा समझौते के बाद तुर्किये, सऊदी अरब व पाक के बीच आज पहली बैठक

- बैठक में तीनों देशों के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री के साथ ही सेना प्रमुख भी शामिल होंगे

इस्तांबुल, रायटर : तुर्किये, सऊदी अरब व पाकिस्तान के बड़े अधिकारी सोमवार को इस्तांबुल में उस संयुक्त रक्षा समझौते के तहत पहली बैठक करेंगे, जिस पर उन्होंने इसी महीने हस्ताक्षर किए थे। तुर्किये के विदेश मंत्रालय के सूत्र ने बताया कि इस्तांबुल में होने वाली इस बैठक में तीनों देशों के विदेश, रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख शामिल होंगे।

सात अगस्त को हुए मक्का संयुक्त रक्षा समझौते ने सुन्नी मुस्लिम देशों और अमेरिका के सहयोगियों को साथ ला खड़ा किया है। ये देश ईरान के साथ युद्ध और क्षेत्रीय संघर्ष को लेकर चिंतित हैं, जिसके कारण खाड़ी क्षेत्र के तेल निर्यातकों पर ईरानी मिसाइलें दागी गई हैं। इस समझौते का मकसद किसी भी तरह के हमले के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा को मजबूत करना है। इसमें यह प्रविधान है कि तीनों देशों में से किसी एक पर भी सशस्त्र हमला होने पर उसे सभी पर हमला माना जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे नाटो के आर्टिकल-5 में सामूहिक रक्षा का नियम है। सूत्र ने कहा, "बैठक के एजेंडे में अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे शामिल होंगे।" इसमें रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने, तीनों देशों की सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल और रक्षा उद्योग में सहयोग को गहरा करने (जिसमें संयुक्त उत्पादन और विकास भी शामिल है) पर चर्चा होने की उम्मीद है। तीनों देश इजरायल और ईरान के सैन्य रुख को लेकर चिंतित हैं, जबकि उनका पुराना सहयोगी अमेरिका क्षेत्रीय उथल-पुथल को रोकने के लिए संघर्ष कर रहा है।

मक्का समझौते के दौरान बात करते पाकिस्तान, सऊदी अरब व तुर्किये के शीर्ष नेता। फाइल

अपने असली दुश्मन को पहचानें और उनका मुकाबला करें : मोजतबा खामेनेई

- ईरान के सर्वोच्च नेता ने 'अमेरिकी-इजरायली नापाक चालों' के खिलाफ मुस्लिम देशों से की अपील

तेहरान, रायटर : ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैयद मोजतबा हुसैनी खामेनेई ने इस्लामिक उम्माह की तमाम मुश्किलों का एकमात्र हल आपसी एकता व भाईचारे को बताया है। इस्लामिक एकता सप्ताह के अवसर पर जारी संदेश में उन्होंने खाड़ी और पश्चिम एशिया के सभी मुस्लिम देशों के शासकों से आह्वान किया है कि वे अपने 'असली दुश्मन' को पहचानें और उसके खिलाफ एकजुट होकर खड़े हों।

खामेनेई ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म एक्स और टेलीग्राम पर सिलसिलेवार संदेशों में अमेरिका और इजरायल को इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन करार दिया है। कहा, अमेरिका और अवैध जायोनी शासन जानबूझकर नस्लीय, सांस्कृतिक व भौगोलिक भेदों का फायदा उठाकर मुसलमानों के बीच फूट डालने की साजिश रच रहे हैं। जो भी व्यक्ति, चाहे अनजाने में ही क्यों न हो, ऐसा कृत्य करता है जिससे मुसलमानों में वैमनस्य फैले, वह सीधे तौर पर दुश्मनों के एजेंडे को मजबूत कर रहा है। खामेनेई ने फलस्तीन के दर्द और खाड़ी देशों की सुरक्षा पर गहरी चिंता व्यक्त की। कहा, खाड़ी तट के राष्ट्रों और सरकारों को इस्लाम के झंडे तले अपनी एकता को मजबूत करना चाहिए, ताकि कोई भी बाहरी ताकत उनकी भूमि और संपत्ति पर बुरी नजर डालने का साहस न कर सके। उन्होंने कहा, "यदि मुस्लिम समुदाय एकजुट होता, तो फलस्तीन की जनता इस तरह असहाय होकर अत्याचारों का शिकार नहीं बनती। खाड़ी देशों के शासक हजारों किलोमीटर दूर बैठे विदेशी ताकतों की महत्वकांक्षाओं को समझें और आपसी मतभेद भुलाकर एक मंच पर आएं।"

मोजतबा खामेनेई।

कहा- इस्लामिक उम्माह की तमाम मुश्किलों का एकमात्र समाधान आपसी एकता और भाईचारा है

यह संदेश ऐसे समय में सामने आया है जब ईरान आर्थिक मोर्चे पर अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। हाल ही में अमेरिकी वित्त विभाग द्वारा ईरान के खिलाफ 'आपरेशन इकोनामिक आउटकास्ट' की घोषणा की गई है। जवाब में ईरान घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने और अमेरिकी डालर पर निर्भरता कम करने की रणनीति पर जोर दे रहा है। छह महीने पहले अमेरिका-इजरायली हवाई हमलों में घायल होने के बाद सार्वजनिक रूप से नजर न आने वाले खामेनेई का यह संदेश क्षेत्र में एक बड़े भू-राजनीतिक बदलाव और कूटनीतिक ध्रुवीकरण का संकेत देता है।

यूरोपीय संघ में शामिल होने से आइसलैंड ने किया इन्कार

- जनमत संग्रह में 52.8 प्रतिशत लोगों ने प्रस्ताव के विरोध में मतदान किया
- बहुमत ने कहा, हम अपने धंधे और संप्रभुता से समझौते को तैयार नहीं

रेजेविक, रायटर: यूरोपीय देश आइसलैंड की जनता ने यूरोपीय संघ (ईयू) में शामिल होने के सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। रविवार को इस प्रस्ताव पर हुए जनमत संग्रह में ईयू में शामिल होने के पक्ष में 47.2 प्रतिशत जबकि विरोध में 52.8 प्रतिशत मतदाताओं ने राय जाहिर की। चार लाख की आबादी वाले देश में दो लाख पैंसठ हजार मतदाता हैं जिनमें से 82.5 प्रतिशत ने जनमत संग्रह में हिस्सा लिया था। आइसलैंड अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य संगठन नाटो का सदस्य है लेकिन ईयू का सदस्य नहीं है।

आइसलैंड के लोगों के इस फैसले को सरकार व ईयू के लिए झटका माना जा रहा है। नजदीक स्थित ग्रीनलैंड पर कब्जे को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों से आइसलैंड की सुरक्षा के लिए भी चिंता पैदा हो गई है। ट्रंप अपने बयानों में कई बार आइसलैंड का भी जिक्र कर चुके हैं। ऐसे में सरकार का मानना था कि वह ईयू में शामिल होकर अपनी सुरक्षा चिंताएं कम कर सकती है। इसके लिए ही ईयू से वार्ता शुरू करने के लिए सरकार से जनता की राय मांगी थी, पर देशवासियों ने समुद्र में मछली पकड़ने के अधिकार, सस्ते रहन-सहन और संप्रभुता के साथ किसी तरह का समझौता न करने की इच्छा जता दी है। ज्ञात हो, ईयू के सदस्यों को तमाम सुविधाओं के साथ ही अपने संसाधनों की अन्य सदस्य देशों के साथ साझेदारी करनी होती है। आइसलैंड ने इससे पहले 2009 में भी ईयू में शामिल होने के लिए वार्ता शुरू की थी लेकिन आर्थिक संकट के बीच 2013 में इस वार्ता को रोक दिया गया था। ईयू में शामिल होने के प्रस्ताव के विरोधी विपक्ष के नेता गुडरन हैफ्सटीनडोटीर ने कहा है कि हमारी ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ईयू कर सकेगा। इसलिए उससे अलग रहना ही उचित है।

268 यात्रियों को ले जा रही फेरी पलटी, सात की मौत

निकोसिया, रायटर: उत्तरी साइप्रस के पास 268 लोगों को ले जा रही कैटामारन नामक फेरी पलट गई। दुर्घटना में सात लोगों की मौत हो गई। फेरी पर 260 यात्री और आठ क्रू मेंबर थे।

निजी स्वामित्व वाली यह फेरी दोपहर 12:30 बजे (स्थानीय समय) उत्तरी साइप्रस के कायरिनिया बंदरगाह से रवाना हुई। कुछ समय बाद ही फेरी में पानी भरने लगा। यह पूर्वी भूमध्य सागर में बंदरगाह तासुकु की ओर जा रही थी। जहाज से बचाए गए लोगों को कायरिनिया बंदरगाह ले जाया गया, जहां से अस्पताल भेजा गया। कायरिनिया के मेयर मूरत सेनकुल ने कहा, फेरी पर सवार 237 यात्रियों को बचा लिया गया है। 24 अन्य तलाश जारी है। वीडियो फुटेज में लाइफ जैकेट पहने लोगों को पलटी हुई फेरी के ऊपर बैठे या खड़े देखा जा सकता है। अधिकारी उन्हें किनारे तक लाने में मदद के लिए कोस्ट गार्ड और निजी जहाजों को भेज रहे थे।

स्विट्जरलैंड में रेव पार्टी में गोलीबारी, एक की मौत

स्विट्जरलैंड के आराऊ के पास रविवार को एक रेव इवेंट के दौरान हुई गोलीबारी के बाद शैचेन हार्स रेसिंग ट्रैक के पास गश्त करते हथियारबंद पुलिस अधिकारी। एपी

जिनेवा, रायटर : स्विट्जरलैंड के आराऊ शहर में एक रेव पार्टी में हुई गोलीबारी में 22 वर्षीय युवती की मौत हो गई और पांच अन्य घायल हो गए, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर हैं।

सभी पीड़ित स्विट्जरलैंड के निवासी हैं और 20-30 साल की उम्र के बीच के हैं। वहीं, इटली के विदेश मंत्रालय ने कहा, स्विस अधिकारियों ने उन्हें एक इतालवी महिला की मौत की जानकारी दी है। हमने जांच में मदद की पेशकश की है। पुलिस प्रवक्ता बर्नहार्ड ग्रासर ने कहा, हमलावर की तलाश जारी है और शहर के बड़े इलाकों की घेराबंदी कर दी गई है। कहा, हमारे पास इस हमले के पीछे कौन है, इस बारे में पक्की जानकारी नहीं है। हमें नहीं पता कि हमलावर एक है या कई लोग हैं, और वे गाड़ी से भाग रहे हैं या पैदल।" एक प्रत्यक्षदर्शी ने कहा, रविवार सुबह 2:30 बजे संगीत बंद होने के कुछ ही देर बाद उसने गोलियों की आवाज सुनी।

वाट्सएप पर चल रहा हवाला का नेटवर्क, यूरोप से लेकर सीरिया पहुंचा काला धन

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

डिजिटल दौर में बैंकिंग और आनलाइन पेमेंट पर निगरानी बढ़ी तो अपराधियों ने पैसे के लेन-देन के पुराने तरीके हवाला (भरोसे पर आधारित बिचौलियों का नेटवर्क) को भी डिजिटल बना लिया। यूरोपीय ब्राडकास्टर्स यूनियन (ईबीयू) की रिपोर्ट में ऐसे ही एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का खुलासा हुआ है, जो वाट्सएप के जरिए यूरोप से लेकर सीरिया तक नकदी का लेन-देन कर रहा था। 'ट्रेडर्स आफ ग्रेटर यूरोप' नाम के वाट्सएप ग्रुप में 532 सदस्य थे। इस नेटवर्क का इस्तेमाल मानव तस्करी व आतंकवाद से जुड़े वित्तीय लेन-देन में भी किया जा रहा था। बेल्जियम के अफसरों को 2022 में फरवरी से दिसंबर के बीच इस ग्रुप के 82 हजार से अधिक वाट्सएप संदेश मिले। संदेशों में अरबी भाषा में हवालादारों के बीच रकम पहुंचाने व लेने के निर्देश दिए जाते थे।

532 सदस्यों वाले ग्रुप में अरबी में तय होते थे लेन-देन, नोटों के सीरियल नंबर बनते थे पहचान

- मानव तस्करी से लेकर आइएस से जुड़े लोगों तक पैसे पहुंचाने में नेटवर्क के इस्तेमाल का खुलासा

प्रतीकात्मक।

नोटों की तस्वीर बनी लेन-देन की 'रसीद' : 2024 में नेटवर्क के प्रमुख 'अबू एडम' व उसके सहयोगी 'अबू अहमद' को पकड़ा गया। एडम के फोन से पांच यूरो के नोटों की 6,000 तस्वीरें मिलीं। नोटों के सीरियल नंबरों को लेन-देन के कोड की तरह प्रयोग किया गया था। लेन-देन सीरिया के डिटेंशन कैंपों में मौजूद आइएस से जुड़े लोगों के परिवारों तक पैसा पहुंचाने तक में किया गया।

कबाब रेस्टोरेंट के पीछे चल रहा था हवाला कारोबार

आस्ट्रिया में जांचकर्ताओं को हवाला नेटवर्क का एक और ठिकाना वियना के एक कबाब रेस्टोरेंट में मिला। रेस्टोरेंट चलाने वाले दो सीरियाई भाइयों पर मानव तस्करी से जुड़े मामले में कार्रवाई की गई। आस्ट्रियाई पुलिस और यूरोपोल से जुड़ी जानकारी के मुताबिक, एक अन्य आपराधिक नेटवर्क ने हवाला के जरिए बड़ी संख्या में प्रवासियों की यूरोप तक अवैध तस्करी में भुगतान हासिल किया। कुछ मामलों में तस्करों द्वारा लोगों की प्रताड़ना के वीडियो उनके परिवारों को भेजकर फिरौती मांगे जाने की बात भी सामने आई।

कीव में मृतक संख्या 38 हुई, लगातार चौथे दिन भी हमला

कीव, एपी : यूक्रेन की राजधानी कीव के निकट गोला-बारूद के गोदाम पर शुक्रवार देर रात हुए हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 38 हो गई है, चार लोग अभी भी लापता हैं। 2026 में किसी एक दिन में रूसी हमले में मरने वाले यूक्रेनी नागरिकों की यह सर्वाधिक संख्या है। कीव के नजदीक जिस मीला गांव पर रूस का हमला हुआ था वहां पर आग अभी नहीं बुझी है। बचाव और राहत दल वहां पर मृतकों के शवों और घायलों की तलाश के काम में लगे हुए हैं। शनिवार देर रात रूस ने लगातार चौथे दिन कीव पर ड्रोन से हमला किया। इस हमले में कई भवनों को नुकसान हुआ और तीन लोग घायल हुए हैं। जबकि यूक्रेन के ताजा ड्रोन हमले में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर के नजदीक स्थित किरिशी आयल रिफायनरी में आग लगने की सूचना है। इस बीच सैन्य संगठन नाटो ने कहा है कि यूक्रेन युद्ध में रूस को मजबूती से जवाब दे रहा है।

6 | संपादकीय
जनसत्ता | 31 अगस्त, 2026

त्रासदी के सबक

नेपाल और तिब्बत के सीमांत इलाकों में आई विनाशकारी बाढ़ के कारणों का विश्लेषण और नतीजों का आकलन अभी जारी रहेगा, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर इस जरूरत को रेखांकित किया है कि आशंकाओं की अनदेखी या उसके प्रति उदासीनता का परिणाम क्या हो सकता है। नेपाल का जो समूचा इलाका हिमनद टूटने की वजह से तबाह हो गया, जानमाल की व्यापक क्षति हुई, उसका आम लोग भले ही ठीक-ठीक अनुमान नहीं लगा सके होंगे, लेकिन सरकार की नजर स्थानीय उथल-पुथल के संकेतों पर रहनी चाहिए थी। साथ ही अन्य देशों में ऐसी स्थितियों के असर की आशंका हो, तो वहां की एजंसियों के साथ तालमेल से कुछ एहतियाती कदम उठाए जा सकते थे। खासतौर पर तब, जब नेपाल-तिब्बत के इस इलाके में बर्फ और चट्टानों वाला हिमस्खलन होने और उसकी वजह से बाढ़ आने की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। ऐसे में सावधानी बरतना एक नियमित तकाजा था। हालांकि यह सही है कि प्राकृतिक आपदाओं को रोकना संभव नहीं है, लेकिन अगर अचानक उपजने वाले खतरों को ध्यान में रख कर बचाव के पूर्व-इंतजाम किए जाएं, तो नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

जाहिर है, अब नेपाल को अगले कुछ समय तक के लिए तबाह हो गए इलाकों में बचे-खुचे को संभालने, लापता लोगों की खोज, पुनर्वास और पुनर्निर्माण को लेकर कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। बेशक वह अपने स्तर पर यह सब करने की कोशिश करेगा, लेकिन ऐसे समय में दूसरे देशों की सहायता भी काफी मायने रखती है। प्रभावित सभी इलाकों में हुए नुकसान का आकलन सामने आने के बाद पूरी तस्वीर साफ होगी, लेकिन फिलहाल नेपाल के वित्त मंत्री का कहना है कि इस प्रलयंकारी बाढ़ से हुई क्षति की भरपाई के लिए देश को चार-पांच अरब डालर की जरूरत होगी। यह समझा जा सकता है कि अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर पहले ही कई तरह के दबाव झेल रहे नेपाल के सामने अब इस त्रासदी की वजह से जो मुश्किल पैदा होगी, उससे निपटना उसके लिए एक बड़ी चुनौती होगी। इसके अलावा, इस बात का अध्ययन करने की जरूरत है कि व्यापक तबाही वाली इस बाढ़ की प्रकृति, रफ्तार और नुकसान पहुंचाने का दायरा इतना अलग क्यों था और इसकी वजहें क्या होंगी।

दरअसल, इस आपदा का जो स्वरूप सामने आया, उसे समझना न केवल नेपाल, बल्कि उससे सटे देशों के लिए भी इसलिए जरूरी है कि अगर इसका दायरा और बड़ा हुआ तो इसकी जद में खासतौर पर भारत के भी कई इलाके आएंगे। इसलिए अब भारत को न केवल तिब्बत, चीन और नेपाल में होने वाली प्राकृतिक उथल-पुथल को लेकर ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है, बल्कि अपनी सीमा में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्कम जैसे इलाकों में मौजूद हिमनद झीलों के खतरों के प्रति भी एहतियाती उपाय अभी से करने होंगे। हिमाचल प्रदेश में जलवायु परिवर्तन केंद्र के अध्ययन के मुताबिक, सतलुज नदी के क्षेत्र में हिमानी झीलों की संख्या 2019 के 562 से बढ़ कर 2023 में 1,048 हो गई। इन झीलों के विस्तार और इनसे संभावित खतरों को नजरअंदाज करना व्यापक नुकसान को न्योता देने की तरह होगा। अक्तूबर, 2023 में सिक्किम के दक्षिण ल्होनक झील के टूटने से जो तबाही हुई, वह एक उदाहरण है। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि नेपाल में इस विनाशकारी त्रासदी को एक सबक के तौर पर देखा जाए और उसी मुताबिक बचाव के लिए एहतियाती कदम उठाए जाएं।

नशे के विरुद्ध

देश में नशीले पदार्थों का बढ़ता अवैध कारोबार व्यक्ति, परिवार और समाज के लिए एक गंभीर समस्या बन चुका है। इससे न केवल स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं पैदा हो रही हैं, बल्कि घरेलू कलह, हिंसा और अन्य आपराधिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिल रहा है। खासकर युवा पीढ़ी इससे ज्यादा प्रभावित हो रही है और घरेलू स्तर पर इसकी मार महिलाओं और बच्चों को झेलनी पड़ती है। सरकार की ओर से नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने के दावे तो किए जाते हैं, लेकिन इन्हें धरातल पर उतारने की गंभीरता कम ही नजर आती है। ऐसी स्थिति में विभिन्न राज्यों में सामाजिक स्तर पर नशे के खिलाफ मुहिम चलाने के प्रयास होते रहे हैं। इसी क्रम में अब उत्तराखंड में देहरादून के थानी गांव में महिलाओं ने नशे के विरुद्ध मोर्चा संभाला है। ये महिलाएं शाम होते ही गांव की गलियों में निकल आती हैं और हर आने-जाने वाले पर नजर रखती हैं। इनका मकसद गांव को मादक पदार्थों के सेवन और कारोबार से दूर रखना है। महिलाओं का यह साहस और प्रतिबद्धता निश्चित तौर पर एक स्थायी बदलाव की दिशा में सराहनीय प्रयास है, लेकिन इससे सरकारी तंत्र की व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े होते हैं।

गौरतलब है कि देश में नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार का जाल अब ग्रामीण इलाकों तक पहुंच गया है। स्कूल-कालेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थी और बेरोजगार युवा मादक पदार्थों के तस्करों का आसान निशाना बन रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि सामाजिक स्तर पर भी नशे के खिलाफ व्यापक मुहिम चले। हालांकि, देहरादून के गांव में महिलाओं ने जो बीड़ा उठाया है, वह आसान नहीं है। दिनभर घर के कामकाज में व्यस्त रहना और रात को गांव की गलियों में पहरा देना दूसरे लोगों के लिए भी प्रेरणादायक है। इस तरह की मुहिम इसलिए भी महत्त्वपूर्ण है कि अगर सरकार किसी राज्य या जिले में मादक पदार्थों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाती है, तो मादक पदार्थों के सेवन और कारोबार से जुड़े लोग वैध-अवैध वैकल्पिक रास्ता तलाश लेते हैं। मगर, जब सामाजिक स्तर पर बदलाव का प्रयास किया जाए, तो उसके परिणाम समस्या के स्थायी समाधान के रूप में सामने आ सकते हैं। हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि संबंधित सरकारी महकमे या सुरक्षा एजंसियों की जिम्मेदारी कम हो जाती है।

कल्पमेधा

असफल होने पर आपको निराशा का सामना करना पड़ सकता है।
मगर प्रयास छोड़ देने पर आपकी असफलता निश्चित है।
- ब्रेवेरली सिल्स

उच्च शिक्षण संस्थानों की साख पर सवाल

किसी भी उच्च शिक्षण संस्थान की साख में गिरावट पूरी मानवता के लिए स्वाभाविक चिंता का विषय होना चाहिए। दुनिया के श्रेष्ठतम विश्वविद्यालय में नस्लीय भेदभाव के आरोप बेहद गंभीर हैं।

प्रदीप कुमार राय

दुनिया के किसी भी उच्च शिक्षण संस्थान की साख में गिरावट पूरी मानवता के लिए स्वाभाविक चिंता का विषय होना चाहिए, क्योंकि यहां की चारदीवारी में न केवल तरक्की की इबारत लिखी जाती है, बल्कि 'व्यक्ति से व्यक्तित्व' का निर्माण भी होता है। सवाल जब उस देश से जुड़ा हो, जो उच्च कोटि के विश्वविद्यालयों का घर (इंग्लैंड) है और उसमें में भी वहां के श्रेष्ठतम विश्वविद्यालय आशंका के घेरे में हों, तो चिंता और भी गहरी हो जाती है। भरोसे की दीवार एक बार ढह जाए, तो उसे दोबारा बनाना आसान नहीं होता। दरअसल, न्यूटन, डार्विन और स्टीफन हाकिंग जैसी विलक्षण प्रतिभाओं को पल्लवित करने वाले इंग्लैंड के वर्ष 1209 में स्थापित कैंब्रिज विश्वविद्यालय और यहां के लीवर पूल जान मूर्स नाम के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के भरोसे की दीवार बुरी तरह दरकी है। इन विश्वविद्यालयों की दुनिया में एक अलग पहचान है, मगर ये आज भी नस्लीय भेदभाव से अछूते नहीं हैं।

कैंब्रिज विश्वविद्यालय ने वर्ष 2022 में एक अश्वेत शिक्षाविद डा जेसन अर्डे को 37 बरस की उम्र में अपने यहां 'शिक्षा और समाजशास्त्र' विषय में प्रोफेसर नियुक्त किया था। विश्वविद्यालय को इस नियुक्ति के लिए खासी सराहना मिली, मगर यह चार बरस की चांदनी ही साबित हुई। जुलाई, 2026 में कुछ लोगों ने प्रोफेसर जेसन पर नकल करके पीएचडी करने के आरोप लगा दिए। इसके बाद पीएचडी की उपाधि देने वाले विश्वविद्यालय के स्पष्टीकरण पर यह मामला थोड़ा शांत हुआ, पर विवाद का जिन्न फिर जाग गया। कैंब्रिज विश्वविद्यालय के कुछ अधिकारियों ने ही प्रोफेसर जेसन की नियुक्ति के मानदंडों पर पर सवाल खड़े कर दिए। मीडिया में भी इस पर चर्चा हुई और विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से भी इस मामले पर असंवदेनशीलता दिखाई गई, जबकि आरोप सिद्ध नहीं हुए थे। वहीं, आरोपों से व्यथित होकर प्रोफेसर जेसन ने सही से अपना पक्ष रखे बिना ही बीते पांच अगस्त को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। विश्वविद्यालय ने भी उन्हें जांच पूरी होने तक अपने पद पर बने रहने के लिए नहीं कहा।

प्रोफेसर जेसन इस प्रकरण से बहुत आहत हुए और चौदह अगस्त को अचानक उनका निधन हो गया। जांच एजंसियों ने इसे प्राकृतिक मौत माना, पर इसके लिए अप्राकृतिक कारण जिन्होंने पैदा किए, उस पर पूरा व्यवस्था तंत्र मौन है। प्रोफेसर जेसन की पीएचडी को अपनी शिकायत से विवादों में लाने वाले श्वेत अनुसंधानकर्ता नाथन काफनास को उनके अपने ही बैल्जियम स्थित गेंट विश्वविद्यालय ने नस्लीय भेदभाव के आरोप में निलंबित कर दिया है। उल्लेखनीय है कि नाथन अपने अध्ययनों के जरिए यह दावा भी कर चुके हैं कि कैसे श्वेत और अश्वेत व्यक्ति की योग्यता आनुवांशिक आधार पर तय की जाती है। कैंब्रिज में ह्यूनवर्सिटी एंड कालेजह्ल यूनियन के महासचिव जो ग्रेडी का कहना है कि प्रोफेसर जेसन को जिस तरह का उत्पीड़न झेलना पड़ा, उससे घृणित कुछ भी नहीं हो सकता। उन्होंने इसकी गहराई से जांच करने की मांग की है।

गौरतलब है कि प्रोफेसर जेसन की मौत के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री से लेकर दुनिया भर के शिक्षक समुदाय तथा अन्य क्षेत्रों के विशेषज्ञों की तरफ से जो सवाल उठाए गए, उसने कैंब्रिज विश्वविद्यालय की साख को

गहरी चोट पहुंचाई। प्रधानमंत्री एंडी बर्नहेम ने कहा कि प्रोफेसर जेसन की मौत कई स्तरों वाली त्रासदी है। उनके इस सारगर्भित वाक्य को कुछ ऐसे समझा जा सकता है- इस मामले में बहुरूपी त्रासदी बड़े विश्वविद्यालयों की उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और उपाधि की पूरी गांरटी देने की विफलता में नजर आती

> **इसमें कोई संदेह नहीं कि कैंब्रिज विश्वविद्यालय ने शोध, पठन-पाठन और प्राध्यापकों की नियुक्ति के उच्च आदर्श स्थापित किए हैं। मगर सैकड़ों वर्षों की इस सशक्त विरासत का अर्थ पारदर्शिता से मुंह मोड़ना नहीं हो सकता। प्रोफेसर जेसन अर्डे के मामले में कैंब्रिज को अपनी चूक भी जगजाहिर करनी चाहिए। वे दोषी थे या नहीं, इसकी गहन जांच होनी चाहिए। संस्थान को जवाब तो देना होगा। अगर यह पीएचडी की उपाधि के बजाय नस्लीय भेदभाव का मामला है, तो भी उसकी तह में जाना होगा। इस मामले की जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई से न्याय सुनिश्चित हो पाएगा। विश्वविद्यालयों की वैश्विक रैंकिंग में दूसरे देशों के संस्थानों की व्यवस्था में खोट निकालने वालों को अपनी नैतिक रैंकिंग का हिसाब भी देना चाहिए।**

है, यह त्रासदी कैंब्रिज विश्वविद्यालय जैसे शीर्ष संस्थान की संवेदनहीनता भी दिखाती है। इसके अलावा यह त्रासदी एक बड़े विश्वविद्यालय के नियुक्ति के उच्च मानदंडों पर भी सवाल खड़ा करती है।

इस घटना का ताल्लुक केवल दो विश्वविद्यालयों की दीवारों के भीतर समाप्त नहीं होता, बल्कि यह पूरी दुनिया को खुद से जोड़ता है। सवाल यह है कि प्रोफेसर जेसन को पीएचडी की उपाधि प्रदान करने वाले लीवर पूल जान मूर्स विश्वविद्यालय ने अपना पक्ष रखते हुए पीएचडी में साहित्य चोरी के आरोपों से तो साफ इनकार कर दिया था, मगर जब शिकायतकर्ताओं ने आरोप को दूसरे परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया, तो संबंधित विश्वविद्यालय ने इसका पुरजोर तरीके से विरोध क्यों नहीं किया? प्रोफेसर जेसन की पीएचडी में गड़बड़ी के आरोपों को उछालने वाले कैंब्रिज के शोधार्थी नाथन काफनास ने दावा किया था कि जेसन ने अपने शोधपत्र में कई पैरा कहीं दूसरी जगह बिना संपादन के चस्पा कर दिए।

सवाल यह भी है कि नाथन के दावे के समांतर प्रोफेसर जेसन को पीएचडी की उपाधि देने वाले विश्वविद्यालय ने शोधपत्र जमा कराने के वक्त खुद की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की। पूरी दुनिया को साहित्य चोरी जांचने के महंगे साफ्टवेयर बेचने वाले पश्चिमी देशों को क्या खुद इनकी विश्वसनीयता पर कोई संदेह है? दूसरा, अगर मामला साफ्टवेयर की विफलता का नहीं है, तो फिर उन्हें बताना चाहिए कि आखिर परदादारी किस बात की है? शिकायतकर्ता नाथन को तो खुद ही नस्लीय भेदभाव के आरोप में उनके विश्वविद्यालय ने निलंबित कर दिया है, तो अब उनके साहित्य चोरी के आरोप भी गहरी जांच का विषय हैं। देखना होगा कि कहीं यह मामला सुविधा के अनुसार मानदंड बदलने के पूर्वाग्रह का तो नहीं है।

सवाल यह भी उठ रहा है कि कैंब्रिज विश्वविद्यालय इस प्रकरण में बार-बार अपने रंग क्यों बदलता रहा? पहले प्रोफेसर जेसन की नियुक्ति पर जमकर वाहवाही लूटी गई। फिर उनकी पीएचडी को लेकर लगे आरोपों के साबित हुए बिना ही पूरी दुनिया में उनकी छवि को धूमिल होने दिया गया। शायद वह भूल गया कि जब लोग पूछेंगे कि क्या कैंब्रिज जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में भी नियुक्तियों में अनियमितताएं होती हैं, तो उसके पास क्या जवाब होगा। हालांकि, शिक्षाविदों का कहना है कि यह सब इतना आसान नहीं है कि इतनी बड़ी त्रासदी को कैंब्रिज प्रशासन चटाई के नीचे छिपाकर बैठ जाएगा। विश्वविद्यालय की कुलपति ने इस घटना पर खेद जताकर भले ही मानवीय दृष्टिकोण रखा, लेकिन इसे न्याय की दृष्टि से कभी नहीं देखा जाएगा। इस मामले की जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई से न्याय सुनिश्चित हो पाएगा।

एक ब्रिटिश राजनेता का कहना है- 'कुछ विश्वविद्यालयों ने प्रोफेसर जेसन को अपना पोस्टर ब्वाय बनाने के लिए उनकी कम उम्र और अश्वेत होने को ही नियुक्ति का आधार बना लिया'। फिर इस मामले में नस्लीय भेदभाव के आरोप तो और भी कई लोग लगा रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि कैंब्रिज ने शोध, पठन-पाठन और प्राध्यापकों की नियुक्ति के उच्च आदर्श स्थापित किए हैं। मगर सैकड़ों वर्षों की इस सशक्त विरासत का अर्थ पारदर्शिता से मुंह मोड़ना नहीं हो सकता। संस्थान को जवाब तो देना होगा। इस मामले में कैंब्रिज को अपनी चूक भी जगजाहिर करनी चाहिए। प्रोफेसर जेसन दोषी थे या नहीं, इसकी भी गहन जांच होनी चाहिए। अगर यह पीएचडी की उपाधि के बजाय नस्लीय भेदभाव का मामला है, तो भी उसकी तह में जाना होगा। विश्वविद्यालयों की वैश्विक रैंकिंग में दूसरे देशों के संस्थानों की व्यवस्था में खोट निकालने वालों को अपनी नैतिक रैंकिंग का हिसाब भी देना चाहिए।

सौहार्द की जगह

सुनील चमड़िया

आजादी ने बंटवारे का दर्द झेला और सांप्रदायिक तनाव का भी सामना किया। पर तब भी ऐसे तमाम लोग थे, जिन्होंने अपने इंसानी उसूल को नहीं भुलाया। मिलजुलकर रहने और एक समाज बनाने का उसूल, जिसने बहुतों को राह दिखाई। लोग तनाव भूलते जा रहे थे। जख्म भरते चले गए। सत्तर के दशक में एक ऐसी भी पीढ़ी थी, जिसे महसूस ही नहीं हुआ कि उनके मोहल्ले या शहर में किसी तरह का कोई तनाव है। किसी परिवार के घर के कपड़े की सिलाई कोई मुसलमान दर्जी करता था, तो घर की महिलाओं के कपड़ों की सिलाई पड़ोसन तारा कर देती थी। बच्चे पांच पैसे के पांच लेमनचूस और साथ में 'घलुआ' यानी एक मुफ्त लेमनचूस भी मांगते हुए यह सोचते तक नहीं थे कि दुकानदार मुसलिम है या नहीं।

उस पीढ़ी के बच्चों के रिश्ते ऐसे ही बन रहे थे। गांव में लगने वाले बाजार में जो सब्जी होती थी, उसे उगाने वाले हिंदू होते थे, तो उनसे खरीद कर बेचने वाले ज्यादातर मुसलिम। धूमधाम से होने वाली दुर्गा पूजा या सरस्वती पूजा में पूरे मोहल्ले के हिंदू, मुसलिम, सिख के अलावा निचली कही जाने वाली जातियों तक की बराबर की भागीदारी होती थी। मोहर्रम में कोई बच्चा बिना किसी आग्रह के खुश होकर ताजिए के नीचे चलता था। रात भर विभिन्न गांव से आए हुए मोतियों में पिरोए ताजिए का लोग इंतजार करते थे। उसकी तैयारी में हिंदू भी बराबर शामिल होते थे। देखरेख की औपचारिकता के लिए सरकारी अधिकारियों का जमावड़ा भले होता था, लेकिन जब ताजिया निकलता था, तब कहीं कोई तनाव नहीं होता था। तब कुछ उदाहरणों के बावजूद लोगों के बीच विभाजित करने वाली सोच नहीं थी। शहरों में बर्तन की दुकान से सभी धर्म और जातियों के लोग बर्तन खरीदते थे। सिलाई मशीन बेचने वाले हिंदू थे, तो उसे खरीदने वाले अधिकतर कारीगर मुसलिम थे।

मंदिर के बगल में मसजिद भी होती थी, तो कोई तनाव नहीं दिखता था। होली में रंग लगाने से पहले यह नहीं पूछा जाता था कि तुम हिंदू हो या मुसलमान। रंग लगाने के लिए हिंदू युवक अपने मोहल्ले के मुसलिम दोस्त के घर आसानी से जाते थे। रंग लगाने और होली खेलने में दोनों के बीच जो प्यार और सौहार्द दिखता था, वह अब दुर्लभ है। इसी तरह, ईद-बकरीद में भी वही प्यार जीवन पाता था। हर त्योहार धूमधाम और उत्सव के साथ मनाया जाता था। हिंदू बच्चे मुसलिम बुजुर्गों को, तो मुसलिम बच्चे हिंदू बुजुर्गों को नाना, मामा, नानी, मौसा, मामी कह कर संबोधित करते। ईद के समय ये तमाम रिश्ते विभिन्न किस्म के पकवान के साथ ईदी में मिलते, तो सद्भावना और प्यार का रंग थोड़ा और गाढ़ा हो जाता। वहीं दुर्गा पूजा के दौरान इंसानियत के रंगों से सजे हुए बाजार में क्या हिंदू, क्या मुसलमान- सभी बराबर प्यार और सौहार्द के भागीदार होते थे।

तब रास्ते बंटे हुए नहीं थे। हर रास्ता हर किसी के लिए था। मूर्तियों के विसर्जन के दौरान शायद ही कहीं से विवाद की खबर आती थी। इसी तरह ताजियों के लिए किसी रास्ते में अड़चन नहीं थी। कोई समूह जिधर से चाहता था, उधर से विसर्जन के लिए मूर्ति ले जाता था। इन यात्राओं में हिंदू-मुसलमान, सब बराबर और दिल से शामिल होते थे। आज भी बहुत सारे लोग शायद इस बात पर गौर कर पाते होंगे कि दीपावली की धूमधाम में पटाखे, फुलझड़ियां मुख्य रूप से मुसलिम समुदाय के लोगों द्वारा ही बनाई जाती थीं। उस दौर में पटाखे लेते हुए कौन सोचता था कि पटाखे बेचने वाले लोग किस धर्म से जुड़े हुए हैं!

किसी की मां बीमार हुई, तो देखने वाले डाक्टर की पहचान हिंदू की थी, या मुसलमान की, यह कौन देखता था। तब किसी के दिमाग में इनकी पहचान कराने की बात नहीं आती थी। किसी डाक्टर की धार्मिक पहचान से किसी मरीज को डर नहीं लगता था और न ही डाक्टरों के भीतर अपने मरीजों की पहचान को लेकर कोई आग्रह था। बल्कि हालत तो यह थी कि किसी को यह जानने की जरूरत भी नहीं थी कि कौन डाक्टर और कौन मरीज किस धार्मिक पहचान के साथ जीता है। मगर जब दंगों के बीज रोपे गए और उनकी जड़ें फैलने लगीं, तो उसके बाद किसी को मुसलमान बना दिया गया, तो कोई हिंदू पहचान के साथ मुखर होने लगा। जिनका जीना-मरना एक साथ था, उनके दो पक्ष बना दिए गए। एक पक्ष खुद को दूसरे से असुरक्षित महसूस करने लगा और लोगों के घर अपनी धार्मिक पहचान के दायरे में सिमटने लगे।

दुनिया मेरे आगे

> **राजनीतिक लाभ के लिए धर्म पूछ कर सामान खरीदने की नई मानसिक बीमारी पैदा हो चुकी है। अब बच्चे कहां से लेमनचूस खरीदें? सियासी जहर से अब बचपन भी पीड़ित होने लगा है। इस बचपन से क्या बनेगा? इस सवाल के जवाब में सब बहाना बनाने लगते हैं। हम एक इंसान के रूप में वक्त के पन्नों पर अपनी शिकायत दर्ज करवा रहे हैं।**

जाहिर है, समय ने करवट बदल ली और सियासी साजिशों ने पूरे माहौल को बदल डाला। मुसलिम और हिंदू की अलग-अलग पहचान होने लगी। पहले दोनों के त्योहार एक दूसरे के साथ मनाए जाते थे, अब वही त्योहार सांप्रदायिक तनाव और पुलिस भारी भारी सुरक्षा के बीच मनाए जाने लगे। दंगों ने नेता पैदा करना शुरू किया। आजादी ने उसूलों वाले नेता बनाए थे। सांप्रदायिक माहौल से नेता बनना आसान लगने लगा। नेता जवाबदेही से आजाद होना चाहते थे। दंगे ने उन्हें वह आजादी दे दी। कोई जानने की कोशिश क्यों नहीं करता कि खासकर कोरोना महामारी के दौर में मानसिक रोगियों की संख्या तेजी से क्यों बढ़ी, जबकि हमने सुना और पढ़ा है कि अतीत में हम प्लेग को हरा चुके थे। राजनीतिक लाभ के लिए धर्म पूछ कर सामान खरीदने की नई मानसिक बीमारी पैदा हो चुकी है। अब बच्चे कहां से लेमनचूस खरीदें? सियासी जहर से अब बचपन भी पीड़ित होने लगा है, तो इस बचपन से क्या बनेगा? इन सवालों का जवाब पूछिए, तो सब बहाना बनाने लगते हैं। हम एक इंसान के रूप में वक्त के पन्नों पर अपनी शिकायत दर्ज करवा रहे हैं।

वादों के बरक्स

उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाला है। इसी के दृष्टिगत यहां मुफ्त की योजनाओं और चुनावी वादों का बाजार भी गर्म होता दिखा रहा है। हालांकि राजनीति में कल्याणकारी योजनाएं कोई नई बात नहीं हैं। इसी क्रम में योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी महिलाओं के लिए 50 हजार स्कूटी देने, बुजुर्ग महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, रसोइयों के मानदेय में वृद्धि और युवाओं को 25 लाख टैबलेट उपलब्ध कराने जैसी घोषणाएं की हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या केवल मुफ्त की योजनाओं के माध्यम से ही सरकार बनाई जा सकती है? यदि ऐसा है तो यह तात्कालिक लाभ दीर्घकालिक योजनाओं को भारी नुकसान पहुंचता है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में यह कहना जरूरी है कि यहां महिलाओं में खून की कमी और कुपोषण की समस्या है, महिलाओं को नौकरी की दरकार है और उनकी सुरक्षा महत्त्वपूर्ण विषय है। इन सब मसलों पर सरकार को ज्यादा गंभीरता से विचार करना चाहिए, न कि मुफ्त की योजनाओं पर। मुफ्त की योजनाओं से वोट तो मिल सकता है, लेकिन राज्य की उन्नति नहीं हो सकती।

- वीरेंद्र कुमार जाटव, दिल्ली

खर्चीला उपचार

निजी अस्पतालों में इलाज का बढ़ता खर्च आम परिवारों के लिए चिंता बन गया है। हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर संसदीय स्थायी समिति की 176वीं रिपोर्ट (7 अगस्त 2026) में यह स्पष्ट हुआ है कि निजी अस्पतालों में औसतन भर्ती खर्च 50,508 रुपए है, जबकि सरकारी अस्पतालों में यह मात्र 6,631 रुपए है। प्रसव के मामले में भी निजी क्षेत्रों में जेब से होने वाला खर्च 37,630 रुपए है, जो सरकारी क्षेत्रों (2,299 रुपए) की तुलना में कई गुना अधिक है। स्वास्थ्य सेवा एक बड़ी पूंजी का क्षेत्र है, जिसमें भूमि, आधुनिक उपकरण, आपातकालीन व्यवस्था और विशेषज्ञ चिकित्सकों पर भारी लागत आती है। भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र की वास्तविक प्रगति इस बात से नहीं मापी जाएगी कि कितना पूंजी निवेश हुआ या चिकित्सा पर्यटन कितना बढ़ा, बल्कि इस बात से तय होगी कि देश का आम नागरिक बिना किसी आर्थिक डर के सही समय पर उचित इलाज प्राप्त कर पा रहा है या नहीं।

- प्रसिद्ध यादव, फुलवारी, पटना

परीक्षा सुरक्षा तंत्र

पिछले दिनों सार्वजनिक परीक्षाओं में सुधार के लिए एचपीटीएफ द्वारा सुझाव मांगे गए थे। इस संदर्भ में भारत को अंतरराष्ट्रीय परीक्षा संस्थाओं की तर्ज पर पूर्ण सावधानी से परिणाम-जांच तक एक परीक्षा सुरक्षा तंत्र बनाना चाहिए। प्रश्नपत्र तैयार करने से लेकर परीक्षा केंद्र पहुंचने तक उसकी गोपनीयता अधिकृत लोगों तक सुरक्षित रखी जाए। हर स्तर पर यह दर्ज हो कि प्रश्नपत्र किसके पास और कब पहुंचा। प्रश्नपत्रों को सुरक्षित तरीके से रखा जाए तथा उनके परिवहन पर कड़ी निगरानी हो। जहां संभव हो, परीक्षा से ठीक पहले सुरक्षित प्रश्न भंडार से अलग-अलग प्रश्नपत्र तैयार किए जाएं, ताकि पहले से प्रश्नपत्र लीक होने की संभावना न्यूनतम हो। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर विशेष रूप से प्रशिक्षित, प्रमाणित और स्वतंत्र परीक्षा-सुरक्षा दल तैनात हो, जिसका नियमित पुनः प्रशिक्षण तथा औचक निरीक्षण हो।

- बृजभूषण गोयल, लुधियाना

ठगी का जाल

हाल ही में 'डिजिटल अरेस्ट' के नाम पर एक बुजुर्ग दंपति को 97 दिनों तक भय और दबाव में रखकर 22 लाख रुपए ठग लिए गए। चिंताजनक यह है कि उनके उच्च शिक्षित युवा बेटे-बेटी भी इस ठगी के तरीके को पहचान नहीं सके। उन्होंने माता-पिता को सलाह दी कि वे ईडी का सहयोग करें, मांगी गई राशि जमा कर दें और बाद में कानूनी लड़ाई लड़ लेंगे। यह घटना केवल साइबर अपराधियों की चालाकी नहीं, बल्कि हमारी जागरूकता में कमी को भी दर्शाती है। शासन और पुलिस द्वारा लगातार समाचारों, विज्ञापनों और अन्य माध्यमों से डिजिटल अरेस्ट के प्रति लोगों को सतर्क किया जाता है। इस दरमियान बताया जाता है कि कोई भी सरकारी एजंसी फोन या वीडियो काल पर किसी व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट नहीं करती और न ही धन जमा कराने को कहती है। फिर भी शिक्षित लोग भी इस जाल में फंस रहे हैं।

- अरविंद जैन 'बीमा', फ्रीगंज, उज्जैन

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

लोकमानस

loksatta@expressindia.com

सवलत वेळेची, आवाजाच्या मर्यादेची नाही

सीओईपी तंत्रशास्त्र विद्यापीठाचे विद्यार्थी गेली २५ वर्षे विसर्जन मिरवणुकीतील ध्वनिपातळीची नोंद ठेवत आहेत. गेल्या वर्षीच्या मिरवणुकीत अनेक ठिकाणी ही नोंद शंभर डेसिबलच्या पुढे गेली. ध्वनिप्रदूषण (नियमन व नियंत्रण) नियम, २००० नुसार निवासी विभागातील दिवसाची मर्यादा ५५ डेसिबल आहे. डेसिबल हे प्रमाण लॉगरिदमिक असल्याने हा फरक किरकोळ नाही; शंभर डेसिबलची ध्वनिऊर्जा ५५ डेसिबलच्या सुमारे ३० हजार पट असते. असे बारकावे सामान्यांच्या लक्षात येत नाही आणि तज्ज्ञांची मुस्कटदाबी करायची कला समाजाने केव्हाच विकसित केलेली आहे. उत्सवाच्या दिवसांसाठी जी सवलत दिली जाते, ती वेळेची आहे; आवाजाच्या मर्यादेची नाही. ध्वनिक्षेपकाचा वापर हा कोणत्याही धर्माचा अनिवार्य भाग नाही, हे मुंबई उच्च न्यायालयाने डॉ. महेश बेडेकर विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य (२०१६) या निकालात स्पष्ट केले आहे. जानेवारी २०२५ च्या निकालातही न्यायालयाने नोंदवले, की ध्वनिक्षेपकाचा वापर हा अनुच्छेद २५ अथवा १९(१)(अ) खालील हक्क नाही. हे निकष कोणत्याही एका धर्मापुरते नाहीत; मशीद, चर्च आणि मंदिर या सर्वांना तेच नियम सारखे लागू होतात. आमचा आक्षेप डेसिबलवर आहे.

या आवाजाची किंमत नास्तिक तर चुकवतातच. पण मिरवणुकीत तासन्तास उभे राहणारे तरुण कार्यकर्ते, मार्गावरील रुग्णालयांतील रुग्ण, परीक्षेच्या तोंडावरची मुले आणि घरातील वृद्ध हेही चुकवत असतात, हे सगळे आपल्याच समाजातले घटक असतात. आणि गंमत म्हणजे डीजेची सवलत या सर्वांच्याच नावावर मागितली जाते, तेही त्यांना विश्वासात न घेता, नास्तिक तर लांबच राहिले. मुळात ज्यांना ज्यांना आवाजाचा परिणाम जाणवेल त्या त्या सर्वांना विश्वासात न घेणे ही एकप्रकारची मनमानी, बळजबरीच नाही का?

यावर बोलून वाईटपणा घ्यावा असे माझे मत आहे, कारण हे चित्र नवे नाही. जादूटोणाविरोधी कायद्याने ज्यांना संरक्षण मिळाले ते नास्तिक नव्हते; भोंदूगिरी आणि फसवणुकीला बळी पडलेली सामान्य धार्मिक कुटुंबेच होती. तो अध्यादेश डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येनंतर अवघ्या काही दिवसांत निघाला. आगरकरांची हयातीत प्रेतयात्रा काढली गेली. ज्यांना त्या काळात धर्मद्रोही ठरवले गेले, त्यांनीच आज सर्वांना उपलब्ध असलेली संरक्षणे मिळवून दिली.

म्हणूनच प्रशासनाने दबावापुढे झुकू नये. मंडळांच्या मागे संघटित यंत्रणा आहे; ज्यांचे कान, झोप आणि आरोग्य पणाला लागते त्यांच्यामागे ती नाही. कायद्याची अंमलबजावणी हेच त्यांचे एकमेव संरक्षण आहे.

■ **मयूर कुळकर्णी**, कोअर कमिटी मेम्बर, ब्राइट्स सोसायटी, पुणे

विरोध उपद्रवकारक साजरीकरणाला

'**अमर्याद 'आव्वाज**'' हे संपादकीय (२९ ऑगस्ट) वाचले. सण उन्मादानेच साजरे करायचे ही विकृती अंगात इतकी भिनली आहे की, वृद्ध नागरिक, रुग्ण, विद्यार्थी, नवजात बालके यांना कर्कश ध्वनिप्रदूषणाने होणाऱ्या त्रासाबाबत आमच्या संवेदना पार बोथट झाल्या आहेत. विद्यानंद बापट यांच्या मतांचा तर्कशुद्ध, प्रभावी प्रतिवाद करण्याची क्षमता नाही, या संबंधितांच्या हतबलतेतून (नेहमीप्रमाणेच) मनगटशाहीचा वापर करून बापट यांचा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. वास्तविक सण साजरा करण्यास कुणाचाच विरोध नसतो. (अगदी नास्तिकांचा वा हिंदुत्ववादी राजकारण विरोधकांचाही नसतो.) विरोध असतो तो, त्याच्या अत्यंत उपद्रवकारक साजरीकरणाला. पण हे वास्तव सोयीस्करपणे नजरेआड करून 'फक्त हिंदूंच्या सणांना विरोध का ?' असा दिशाभूल करणारा कांगावा केला जातो. आणि तो केला की, अन्य कुठल्याही तर्कशुद्ध युक्तिवादाची गरज न भासणारा समाज अलीकडच काळात आकारास आला आहे. सर्वपक्षीय स्थानिक नेत्यांचा भक्कम पाठिंबा आणि प्रोत्साहन हे यामागचे प्रमुख कारण आहे. यामुळे सारी प्रशासन व्यवस्था हतबल ठरते. वास्तविक 'नेता' या शब्दाचा अर्थ विधायक व विवेकी मार्गाने चालण्यासाठी जो समाजाला आपल्या पाठीमागे यायला लावतो तो ! पण अलीकडचा काळात जो स्वतः 'गर्दी' च्या पाठीमागे फरफटत जातो तोच नेता, असे समीकरण बनले आहे. ते जोपर्यंत बदलत नाही तो पर्यंत 'अमर्याद आव्वाजा'चे प्राबल्य राहणार असे दिसते.

■ **अनिल मुसळे**, ठाणे (पश्चिम)

दणदणाटाशिवाय उत्सवच नाही?

'**अमर्याद 'आव्वाज**'' हे संपादकीय वाचले. गणेशोत्सवातील ध्वनिवर्धक आणि नंतर ढोल - ताशे यांच्या कर्कश आवाजाला विरोध करणारे पुण्याच्या नारायण पेठेतील रहिवासी विद्यानंद बापट सध्या समाज माध्यमातून चर्चेत आले आहेत. दणदणाटी उत्सवांतील ध्वनिप्रदूषणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश देऊन देखील डी. जे., डॉल्बीचा दणदणाटाची कमाल पातळी ओलांडल्याविना उत्सव साजराच होत नाही. न्यायालयीन आदेशाची यंत्रणेकडून काय आणि कशी अंमलबजावणी होते हे सर्वश्रुत आहे. गतवर्षीच्या गणेश विसर्जन मिरवणुकीत मुंबईत १२०.२, तर पुण्यात १०५ डेसिबलपर्यंतच्या दणदणाटाची नोंद झाली आहे. संशोधनानुसार ७९ डेसिबलपर्यंतचा आवाज मानवी कानासाठी सामान्य आहे. तर भारताच्या केंद्रीय प्रदूषण मंडळाने त्याची मर्यादा ६५ डेसिबल इतकी निश्चित केली आहे. आजच्या आधुनिक - उत्सवांबाबत काही आक्षेप नोंदवले की रूढीं, परंपरा, धार्मिक अस्मितांचे मुद्दे अकारण प्रतिष्ठेचे करून तोंडे बंद केली जातात. वास्तविक सण, समारंभ, उत्सव साजरे करताना त्यांचा इतरांना त्रास होणार नाही याची काळजी सर्वांनीच घ्यायला हवी.

■ **बाळकृष्ण शिंदे**, बिबवेवाडी, पुणे

निर्बंधमुक्त म्हणजे दणदणाट नाही

'**अमर्याद 'आव्वाज**'' हा अग्रलेख (२९ ऑगस्ट) वाचला. पुण्यातील नारायण पेठेतील रहिवासी विद्यानंद बापट यांच्या प्रातिनिधिक तक्रारीला डी. जे. च्या आवाजातच (!) गणेशोत्सव मंडळांच्या आणि सरकारच्या कानी पोहोचवण्याची वेळ आली आहे. ध्वनिप्रदूषणाने त्रस्त झालेल्या नागरिकांनी बापटांना साथ दिली, तर कदाचित या ध्वनिप्रदूषणाला आळा बसेल; अन्यथा नाही. निर्बंधमुक्त उत्सव म्हणजे नागरिकांना बहिरे करण्याचा परवाना नव्हे. मंडळांनीही स्वयंशिस्त पाळून आपल्या सामाजिक परिपक्वतेचे दर्शन घडवावे, एवढीच रास्त अपेक्षा. गणेशोत्सव हा केवळ उत्सवाचा नव्हे, तर चेतना-जागृतीचा प्रसंग ठरला, तरच त्याचे खरे सार्थक होईल.

■ **राघवेंद्र मण्णूर**, डोंबिवली

विपरित परिणाम करणारी वाद्ये नकोतच

'**अमर्याद 'आव्वाज**'' हा अग्रलेख वाचला. हृदयाची धडधड वाढविणारी, गरोदर स्त्रिया, वयस्कर लोक, लहान मुले यांच्यावर विपरित परिणाम करणारी सर्व वाद्ये ही बंद केलीच पाहिजेत. अन्यथा पोलिसांवरच न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्याबाबतचे गुन्हे थेट न्यायालयातच दाखल व्हायला हवेत. कारण अशा तक्रारी पोलीस दाखल करून घेतच नाहीत.

■ **प्रकाश विचारे**, नवे पनवेल

'त्यांचे' ध्वनिप्रदूषण जास्त, आपले कमीच

'**अमर्याद 'आव्वाज**'' संपादकीय वाचले. गणेशोत्सव आला की आवाज फाऊंडेशन आणि मराठी वृत्तपत्रे कमालीच्या उत्साहाने ध्वनी प्रदूषणाच्या दृष्टीने कामाला लागतात. मोहरमच्या वेळी दणादणा डी.जे. वाजत असताना ताबुतांच्या मिरवणुकांचे वेळी हे सारे कोणत्या बिळात लपलेले असतात कळत नाही, 'आवाज फाऊंडेशन'ची ध्वनी प्रदूषणाची पातळी मोजण्याची पद्धत ही सदोष आहे. सामान्यतः सध्याच्या परिस्थितीत, विविध कारणास्तव सर्वच ठिकाणी, आवाजाची पातळी मर्यादेपेक्षा अधिकच असते. हा प्रयोग दस्तुरखुद्द मुंबई उच्च न्यायालयात केला गेला होता. न्यायालयात प्रत्यक्षात कोणतीही ॲक्टिव्हिटी चालू नसताना आवाजाची पातळी मोजली असता ती मर्यादेपेक्षा जास्त नोंदली गेली, याला कारण वातावरणात आवाजाची सतत होत असणारी स्पंदने होय. फाऊंडेशन डी. जे. वाजत असतानाच्या आवाजाच्या पातळीतून जर त्याच ठिकाणच्या सर्वसाधारण ध्वनी प्रदूषणाची पातळी वजा करून तेथील आवाजाच्या पातळीची मोजदाद करेल तर त्यांना जाणवेल की गणेशोत्सवाच्या मिरवणुकीत होणारे ध्वनिप्रदूषण अत्यंत किरकोळ असते. मुख्यत्वे करून गणेशोत्सव मिरवणुकीत घरगुती गणपती सहसा डी. जे. चा वापर करतच नाही आणि दोन सार्वजनिक गणपतींच्या मिरवणुकीत अंतर बरेच मोठे असते, सबब ध्वनिप्रदूषणात फार मोठा फरक पडत असतो. उलट ताबूतांच्या मिरवणुका एकाला दुसऱ्या जोडूनच पुढे सरकत असतात आणि त्या प्रत्येकाच्या डी. जें चा दणदणाट एकापेक्षा एक सरस असतो.

■ **ॲड. एम. आर. सबनीस**, अंधेरी (पूर्व) मुंबई

नदीला वाहण्याचा हक्क देणारे संविधान

पचामामा ही इक्वेडोरमधील मूळनिवासींची जगन्माता. तेलमाफियांनी आपल्या हव्यासापोटी निसर्गाशी तिथल्या लोकांचे असलेले नातेच उद्ध्वस्त करून टाकले होते. सामाजिक चळवळीतून पुढे आलेल्या राफेल कोरिआ या मुत्सद्दी नेत्याने पचामामा कायदा करून हे नाते पुन्हा जोडण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे.

चित्ततोष खांडेकर
नदी विषयक संशोधक अभ्यासक
chittatoshresearch@gmail.com

नदीकारण

विष्णूमय जग वैष्णवाचा धर्म।
भेदाभेदभ्रम अमंगल ।।

तुकोबांचा हा अभंग फक्त भक्तीची परिसीमा सांगत नाही.. तर अद्वैताचे तत्वज्ञान मांडतो. सारे जग ईश्वराने भरलेले आहे. त्यामुळे मी आणि तू असा भेद करणे चुकीचे आहे. तुकाराम महाराजांचे हे वैश्विक तत्वज्ञान ऐकायला चांगले वाटत असले तरी हे तत्वज्ञान वास्तवात आणता येते? त्यावर एखादी शासन व्यवस्था उभी करता येते? नदीच्या हक्कांच्या अनुषंगाने या प्रश्नाचे उत्तर आज शोधूया...

दक्षिण अमेरिकेतील मूळनिवासी समूह एक लोककथा सांगतात. एक गरुड आणि एक गिधाड संपूर्ण आसमंतात उडत असतात. त्या दोघांचं संपूर्ण विश्वावर राज्य असतं. पण एक दिवस गिधाड आणि गरुडाचे मार्ग वेगळे होतात. गिधाड अवकाशात एका बाजूला जाऊन पूर्णपणे नाहीसे होते, तर गरुड पूर्ण आसमंतात एकटाच उंच भरारी घ्यायला लागतो. तो गरुड म्हणजे दुसरे-तिसरे काही नसून आधुनिकता आहे. मूळनिवासी समूह या आधुनिकतेला मानवाची विजयगाथा मानतात - जगातली इतर सर्व सजीवांवर आणि निर्जीवांवर सत्ता गाजवण्यासाठी मिळालेली शक्ती. ५०० वर्षे तो गरूड आसमंतात एकटाच भरारी घेत राहतो. म्हणजेच आधुनिकतेतून औद्योगिकीरण - त्यातून नागरीकरण - विकास - आजचं सगळ जग या साऱ्या प्रक्रियेतून उभं राहणं ही मानवाची 'गरुडभरारी' आहे. पण या गरुडभरारीचे परिणाम काय झाले?

या प्रश्नाचे उत्तर इक्वेडोरमधील स्थानिकच चांगल्याप्रकारे देतील. निसर्गसंपन्नतेने भरून पावलेल्या, ॲण्डीसच्या पर्वतरांगानी सजलेल्या, अमेझॉनच्या उपनद्यांनी बहरलेल्या प्रदेशांनी इक्वेडोर तयार झाला. तिथे मुळात निसर्ग असा वेगळा नव्हताच काही. या जमाती निसर्गाच्या अविभाज्य घटकच होत्या. झऱ्यातून खळाळणारे पाणी छोट्या नद्यांना मिळते, या छोट्या नद्या अमेझॉनसारख्या मोठ्या नदीला मिळतात, अमेझॉन सागराला मिळते, सागराकाठी हिमपर्वतातील पक्षी येऊन वस्ती करतात, तर हिमपर्वतांच्या शिखरांवर सागरगोटे सापडतात. हे निसर्गातील गुंतागुंतीचे नाते, त्याची अगाधता ते पहात होते. त्यांच्याकडे दुर्बिणी नव्हत्या, प्रयोगशाळा नव्हत्या. होती ती रानं, फुलं, नद्या, पर्वत, त्यांची निरीक्षणं आणि न संपणारी कल्पनाशक्ती. याच कल्पनाशक्तीतून त्यांनी विश्वाची एक संकल्पना रचली. त्या संकल्पनेचे नाव 'पचा'... पचा म्हणजे विश्वाचे हे गूढ नाते - घागरीत सागर आहे आणि सागरात घागर आहे, बिंदुतच सिंधु सामावला आहे आणि सिंधूच बिंदू आहे. जगात दुसरे असे काहीच नाही - सारे एकातच सामावले आहेत... तुकाराम महाराजांचे अद्वैत ते हेच, दुसरे काय? निसर्ग असं वेगळं काही नाही - एक गुंतागुतीचे विश्वाचे नाते आहे, ज्यात मानवही सामावला आहे. या गुंतागुंतीने भरलेल्या विश्वाला जोडणारे सूत्र म्हणजे विश्वाची आई - पचाममा अर्थात जगन्माता, जिने हे विश्व निर्माण केले. या विश्वात ती भरून आहे. सजीवात-निर्जीवात सामावली आहे. मानवही त्याला अपवाद नाही. 'नेचर' म्हणजे मानव सोडून सगळे ही पाश्चिमात्य संकल्पना त्यांना मान्य नाही. पचाममा हीच सारं जग व्यापून आहे, त्या पचाममातलं रोजचं जीवनच सण होतात, पीक आलं की आनंदाच्या नद्या ओसंडून वाहतात आणि दुष्काळ पडला की दुःखाचे सागर! अशा या जग्नमातेची प्रार्थनास्थळं इक्वेडोरमध्ये ठिकठिकाणी सापडतात. सतराव्या शतकाच्या सुरुवातीला इथे स्पॅनिश सेना येऊन धडकली. त्यांना पचाममा वगैरे काही मान्यच नव्हते. त्यांना मान्य होतं मानवाचे - पुरुषांचे राज्य. पुरुषांची स्त्रियांवर आणि संपूर्ण जगावर सत्ता. हे जग त्यातील सजीव-निर्जीव सारेच या पुरुषांच्या उत्कर्षाची साधनं, ही स्पॅनिश धारणा. माणसाचा हा पुरुषी अहंकार, त्याची जग पादाक्रांत करण्याची वृत्ती येथील मूळनिवासींना गरुडासारखी वाटते. म्हणूनच आधुनिकता त्यांच्या लोककथेत गरूड होते, तर पचाममा ही जगन्माता त्यांचा कथेत गिधाड होते. गिधाड नाहीसे होणे, म्हणजे पचाममाचे महत्त्व मानवाच्या मनात संपणे. जगन्माता सजीव-निर्जीव सगळ्यांची काळजी घेते. कोणाचीच हानी होऊ देत नाही. गरुडाचे तसे नाही. तो स्वतःच्या स्वार्थासाठी सगळ्यांची हानी करतो. पण ही अशी संकल्पना या मूळनिवासींच्या मनात का रुजली?

इक्वेडोरमध्ये अनेक खनिजं सापडतात.. पण सगळ्यात महत्त्वाचे खनिज म्हणजे तेल. शंभर-दीडशे वर्षांपूर्वी तेलाचा शोध लागला, नंतर तेलाचे खाणकामही ठिकठिकाणी सुरू झाले. आधुनिक जगाचे इंधन म्हणजे तेल. हवा तितका पैसा तेलातून मिळतो. त्यामुळे इक्वेडोरच्या तेलावर स्थानिक व्यापाऱ्यांची आणि राजकारण्यांची तर नजर होतीच पण बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची आणि अमेरिकेसारख्या शेजारी राष्ट्रांचीही नजर होती. त्या तेलाच्या व्यापारावर ताबा मिळवण्यासाठी एक जीवघेणी स्पर्धाच सुरू झाली. यातून इक्वेडोरमध्ये गृहयुद्ध झाले. शेजारच्या पेरूशी झालेल्या युद्धात देशाचा बराचसा भाग गमवावा लागला. या देशावर आपले नियंत्रण राहावे यासाठी अमेरिकेने भरपूर प्रयत्न केले. अमेरिकेला पूरक काम करणारा राज्यकर्ता नसेल तर लगेच लष्कर बंड करायचे आणि लष्करशाही यायची. लष्कर अमेरिकेच्या विरोधात गेले की पुन्हा लोकशाही येई. अमेरिकेचे इक्वेडोरमधील तेलावर नियंत्रण राहावे म्हणून हा सगळा खेळ आलटून-पालटून १९७९ पर्यंत सुरूच राहिला.

तेलाच्या या जीवघेण्या स्पर्धेत मूळनिवासींच्या जमिनी तेल-कंपन्यांनी हडपल्या, खाणमाफिया

राफेल कोरिआ

आणि त्यांच्यातील युद्धाने अशांतता निर्माण झाली, नद्या आणि पाण्याचे स्रोत प्रदूषित झाले, प्रचंड जंगलतोड झाली. या साऱ्यावर अवलंबून असलेले शेतकरी आणि भटक्या-विमुक्त जमाती बहुतांशी मूळनिवासी होत्या. दारिद्र्य, अशांतता, भूकबळी आणि टंचाई एवढेच त्यांच्या नशिबी आले. त्यांच्या मते हा पचाममाचा - जगन्मातेचा कोप आहे. स्वतःच्या स्वार्थासाठी दुसऱ्यांची हानी करणाऱ्या गरूडाचे हे दुष्टचक्र आहे.

पण गरुडाची आणि गिधाडाची ही कथा इथेच संपत नाही. मूळनिवासी म्हणतात, त्यांचे पूर्वज सांगत की गरुडाची ही गरुडभरारी फक्त ५०० वर्षं चालेल, त्यानंतर मग गिधाड परत आसमंतात येईल, गरुडाला पुन्हा गिधाडासोबत फिरावे लागेल. अन्यथा गरुडाचा स्वार्थ त्याचाच नाश करेल... ती ५०० वर्षं आता संपली आहेत, यावर इक्वेडोरमधील मूळनिवासींचा ठाम विश्वास होता. त्यातूनच निसर्ग वाचवायच्या - नदी सांभाळायच्या चळवळी मूळनिवासींनी सुरू केल्या. त्यांची मागणी एकच, पचममाचा कायदा मानणारे संविधान इक्वेडोरमध्ये हवे. पचाममाचा कायदा काय सांगतो - सजीव-निर्जीव, आजच्या भाषेत मानव-निसर्ग, सारेच विश्वाचे अविभाज्य घटक आहेत, सगळेच देशाचे नागरिक आहेत, देशाच्या साधनसंपत्तीवर सगळ्यांचा समान हक्क आहे, कुणाचेही नुकसान व्हायला नको. या मूळनिवासींची भावना तुकोबांच्या शब्दात सांगायची तर, ''कोणाही जीवाचा न घडो मत्सर, वर्म सर्वेश्वर पूजनाचे''.

इथे सर्वेश्वराची जागा पचाममा घेते एवढंच. १९९७ पासून अशा निसर्गाच्या आणि मानवाच्या हक्कांना मान्यता देणारे संविधान हवे म्हणून मूळनिवासींच्या स्वयंसेवी संस्थांनी चळवळ उभी केली. पण त्या संविधानात या हक्कांना जागा मिळाली नाही. मूळनिवासींनी पचाममाचा कायदा वास्तवात आणण्याचे आंदोलन सुरूच ठेवले. इक्वेडोरमध्ये राजकीय अस्थिरता वाढत गेली. १० वर्षांत आठ राष्ट्राध्यक्ष बदलले. मूळनिवासींच्या पाठिंब्याशिवाय स्थिर सरकार येऊ शकत नाही, हे एव्हाना राजकारण्यांच्या लक्षात आले. पण त्यांचे बोट पकडले राफेल कोरिआ या मुत्सद्दी नेत्याने. राजकीय पक्षातून नाही, तर सामाजिक चळवळीतूनच हा नेता मोठा झाला होता. मला निवडून दिले तर पचाममाचा कायदा आणणारे संविधान निर्माण करीन असा विश्वास त्यांनी मूळनिवासींना दिला. या आश्वासनावरच २००७च्या सार्वत्रिक निवडणुकांत कोरिआ विजयी झाले. जिंकल्यावर त्यांनी संविधान सभा स्थापन केली. मूळनिवासींच्या आणि इतर समूहांच्या प्रतिनिधींना बोलावले. आणि २००८ मध्ये पचाममाचा कायदा वास्तवात आला. निसर्गाला - नदीला, पर्वतांना जगण्याचा, पुन्हा वाहण्याचा, शोषणापासून थांबवण्याचे हक्क देणारे जगातले पहिले संविधान तयार झाले.

इक्वेडोरचे संविधान म्हणजे २१व्या शतकातील लोकशाहीसाठी वास्तुपाठच. यातील कलम १० निसर्गाला संविधानिक हक्क आहे हे मान्य करते. कलम ७१ पचाममाचे तत्वज्ञान मान्य करते आणि त्यानुसार मानवाने जगण्याची तरतूद करते. निसर्गाची कोणत्याही प्रकारे हानी झाली, पचाममाचा कायदा मोडला, तर कोर्टात धाव घेता येईल हेही हे कलम सांगते. कलम ७२ निसर्गाला - आणि पर्यायाने नद्यांना पुनरुज्जीवनाचा मुलभूत हक्क देते. तर पुढचे कलम राज्यसंस्था पचाममाचा कायदा मोडणार नाही, निसर्गाचे शोषण होणार नाही याची काळजी घेईल, असे तत्व मांडते. कलम ७४ निसर्ग आणि मानवी समूह परस्पर फायद्याचे वर्तन करतील - जगा आणि जगू द्या - ही सांविधानिक जबाबदारी आहे - असे अधोरेखित करते. लोकशाहीची इतकी व्यापक व्याख्या करणारे हे जगातील पहिले संविधान ठरले आहे.

अद्वैताची संकल्पना सजीव-निर्जीव साऱ्यांमध्ये समभाव बघते. त्याआधारे निसर्गालाही मानवासारखेच समान हक्क देणारे नवीन संविधान इक्वेडोरने दिले. पण असे संविधान नद्यांचे हक्क खरंच राखू शकते? पुढच्या भागांत पाहू या.

कुतूहल

जर्मन सिल्व्हर म्हणजे काय?

सिल्व्हर म्हणजे चांदी ! चांदी हे मूलद्रव्य आहे. पण 'जर्मन सिल्व्हर' यामध्ये मात्र शून्य टक्के चांदी असते. म्हणजेच नावामध्ये 'सिल्व्हर' असं असलं तरी त्यात चांदी अजिबात नसते.

जर्मन सिल्व्हर, हे तांबं, शिसं आणि निकेल हे धातू एकत्र येऊन केलेलं मिश्रण आहे. हजार वर्षांपूर्वी जर्मनीमधल्या एका शहरात 'अर्नऑगस्ट काईटनर' या शास्त्रज्ञाच्या मार्गदर्शनाखाली, धातूंवर काम करणाऱ्या कामगारांनी याचा शोध लावला आणि त्याला 'पॅक्टॉन' किंवा 'व्हाइट कॉपर' असं नाव दिलं. हे तयार करताना वर सांगितलेले धातू, योग्य प्रमाणात मिसळून, १२८० अंश सेल्सियसपर्यंत तापवून, मग ते साच्यात ओतून थंड केले गेले. तेव्हा या मिश्रणाचे भौतिक गुणधर्म चांदीसदृश आहेत असं आढळलं.

चांदीसारखा पांढरा चकचकीत रंग, तन्य म्हणजे तार करता येण्यासारखं आणि वर्धनीय म्हणजे पत्रा करता येण्यासारखं असं हे मिश्रण ! पण हे मिश्रण, चांदीपेक्षा कठीण, दीर्घकाळ वापरण्याजोगं, गंज प्रतिरोधक, उष्णता आणि वीज प्रवाहित करण्याची क्षमता असणारं आणि विविध वस्तू बनवण्यासाठी अतिशय उपयुक्त ! या गुणधर्मामुळे युरोपीय व्यापारी या 'पॅक्टॉन'कडे आकर्षित झाले आणि त्यांनी या मिश्रणाला 'जर्मन सिल्व्हर' असं नाव दिलं.

जर्मन सिल्व्हर शुद्ध चांदीच्या भावाच्या फक्त दहा टक्के इतक्याच किमतीला मिळतं. शिवाय ते गंजत नाही किंवा काळंही पडत नाही; फक्त कालांतराने त्या वस्तूंचा रंग पांढुरका फिका होत जातो. त्याचं चांदीसारखं दिसणं, हे त्यातल्या निकेल आणि तांबं यांच्या प्रमाणावर अवलंबून असतं. साच्यात घालून कोणताही आकार देणं शक्य असल्यामुळे, त्याचा वापर घरातल्या कटलरी, म्हणजेच कापण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या वस्तू, उदाहरणार्थ चाकू, सुरे, काटे इत्यादी गोष्टी बनवण्यासाठी करतात. शिवाय याची नक्षीची भांडी, पूजेचं साहित्य, देवांच्या मूर्ती वगैरे गोष्टीही तयार करता येतात. जर्मन सिल्व्हर 'तन्य' असल्यामुळे ते विद्युत उपकरणांमध्ये, तसंच संगीत वाद्यामध्ये वापरता येतं.

परंतु शुद्ध चांदीचे दागिने आणि जर्मन सिल्व्हरचे दागिने यामध्ये फसगत होऊ शकते, कारण प्रथमदर्शनी दोन्ही चांदीचे वाटावे इतके त्यांच्यात साम्य असतं. शुद्ध चांदी ओळखता यावी म्हणून त्यावरती सरकारी नियमानुसार शुद्धतेचा मार्क म्हणजे हॉलमार्क असणं बंधनकारक असतं. जर्मन सिल्व्हरमध्ये चांदी अजिबात नसल्यामुळे, त्यावरती हॉलमार्क असण्याचा प्रश्न येत नाही. शुद्ध चांदी मऊ असल्यामुळे तिच्या घडवलेल्या वस्तू दबल्या जाऊ शकतात. पण जर्मन सिल्व्हर, चांदीच्या तुलनेत कडक असतं, त्यामुळे ते सहजासहजी दबलं जाऊ शकत नाही किंवा तुटत नाही.

- उर्मिला फडके
मराठी विज्ञान परिषद
ईमेल : office@mavipa.org
संकेतस्थळ : www.mavipa.org

व्यक्तिवेध

'**हे तर** कुणीही करू शकेल' या मराठी शब्दांतली प्रतिक्रिया यायोई कुसामा या जपानी दृश्यकलावतीच्या कलाकृतींबद्दल येण्याचा धोका पत्करूनही, त्यांच्या निधनाची दखल घ्यावीच लागेल- कारण विसाव्या आणि एकविसाव्या शतकातल्या कलेचा इतिहास त्यांच्या उल्लेखाविना लिहिता येणार नाही. हा केवळ जपानमधल्या कुणा महिलेने मिळवलेल्या यशाचा किंवा विक्रमी किमतींचा (उदाहरणार्थ, 'अनटायटल्ड- द नेट' या १९५९ सालच्या चित्रासाठी २०२५ च्या लिलावात मोजली गेलेली १०.५ मिलियन अर्थात दीड कोटी डॉलर म्हणजे सुमारे ९०.९५ कोटी रुपये ही किंमत, आदींचा) इतिहास नव्हे. तो दृश्यकलेतल्या दैनंदिन सौंदर्यदृष्टीचा, फॅशन आणि कला यांच्यातल्या सीमारेषा धूसर होण्याचा आणि त्याहूनही, भोवताली काय चालले आहे, माहीत असूनही 'जे वाटते तेच करत राहाण्या'तून मिळालेल्या कीर्तीचा इतिहास आहे.

यायोई कुसामा

जगभरच्या दृश्यकला-रसिकांना यायोई कुसामांचे नाव घेताच भोपळे आठवतात ! पिवळे भोपळे. त्यावर काळी वर्तुळे. कागदावर रंगवलेल्या चित्रापासून ते कॅनव्हासवर भोपळे. किंवा फायबरचे तीनचार फुटी भोपळे खोलीभर मांडून झालेले मांडणशिल्प, मग लंडनमध्ये केन्सिंग्टन गार्डनच्या हिरवळीवर विराजमान झालेला सहा मीटर उंच आणि पाच मीटर व्यासाचा ब्राँझचा, पण लहानमोठ्या काळ्या ठिपक्यांचा पिवळा भोपळा. कुठून आला तो? जपानच्या मात्सुमोटो या गावातल्या सुखवस्तू कुटुंबात, १९२९ साली जन्मलेल्या यायोई यांनी घरच्या बागायतीत भोपळेच पाहिले. वयाच्या दहाव्या वर्षापासून चित्रकलेचा नाद लागला. आईवडिलांनी पारंपरिक जपानी कलाशाळेत घातले. तिथले शिक्षण १९४८ साली पूर्ण होताहोता पाश्चात्त्य कलेचे आकर्षण वाढले, पण स्वतः जर पारंपरिक शैली सोडायची असेल तर आपली, स्वतःची, व्यक्तिवादी वाटच शोधली पाहिजे... अनुकरणच करायचे तर पारंपरिक काय नि नवकला काय... हेही उमगले.

लहानपणापासून यायोईंना रंग/ आकार किंवा पोतांमध्ये गमतीजमती दिसत असाव्यात : बागेतली फुले टणक, पाने स्पंजासारखी गुबगुबीत मऊ, किंवा फळांचे रंग आहेत त्यापेक्षा गडद, पाना/ फळांवरले छोटे ठिपके मोठे... 'मला भास होतात, याची जाणीव मला झाली. ते फक्त माझे असतात, म्हणून माझ्या चित्रविषयांमध्ये ते येतात,' असे यायोई यांनी स्वतःच्या कलेबद्दल म्हटले आहे. जपानमध्ये एखाददोन प्रदर्शने झाल्यावर लगेच १९५७ मध्ये न्यू यॉर्कच्या कलाक्षेत्रात जम बसवण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. डोनाल्ड ज्युडसारख्या तेव्हाच्या मिनिमलिस्ट चित्रकारांनी तसेच जॉर्जिया ओकीफ यांनी एक महिला चित्रकार म्हणून यायोईंना प्रोत्साहन दिले. दृश्यकला जेव्हा मांडणशिल्पांमध्ये किंवा हॅपनिंगसारख्या क्षणिक प्रकारांत रुळू लागली होती, तो हा १९६० च्या दशकाचा पूर्वकाळ. तेव्हाचे, 'मऊ पानांच्या गादीवर, ठळक ठिपके असलेल्या जाळीदार पोशाखात झोपलेली यायोई' हे यायोई यांच्या एका हॅपनिंगमधले छायाचित्र आज कलेतिहासाचा भाग झाले आहे. अमेरिकन, पुरुषप्रधान कलाजगतात आपली छाप उमटवून त्या मायदेशी परतल्या. शांतपणे जगताना, हव्या तशा कलाकृती करू लागल्या आणि १४ ऑगस्ट रोजी त्यांचे निधन झाल्याची वार्ताही जगाला, २८ ऑगस्ट रोजी सांगून त्यांचे मरणोत्तर खासगीपणही जपण्यात आले !

राजवाडे विचारविश्व

उत्क्रांत होत जाणाऱ्या रूढींचे स्पष्टीकरण

आपण केलेली ऐतिहासिक विधाने निव्वळ भाकडकथा आहेत किंवा खरोखरच घडलेल्या वास्तव घटना आहेत, या बाबींचा पडताळा पाहण्याची इतर साधने उपलब्ध आहेत, असे सांगून राजवाड्यांनी पुढे लिहिले की, 'ऋग्वैदिक अशी एक समजूत सर्वमान्य आहे की, सूर्याची दुहिता जी उषा ऊर्फ सरण्यू तीच सूर्याची भार्या होती. 'प्रजापतिर्वै स्वां दुहितं मध्यायत।' ह्या ऐतरेय ब्राह्मणवचनांत हाच अर्थ स्पष्ट सांगितला आहे. पितृदुहितृसंबंधाचा हा वैदिक पुरावा झाला. स्मृतिग्रंथातहि ह्या चालीची म्हणजे बापाचा स्वतःच्या मुलीशी संबंध होण्याची उदाहरणे आढळतात'...

एवढा खुलासा करून झाल्यावर राजवाड्यांनी समाजातील अशा चालीरीती कालांतराने कसकशा बदलत जातात, उत्क्रांत होत जातात, याचे विस्ताराने सोदाहरण विवेचन केले. त्यांनी लिहिले, 'वसिष्ठसंहिता ही एक जुनाटातली संहिता म्हणजे स्मृतिग्रंथ समजतात. ह्या संहितेत कानीन म्हणून ज्याला म्हणतात त्या पुत्रासंबंधाने बराच ऊहापोह केलेला आढळतो... पित्याच्या घरात राहून विधिवत विवाह न होता कन्येला तुल्य जातीच्या (पर)पुरुषाकडून जो पुत्र होईल तो त्या कन्येच्या बापाचा म्हणजे मातामहाचा पुत्र असे शास्त्र म्हणजे रूढी समजते. येथे समाजशास्त्राच्या दृष्टीने असा प्रश्न उद्भवतो की, तुल्य जातीच्या परपुरुषाकडून लग्न न झालेल्या स्वकन्येच्या ठायी जो पुत्र उत्पादन केला, तो पुत्र त्या कन्येच्या बापाचा काय म्हणून शास्त्र किंवा रूढी ठरवी? तो कानीन मुलगा ज्या परपुरुषाकडून झाला त्याचा तो वास्तविक ठरावा व आपल्या आज्याचा म्हणजे आईच्या बापाचा नातू ठरावा. परंतु कानीन मुलगा परपुरुषाचाही न ठरता किंवा आज्याचा नातूही न ठरता आज्याचा धर्मोत्पादित पुत्र ठरे व त्या पुत्राची प्रत्यक्ष आई त्याची बहीण ठरे'...

'ह्या चमत्कारिक चालीचा अर्थ काय? समाजात ही समजूत व रूढी व हा धर्म काय म्हणून मान्य झाला? सध्याच्या आपल्या समाजात असा प्रकार निंद्य समजला जाईल. परंतु वसिष्ठसंहिताकाली तो अधर्म्य व निंद्य समजला जात नसे. ह्याचे कारण काय?' असे प्रश्न राजवाड्यांनी उपस्थित केले आणि स्वतःच त्यांच्या उत्तरादाखल लिहिले, 'ह्याचे कारण एकच आहे आणि ते हे की, वसिष्ठकालीन समाज अशा एका पुरातन समाजाचा वंशज होता की, ज्या समाजात पिता आपल्या स्वतःच्या कन्येच्या ठायी संतती उत्पन्न करी. सर्वच समाजात ही चाल त्या पुरातनकाली प्रचलित असल्याकारणाने कोणी कोणाला नावे ठेवीत नसत. म्हणजे त्या चालीला अधर्म्य वा निंद्य समजत नसत. वसिष्ठोत्तर मनु वगैरे संहिताकारांना व मनुसंहिताकालीन आर्यसमाजांना स्वकन्येच्या ठायी परपुरुषाकडून झालेल्या मुलाला कन्येच्या बापाने आपला मुलगा म्हणावा, ही चाल अप्रशस्त व अस्वाभाविक वाटून त्या कानीन मुलाचे पितृत्व उत्पादक परपुरुषाकडे किंवा कन्येच्या भावी पतीकडे येणे प्रशस्त वाटलेले उत्तरकालीन स्मृतिग्रंथांतून नमूद केलेले आहे.'

आपल्या विवेचनाचा ओघ पुढे नेत अशा संबंधांच्याच आणखी एका पैलूबाबत राजवाड्यांनी लिहिले, 'आत्तापर्यंत उदाहरणे नमूद केली, ती सर्व एका स्त्रीशी एकाच बापाचा किंवा भावाचा शरीरसंबंध दाखविण्यापुरतीच झाली. अनेक सपिंड पुरुषांचा एकाच सपिंड स्त्रीशी संबंध दाखविणारी वाक्येही इतिहासातून सापडतात. हरिवंशाच्या दुसऱ्या अध्यायात असे लिहिले आहे की, दहा प्रचेत्यांनी व त्यांचा पुत्र जो सोम त्याने सोमाची जी मुलगी मारिषा तिचे ठायी आपापली तेजे घालून दक्ष प्रजापति निर्माण केला. पितृदुहितृसंबंधाचे तर हे उदाहरण आहेच, शिवाय आजा व नात ह्यांचाहि संबंध या उदाहरणात दाखवला आहे, इतकेच नव्हे, तर दहा आजे व एक बाप यांचा संबंध बापाच्या मुलीशी झाल्याचे लिहिले आहे. याच अध्यायात पुढे असे वर्णन आहे की, सोमाचा मुलगा किंवा दौहित्र जो दक्ष प्रजापति त्याने आपल्या सत्तावीस मुली आपला बाप किंवा आजा जो सोम त्यास प्रजोत्पादनार्थ दिल्या...' किती अतर्क्य आहे हे सारे !

- आनंद हर्डीकर
anand47.hardikar@gmail.com

कर्ज-कर्तनाची 'चंद्र'कला!

हजारो कोटींची कर्जे उचलायची, नफ्यावर मक्तेदारी ठेवायची आणि तोट्याची वेळ येताच बँकांचा गळा घोटून कायदेशीर पळवाटांचा आसरा घ्यायचा, असे सातत्याने घडत आहे.

हा ताजा न्यायिक निवाडा सर्वांनाच बोटे तोंडात घालावयास लावेल. राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाने 'झी' समूहाचे संस्थापक सुभाष चंद्रा यांच्या प्रकरणात दिलेला आदेश अनपेक्षितच नव्हे तर प्रचंड धक्कादायक आहे. यात मंजूर झालेल्या परतफेड योजनेअंतर्गत कर्जदात्यांना फक्त ६.२५ कोटी रुपये मिळणार आहेत. प्रश्न असा की, देणी म्हणून मान्य केलेली रक्कम हजारो कोटी रुपयांत असताना इतकी अत्यल्प वसुली न्याय्य ठरवता येईल काय? प्रश्न असाही आहे की, कर्जदात्यांनीच ८० टक्के बहुमताने त्याला मान्यता कशी दिली? हे प्रकरण एकंदरीतच भारताच्या दिवाळखोरी व्यवस्थेची असामान्यपणे कठोर कसोटी ठरते. नियमाधारित विकसित भांडवलशाही व्यवस्थेच्या कर्जसंस्कृतीबाबत ते प्रश्नचिन्ह उभे करते. म्हणूनच या चंद्रा अध्यायाचा साकल्याने आढावा घेणेही आवश्यक ठरते.

तब्बल २२ हजार कोटींची देणी थकीत आणि अवघ्या ६.२५ कोटी रुपयांत सुटका. त्यामुळे देणेकऱ्यांना ९९.९७ टक्के 'हेअरकट' अर्थात जवळपास सर्वच कर्ज रकमेवर पाणी सोडावे लागणार आहे. हे अंकगणित सामान्य समजुतीलाच धक्का देते. देणी थकलेल्या १०० रुपयांपैकी अवघे तीस पैसेच परत मिळणार, हे कोणाला कल्पनेत तरी पटू शकेल काय? एकूणच गदारोळ उडवून देणारे हे आकडे तांत्रिकदृष्ट्या बरोबर असले, तरी संदर्भाशिवाय पाहिल्यास ते दिशाभूल करणारेही ठरतात. एकीकडे या गदारोळाच्या केंद्रस्थानी असलेल्या चंद्रा यांची भूमिका या आकड्यांना फेटाळणारी आहे. हे स्वतःसाठी घेतलेले कर्ज नाही, तर त्यांनी इतरांच्या कर्जासाठी दिलेली ही केवळ वैयक्तिक हमी आहे, असे त्यांचे म्हणणे. मात्र हे जरी मान्य केले, तरी गोंधळ दूर होत नाहीच. ताज्या निवाड्यातून नेमके काय निकाली निघाले, किती वसुली झाली, कोणाचे कर्ज यात आहे आणि कर्जदात्यांना अजून किती वसुलीचा अधिकार आहे, हे प्रश्न आहेतच. त्याबाबतही पुरती स्पष्टता गरजेची आहे.

राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाच्या दोन सदस्य असलेल्या खंडपीठात उभी फूट पडल्यानंतर, तिसऱ्या न्यायिक सदस्याच्या नियुक्तीतून हा निवाडा बहुमताने पुढे आला. सुभाष चंद्रा यांनी दिलेल्या वैयक्तिक हमींमधून निर्माण झालेल्या दायित्वाच्या आधारे कर्जदात्यांनी त्यांच्या वैयक्तिक दिवाळखोरीसाठी दाखल दाव्यांवर तो दिला गेला. त्यामुळे सर्वप्रथम या प्रकरणी वैयक्तिक हमी म्हणजे काय हे समजून घ्यावे लागेल. भारतीय करार कायद्यात हमीदाराची जबाबदारी ही मुख्य कर्जदाराच्या जबाबदारीशी जोडलेली आहे. डिसेंबर २०१९ मध्ये दुरुस्तीनुसार दिवाळखोरीच्या न्यायशास्त्रानेही त्याला मान्यता दिली आहे. कंपन्यांच्या कर्जासाठी वैयक्तिक हमीदारांवर कारवाई करण्याची कायदेशीर परवानगी दिली आहे. त्यामुळे मूळ दावा जरी १७० कोटी रुपयांच्या कर्जासाठी दिल्या गेलेल्या हमीपासून सुरू झाला असला, तरी दायित्वाची रक्कम एस्सेल समूहातील अन्य कंपन्यांशी (अर्थात स्व-मालकीच्या कंपन्यांसाठीच) घेतल्या गेलेल्या कर्जागणिक पुढे वाढत गेली, हेही ध्यानात घेतले जावे. त्यामुळे हे कर्ज स्वतःसाठी घेतले नसल्याचा चंद्रा यांचा दावा हास्यास्पद ठरतो आणि म्हणून स्वीकृत दाव्याच्या २२ हजार कोटींच्या आकड्यावरील त्यांचा आक्षेपही गैरलागू ठरतो. चंद्रा यांचा हा नामानिराळा युक्तिवाद आणि स्वतःच प्रवर्तक असूनही 'कर्ज कंपनीने घेतले आहे, त्यामुळे माझी काहीच जबाबदारी नाही', असे म्हणणाऱ्यांच्या भूमिकेला एका ताज्या अहवालाने पटलावर आणले आहे. दिवाळखोरी न्यायव्यवस्थेचे नियमन करणाऱ्या 'भारतीय दिवाळखोरी आणि नादारी मंडळ' – म्हणजे 'आयबीबीआय' – त्याची ताजी तिमाही आकडेवारी यावर लख्ख प्रकाश टाकते. यातून चंद्रा यांच्यासारख्या वैयक्तिक हमीदारांच्या

घर, गाडी, मुलांचे शिक्षण यासाठी घेतलेल्या कर्जाच्या हप्त्याची दरमहा कसोशीने जुळवाजुळव करणाऱ्या मध्यमवर्गीयाची ही घोर थट्टा ठरते.

प्रकरणांमध्ये ९९ टक्के 'कर्जकपाती'ची कात्री लागणे हा अलीकडे एक सामान्य नियम बनल्याचेच ध्यानात येते. वैयक्तिक हमीदारांवर कारवाईच्या ३० जून २०२६ पर्यंत दाखल ५,१८६ प्रकरणांपैकी ६४ प्रकरणांमध्ये परतफेड योजनेवर अंतिम तोडगा निघाला, असे 'आयबीबीआय' सांगते. धक्कादायक म्हणजे, या निकाली निघालेल्या या ६४ प्रकरणांमधून कर्जदात्यांना केवळ २३४.५६ कोटी रुपयांची वसुली करता आली आहे. ही जी वसुलीची रक्कम आहे ती एकूण मान्य दाव्यांच्या जेमतेम एक टक्का इतकेच भरते. या आधीही स्वस्तात सुटका झालेले अनेक जण आहेतच! मग आताच इतका गदारोळ कशासाठी, असा चंद्रा यांचा ताजा तळतळाट. तो स्वाभाविकच.

कारण दिवाळखोरीच्या प्रकरणात वसुलीचा दर हा कायम शोचनीय मुद्दा राहिला आहे. कर्जदात्या बँकांना मोठ्या प्रमाणावर येणे रकमेच्या अगदी ९० ते ९५ टक्क्यांवर पाणी सोडावे लागणे, अशी या कायद्यावर रिझर्व्ह बँकेपासून ते प्रमुख अर्थतज्ज्ञांकडून सर्वात महत्त्वाची टीका होत आली आहे ती याच कारणांमुळे. एकीकडे धंदा कधीही आपल्या पैशाने करायचा नसतो, अशी रूढ उद्यम-धारणा. तर दुसरीकडे बँकांचा पैसा बुडवण्याला व्यावहारिक चातुर्याशी जोडणारी सैद्धांतिक बांधणीही विकृतपणे आकार घेऊ पाहात आहे. हजारो कोटींची कर्जे उचलायची, नफ्यावर स्वतःची खासगी मक्तेदारी ठेवायची आणि तोट्याची वेळ येताच बँकांचा गळा घोटून कायदेशीर पळवाटांचा आसरा घ्यायचा. हा उघडपणे दिसून येणारा प्रकार म्हणजे घरासाठी, गाडीसाठी अथवा मुलांच्या शिक्षणासाठी घेतलेल्या कर्जाच्या हप्त्याची दर महिन्याला कसोशीने जुळवाजुळव करणाऱ्या सामान्य मध्यमवर्गीयाची घोर थट्टा ठरते. या मंडळींना मात्र एक हप्ता चुकला तरी दारात जप्तीची नोटीस आणि वसुली एजंट्सचा ससेमिरा उभा ठाकतो, असे अनुभवास येते. एकूणच दिवाळखोरी प्रक्रियेला 'व्यवस्थापकीय चातुर्य' आणि 'उद्योगी मुत्सद्देगिरी'चा गोंडस मुलामा चढवला जात आहे. त्यामुळे देशातील एक अत्यंत महत्त्वाची व दूरगामी आर्थिक सुधारणा ठरलेल्या दिवाळखोरी संहितेचा आत्मा आणि विश्वासार्हताच मारली जाते. हे दुर्दैवीच.

राजकारण्यांप्रमाणे थेट शिवीगाळावर आले नसले तरी आणि बरीच शिस्त-संयम बाळगून आलेल्या देशाच्या उद्योगजगतात या निमित्ताने मानापमान नाट्य सध्या रंगल्याचे दिसून येते. शेरेबाजी, उपरोधिक टोले किंवा टक्के-टोणपे हाणत टीकेला मुक्त वाव मिळताना दिसत आहे. बँकांचे कर्ज बुडवले म्हणून देशाबाहेर फरार झालेले आणि स्व-प्रत्यार्पणाच्या दाव्याविरोधात खटला लढत असलेले विजय मल्ल्या आता भारताला कर्जसंस्कृतीचे धडे देत आहेत. तर स्वस्तात सुटका करून घेणारे सुभाष चंद्रा हे रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे मुकेश अंबानी यांना त्यांच्या पित्याच्या शिकवणीचे स्मरण करून देत आहेत. देशातील अग्रेसर खासगी बँक असलेल्या 'एचडीएफसी'ला अकस्मात पोरकेपणाची जाणीव झाली आणि तिने न्यायाचा धावा सुरू केला आहे. शोषक-शोषितांच्या व्याख्याच नव्याने बदलाव्यात असे हे सारे आहे. ज्यांचा पैसा यातून लयाला गेला त्या त्या प्रामाणिक करदात्याला मात्र या धबडग्यात काहीच स्थान नाही. बड्यांची किरकोळ रकमेवर सुटका आणि लहानांची पै पैसाठी गचांडी अशी ही व्यवस्था. हे जे काही सुरू आहे तो भ्रष्टाचार ठरत नाही काय? 'ही ९९ टक्क्यांच्या कर्ज-कर्तना'च्या औदार्याची गंगा आपल्याही अंगणातून वाहावी असे सामान्य भारतीयालाही वाटल्यास गैर ते काय? आपल्यासाठीही मग असे सोयीस्कर कायद्याचे कालवे खोदले जावेत, ही त्याची देखील आस असेल, तर तिला अनाठायी कसे म्हणावे? ही कर्ज-कर्तनाची 'चंद्र'कला सामान्यांच्या अंगणातही असे चांदणे फुलवेल?

कृतीवादी भाजप आता प्रतिक्रियावादी?

लाल किल्ला

महेश सरलष्कर
mahesh.sarlashkar@expressindia.com

आतापर्यंत अजेंडा ठरवून विरोधकांना प्रतिक्रिया देण्यास भाग पाडणारा भाजप आणि केंद्र सरकार यांच्या वागण्यात जंतर-मंतरवरच्या आंदोलनानंतर लक्षणीय बदल जाणवू लागला आहे. आपल्या कृतीतून राजकारणाची दिशा ठरवून देणारा भाजप प्रतिक्रियावादी का झाला असावा?

जंतर-मंतरवरच्या आंदोलनानंतर भाजप आणि केंद्र सरकार यांच्या वागण्यात बदल झालेला आहे; दोघेही कधी नव्हे इतके प्रतिक्रियावादी झाले आहेत. आत्तापर्यंत कोणाचीही फारशी पर्वा न करता 'आम्ही जे करू ते सहन करा', असे सत्ताधारी उद्दामपणे म्हणत होते. 'आम्ही कृती करणार, तुम्ही प्रतिक्रिया देत राहा, आम्हाला काही फरक पडत नाही', असेच जणू ते सांगत होते. लोकसभेच्या संसदीय अधिवेशनामधील चर्चेला उत्तर देताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी 'काय आणि कधी बोलायचं हे मी ठरवेन. माझ्या भाषणाचा क्रम मी ठरवेन. विरोधक ते ठरवू शकत नाहीत', असे तावातावाने सांगितले होते. संसदेतील सभागृहे ही मोदी-शहांसाठी हक्काची जागा होती. शहा तर अनेकदा सभागृहात संतापलेले सगळ्यांनी पाहिले आहेत. ते विरोधकांच्या म्हणण्याचा जोरदार प्रतिवाद करताना दिसले होते. मोदींनी तर 'मी एकटा पुरेसा आहे', असे विरोधकांना ठणकावले होते. असे ते भाजप आणि केंद्र सरकारचे जबरदस्त दिवस होते. मोदी-शहा किंवा भाजपचे नेते म्हणतील ते होत असे आणि विरोधक त्यावर प्रतिक्रिया देत फिरत असत. उत्तर प्रदेशात कावडियांच्या यात्रेत दुकाने हिंदूंची की मुस्लिमांची हे समजले पाहिजे, असा आग्रह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी धरला होता. त्यांच्या आग्रहानुसार प्रशासनाने कारवाई केली. दुकानांवर नावे लिहिण्याचे फर्मान काढले गेले. मग, विरोधकांनी या धोरणाला कडाडून विरोध केला. असे एकूण सत्ताधाऱ्यांनी करायचे आणि त्यावर विरोधकांनी बोलायचे, असा प्रघात होता. भाजपच्या आयटी सेलचे प्रमुख अमित मालवीय दररोज समाजमाध्यमांवरून नवनवा अजेंडा ठरवायचे. मग, तो मोडून काढण्यात काँग्रेसवाल्यांची दमछाक व्हायची. असा कृतीवादी भाजप आता प्रतिक्रियावादी झालेला आहे. व्यक्ती, संस्था, संघटना, सरकार असे कोणीही प्रतिक्रियावादी व्हायला लागले तर काहीतरी बिघडले आहे, असे मानायला हरकत नाही. काहींना उपपंतप्रधान होता होता; अचानक लोकांच्या नजरेतून गायब व्हावे लागावे, यातच बदललेल्या परिस्थितीचा अंदाज येऊ शकेल.

काँग्रेसचे नेते व लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी पुण्यातील 'छात्रों की गूंज' या कार्यक्रमात 'पितृसत्ताक व्यवस्थेला उखडून टाका', असे म्हटल्याबरोबर सत्ताधारी मंडळी प्रतिक्रिया देऊ लागली आहेत. राहुल गांधी अजेंडा निश्चित करत आहेत आणि भाजपला त्यांना प्रतिसाद द्यावा लागत आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनापासून भाजप आणि केंद्र सरकारच्या या प्रतिक्रियावादाची सुरुवात झाली होती. २० जुलैला जेन-झी आंदोलकांनी मोर्चा काढला, त्यावर पोलिसांनी पॅलेट गन वगैरेचा मारा करून तरुणांमध्ये पोलिसी यंत्रणेची जरब निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला गेला होता. हा प्रयोग खरोखर यशस्वी झाला असता तर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा संसदेच्या सभागृहांत आले असते आणि त्यांनी ठरवलेल्या क्रमानुसार आक्रमक भाषण करून विरोधकांची कोंडी केली असती. मग, अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी सभागृहांमध्ये 'मोदी-मोदी' असा जयघोष केला गेला असता. पण, यापैकी काहीच झाले नाही. त्यानंतर शहा संसदेच्या सभागृहांत आले नाहीत, चर्चा झाली नाही. त्यांना उत्तरही देता आले नाही. मोदी-शहा लोकसभेत फक्त 'वंदे मातरम्' म्हणण्यापुरते आले होते. राज्यसभेत तर ते दोघे फिरकलेही नाहीत. तिथे त्यांच्याशिवायच 'वंदे मातरम्' झाले. ही माघार घेण्याची, दबून जाण्याची प्रतिक्रिया होती. अशा पद्धतीने एक पाऊल मागे घेतले जात असताना, संसदेच्या आवारात सत्ताधारी पक्षाच्या खासदारांना काँग्रेसविरोधात निदर्शने करावी लागली. दोन दिवस तर दोन्ही बाजूचे खासदार एकमेकांना भिडले होते. कोणी या प्रकाराला विनोदी राजकीय दृश्य असे म्हणू शकते. पण हा कथित विनोद सत्ताधाऱ्यांमुळे निर्माण झाला होता, हे त्यांनाही मान्य होऊ शकेल.

संसदेचे पावसाळी अधिवेशन संपताना राहुल गांधी आणि काँग्रेसच्या नेते-कार्यकर्त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या निवासस्थानासमोर 'फ्लॅश मॉब'प्रमाणे 'फ्लॅश प्रोटेस्ट' केला. सत्ताधाऱ्यांना या अचानक झालेल्या निदर्शनाचा अंदाज नव्हता. हे निदर्शन यशस्वी झाले. मग, अशाप्रकारची आंदोलने प्रभावशाली ठरू शकतात हे राहुल गांधी आणि काँग्रेसच्या लक्षात आले. मग, राहुल गांधींनी अचानक संसदमार्ग पोलीस ठाण्यामध्ये जाऊन पॅलेट गनचा वापर करणाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली.

सहा-सात तासांनंतर अखेर गुन्हा दाखलही झाला. हे दुसरे आंदोलनही यशस्वी झाले. या दरम्यान, राहुल गांधींनी देहरादून आणि प्रयागराज या दोन्ही शहरांमध्ये 'छात्रों की गूंज' हा तरुण-तरुणींच्या समस्यांना वाचा फोडणारा कार्यक्रमही यशस्वी केला. संसदमार्ग पोलीस ठाण्यात जाऊन आंदोलन केल्यानंतर राहुल गांधी पुण्यात गेले, तिथे फक्त मुलींसाठी 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम झाला. हा कार्यक्रम अभूतपूर्व यशस्वी झाला, हे भाजपलाही मान्य करावे लागेल. कार्यक्रमासाठी चार पाच तास उभे रहावे लागले तरी तरुणी- स्त्रियांचा उत्साह तसाच टिकून होता. पैसे देऊन आणलेले लोक इतका वेळ उभे राहून नेत्याला उत्स्फूर्त प्रतिसाद देत नसतात. त्यामुळे इथली मोठी गर्दी खरी होती, भाडोत्री नव्हती, असे म्हणायला हरकत नाही. या कार्यक्रमातील पितृसत्ताकतेला दिलेल्या आव्हानामुळे सत्ताधाऱ्यांनी इतक्या पोटतिडिकीने वाद घालायला सुरुवात केली की, आपण काँग्रेसच्या डावपेचात फसत चाललो आहोत याची त्यांना कल्पनाही आली नाही. हा वाद बहुधा राहुल गांधींना अपेक्षितच होता. सध्या राहुल गांधी करत असलेले सार्वजनिक कार्यक्रम हे जेन-झींच्या आंदोलनाला अचूक राजकीय टोक आणणारे आहेत, असे म्हणावे लागते! आता नोव्हेंबरध्ये नागपूरध्ये होऊ घातलेल्या 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रमाकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले गेले आहे.

काँग्रेस आणि राहुल गांधी फक्त जेन-झींचेच आंदोलन नव्हे, तर निवडणुकीचे राजकारणही पद्धतशीरपणे पुढे घेऊन चाललेले आहेत. १८-२९ या वयोगटातील जेन-झींचे प्रमाण २०२६ पर्यंत विविध राज्यांमध्ये २२ टक्के ते ३६ टक्के असेल. त्यातही उत्तरेकडील राज्यांमध्ये ते सर्वाधिक असेल. उत्तर प्रदेश (३४ टक्के), बिहार (३७ टक्के), उत्तराखंड (३२ टक्के), जम्मू-काश्मीर (३१ टक्के), राजस्थान (३२ टक्के), मध्यप्रदेश (३१ टक्के) असे हे प्रमाण असेल. हे 'जेन-झी' पुढच्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये निर्णायक ठरू शकतात. या जेन-झींना आपल्याकडे वळवून घेऊ शकेल, त्या पक्षासाठी लोकसभा निवडणूक तुलनेने अनुकूल ठरू शकते. जंतर-मंतरवरील आंदोलनानंतर राहुल गांधींना जेन-झींचा प्रतिसाद मिळू लागला आहे आणि तो वाढत जाण्याची शक्यता दिसते. हे लक्षात घेऊन काँग्रेसने धोरणात्मक पावले टाकल्याचे जाणवते. शिक्षण आणि इतर मूलभूत प्रश्नांवर जेन-झी व्यक्त होत आहेत, त्यांना राहुल गांधींकडून प्रतिसाद मिळतो. ते सातत्याने 'छात्रों की गूंज' आणि इतर कार्यक्रमांमधून तसेच समाजमाध्यमांमधून जेन-झींशी थेट संवाद साधत आहेत. या जेन-झींमधील मुलींना ते काँग्रेसकडे वळवू पाहत आहेत. कुठल्याही पक्षासाठी नवे तरुण मतदार महत्त्वाचे ठरतात, त्यातही महिला मतदार अधिक. राज्या-राज्यांत भाजपच्या विजयामध्ये महिला मतदार निर्णायक ठरल्याचे मानले जाते. तोच प्रयोग काँग्रेस करत आहे, मात्र जेन-झींच्या संदर्भात. पुण्यातील कार्यक्रम फक्त जेन-झींना आवाहन करणारा नव्हता, तो तरुण महिला मतदारांना साद घालणारा होता. पुण्याच्या कार्यक्रमातून राहुल गांधींनी तीन गोष्टी साध्य करण्याचा प्रयत्न केलेला दिसला. एक; जेन-झींचे प्रश्न मांडणे, त्यांना सातत्याने प्रतिसाद देणे, त्यांचा उत्साह कायम ठेवणे. दोन; जेन-झी महिलांपर्यंत पोहोचणे, त्यांच्या आशा-आकांक्षांना पाठिंबा देणे. तीन; दलित मतदारांनाही पुन्हा हाक देणे. शनिवारी दिल्लीत झालेल्या पत्रकार परिषदेत काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या हल्दवानीतील कार्यक्रमानंतर झालेल्या 'शुद्धीकरणा'च्या घटनेवरून राहुल गांधी आक्रमक झाले होते. 'खरगे माझ्या पक्षाचे, काँग्रेसचे अध्यक्ष आहेत. त्यांच्याबाबतीत झालेली घटना ही अस्पृश्यता मानली पाहिजे. संविधान अस्पृश्यता मानत नाही. हा गुन्हा आहे, पोलिसांना गुन्हा दाखल करावाच लागेल', असे राहुल गांधींनी म्हटल्यामुळे काँग्रेस पुन्हा 'फ्लॅश प्रोटेस्ट' करेल असे दिसते. दलितांच्या मुद्द्याबरोबर ओबीसी जनगणनेचा मुद्दाही काँग्रेसने हाती घेतलेला आहे. हे सगळे मुद्दे उत्तरेकडील राज्यांमध्ये कळीचे ठरतात. जेन-झींची सर्वाधिक संख्या उत्तरेच्या राज्यांमध्ये आहे; या संभाव्य मतदारांनी काँग्रेसला प्रतिसाद दिला तर भाजपसाठी निवडणुका आव्हानात्मक होतील. जेन-झी आणि जेन-अल्फा यांच्या पालकांच्या पिढीला भाजपने हिंदुत्व आणि त्यावर आधारित राष्ट्रवादाच्या मोहात अडकवले आणि सत्ता मिळवली, ती टिकवलीही. भाजपने आपला मतदार ओळखला, त्याला आपल्याकडे खेचून घेतले. जेन-झीच्या रुपात काँग्रेसला आपला मतदार मिळू शकतो. राहुल गांधींची वाटचाल त्या दिशेने सुरू आहे, असे म्हणता येईल. जेन-झी मतदारांपर्यंत पोहोचण्यामध्ये राहुल गांधींनी आघाडी घेतलेली आहे. यावेळी भाजप मागे राहिलेला आहे. म्हणूनच भाजपसारखा कृतीवादी पक्ष आता अचानक प्रतिक्रियावादी झाल्याचे दिसू लागला आहे.

अन्वयार्थ

ऐतिहासिक गरुडभरारी

खेळ कुठलाही असो, जेव्हा सर्व काही संपल्यासारखे वाटते, तिथूनच अनेकदा विजेत्याचा उदय होतो. भारताचा युवा बुद्धिबळपटू ग्रँडमास्टर आर. प्रज्ञानंद याने ग्रँड चेस टूर स्पर्धेतील विजेतेपदापर्यंत मारलेली मजल पाहिली, की याचा प्रत्यय येतो. या स्पर्धेच्या अंतिम लढतीत जागतिक क्रमवारीत दुसऱ्या स्थानावर असलेल्या अमेरिकेच्या फॅबियानो कारुआनाविरुद्ध बुद्धिबळाच्या पारंपरिक प्रकारातील सहा गुणांची मोठी पिछाडी जलद आणि अतिजलद प्रकारात भरून काढून प्रज्ञानंदने विजेतेपदाचा मान मिळवला.

बुद्धिबळातही वेगवेगळ्या स्पर्धा बुद्धिबळपटूंच्या कौशल्याची कसोटी पाहतात. क्रिकेटमध्ये कसोटी, एकदिवसीय, टी-२० अशा वेगवेगळ्या प्रकारांत वेगवेगळ्या प्रकारचे कौशल्य लागते, तसे. त्यामुळे 'ग्रँड चेस टूर' स्पर्धेतील विजेतेपदही जवळपास जागतिक विजेतेपदाइतकेच मानाचे. या स्पर्धेत पारंपरिक पद्धतीबरोबरच बुद्धिबळपटूला जलद आणि अतिजलद प्रकारात स्वतःला सिद्ध करावे लागते. विजेतेपदासाठी या तिन्ही प्रकारांत तुम्हाला सरस कामगिरी करावी लागते. पण, येथे प्रज्ञानंदला पारंपरिक, म्हणजे पहिल्या प्रकारात तब्बल सहा गुणांच्या पिछाडीवर राहावे लागले होते. अनेकांनी कारुआनाचा विजय निश्चित मानला होता. प्रज्ञानंदच्या मनात मात्र काही वेगळेच डावपेच शिजत होते. तो मुळात जलद प्रकारात माहीर आहे. त्याने या वेळी त्या कौशल्याला आणखी धार लावली आणि त्यानंतर जे घडले, तो जागतिक बुद्धिबळाच्या इतिहासातील एक सुवर्णअध्याय ठरला.

प्रज्ञानंदने अफाट संयम आणि आक्रमकतेचा सुरेख मेळ घालून दोन्ही जलदगती सामने जिंकले आणि कारुआनाची आघाडी मोडीत काढली. अतिजलद (ब्लिट्झ) प्रकारात सुरुवातीला वेळेचे गणित साधण्यात तो चुकला खरा, पण वेळीच पटावरील नियंत्रण राखून कमालीच्या संयमाने त्याने विजेतेपदाचा मुकुट आपल्या डोक्यावर चढवला. ही स्पर्धा जिंकणारा तो पहिलाच भारतीय खेळाडू.

सध्या बुद्धिबळातील जागतिक विजेतेपद भारताच्याच डी. गुकेशच्या नावावर आहे. आता पुढच्या जागतिक विजेतेपदाच्या लढतीची प्रतीक्षा असताना, या दुसऱ्या महत्त्वाच्या स्पर्धेतील भारतीय खेळाडूच्या कामगिरीने चौसष्ट घरांच्या खेळातील भारताचे वर्चस्व नव्याने जगासमोर आले. गुकेश आपले जागतिक विजेतेपद टिकविण्यासाठी उझबेकिस्तानचा युवा ग्रँडमास्टर जव्हाखिर सिंदारोव्ह याच्याशी खेळणार आहे. ही लढत याच वर्षी २२ नोव्हेंबरपासून जिनिव्हा येथे होईल.

पहिल्या जागतिक विजेतेपदानंतर गुकेशच्या कामगिरीत या वर्षी अनेक चढ-उतार झाले. पण, दुसरीकडे या संपूर्ण वर्षात प्रज्ञानंदने दाखवलेली सातत्यपूर्ण कामगिरी थक्क करणारी आहे. याच वर्षी नॉर्वे चेस स्पर्धेत जगातील अव्वल खेळाडू मॅग्नस कार्लसनला दोनदा पराभूत करण्याचा पराक्रम प्रज्ञानंदने केला. सिंकफिल्ड चषक स्पर्धेत तो उपविजेता ठरला आणि आता कारुआनाला त्याच्याच भूमीत नमवून त्याने २०२७ च्या टूरमधील आपले स्थानही निश्चित केले.

प्रज्ञानंदच्या २०२५ मधील कामगिरीच्या तुलनेत २०२६ मधील खेळात कमालीचा संयम आणि स्थिरता दिसून येते. प्रज्ञानंद आता केवळ आक्रमक खेळत नाही, तर प्रतिस्पर्ध्याच्या चुकांची वाट पाहून अचूक डाव टाकण्यात पटाईत झाला आहे. एका बाजूला बुद्धीची कसोटी आणि दुसऱ्या बाजूला वेळेचे प्रचंड दडपण, अशा स्थितीत प्रज्ञानंदने पिछाडीवरून खेचून आणलेला विजय कोणत्याही क्षेत्रात संघर्ष करणाऱ्या प्रत्येकासाठी प्रेरणादायी आहे. चेन्नईच्या गल्ल्यांमधून सुरू झालेला 'प्रज्ञे'चा हा प्रवास आज जगाच्या पाठीवर मानाचा ठरत आहे.

प्रज्ञानंदचे हे विजेतेपद आगामी जागतिक ऑलिम्पियाड आणि कँडिडेट्स साखळी स्पर्धांसाठी भारतीय संघाला, तसेच जागतिक विजेतेपदाच्या लढतीसाठी डी. गुकेशला निश्चित प्रेरणादायी ठरेल. डी. गुकेश, अर्जुन एरिगसी आणि प्रज्ञानंद यांच्यात निकोप स्पर्धा असणे भारतीय बुद्धिबळासाठी महत्त्वाचे आहे.

हा विजय केवळ प्रज्ञानंद नावाच्या २१ वर्षीय तरुणाचा नाही, तर भारतीय बुद्धिबळ क्षेत्रात आलेल्या नव्या क्रांतीचा आहे. एके काळी जागतिक स्तरावर भारताची ओळख फक्त विश्वनाथन आनंद यांच्यापुरती मर्यादित होती. मात्र, गेल्या काही वर्षांत डी. गुकेश, अर्जुन एरिगसी, विदित गुजराती या पुरुष खेळाडूंबरोबर कोनेरु हम्पी, आर. वैशाली, दिव्या देशमुख अशी व्याप्ती वाढली आहे. गुकेशने आनंदप्रमाणे जागतिक विजेतेपद मिळविले आणि आता प्रज्ञानंदने ग्रँड चेस टूर जिंकून हे सिद्ध केले, की भारत आता एका खेळाडूवर अवलंबून नसून, तरुणांची एक संपूर्ण फळी जगावर राज्य करण्यास तयार आहे.

कारागृहांवरील कैद्यांच्या संख्येचा ताण कसा कमी करणार?

विश्लेषण

महेश बोकडे
mahesh.bokade@expressindia.com

गृह विभागाच्या कारागृह व सुधारसेवा विभागाच्या ३१ जुलै २०२६ अखेरच्या आकडेवारीनुसार, राज्यातील कारागृहांमध्ये कैद्यांची अधिकृत क्षमता २७ हजार ५०४ असून प्रत्यक्षात तिथे ४० हजार ४१२ कैदी आहेत. त्यापैकी ३३ हजार ६६२ म्हणजे ८३.३ टक्के कच्चे कैदी आहेत.

कारागृहांतील कैदीसंख्येची नेमकी स्थिती काय?

राज्यातील कारागृहांची प्रत्यक्ष कैदीसंख्या अधिकृत क्षमतेच्या १४७ टक्के आहे. म्हणजे प्रत्येक १०० जागांमागे सुमारे १४७ कैदी आहेत. मात्र सर्व कारागृहांतील परिस्थिती सारखी नाही. नऊ मध्यवर्ती कारागृहांपैकी काहींवर मोठा भार आहे. मुंबई मध्यवर्ती कारागृहात ९९९ जागांच्या तुलनेत ३ हजार २१९, येरवड्यात २ हजार ७७७ जागांच्या तुलनेत ६ हजार ९६९, तर ठाण्यात १ हजार १४१ जागांच्या तुलनेत २ हजार ८०३ कैदी आहेत. त्यामुळे प्रत्येक कारागृहावरील प्रत्यक्ष भारही महत्त्वाचा ठरतो.

८३ टक्के कच्चे कैदी असण्याचा अर्थ काय?

राज्यभरातील कारागृहातील एकूण ४० हजार ४१२ कैद्यांपैकी ३३ हजार ६६२ म्हणजे ८३.३ टक्के खटले न्यायप्रविष्ट आहेत. न्यायप्रविष्ट म्हणजे ज्यांच्या प्रकरणांचा अंतिम निकाल अद्याप झालेला नाही असे कैदी. त्यामुळे कारागृहांतील गर्दीचा प्रश्न केवळ शिक्षा झालेल्या कैद्यांच्या संख्येशी जोडता येत नाही. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने २४ मार्च २०२६ रोजी लोकसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, ३१ डिसेंबर २०२३ रोजीही महाराष्ट्रात ३२ हजार ४३८ कच्चे आणि ८ हजार अपराध सिद्ध झालेले कैदी होते. त्यामुळे कच्च्या कैद्यांचे मोठे प्रमाण ही केवळ आताची स्थिती नसल्याचे सरकारी आकडेवारीतून दिसते.

गर्दी कमी करण्यासाठी कायदेशीर व्यवस्था काय?

कच्च्या कैद्यांना दिलासा देण्यासाठी भारतीय नागरिक

सुरक्षा संहितेच्या कलम ४७९ मध्ये तरतूद आहे. काही अपवाद आणि अटींच्या अधीन राहून संबंधित गुन्ह्यासाठी निर्धारित कमाल कारावासाच्या निम्मा कालावधी कोठडीत पूर्ण केलेल्या कच्च्या कैद्यांना जामीन देण्याची तरतूद आहे. प्रथमच गुन्हा करणाऱ्या पात्र कैद्यासाठी हा कालावधी एकतृतीयांश आहे. पात्र कैद्याच्या सुटकेसाठी न्यायालयात अर्ज करण्याची जबाबदारी कारागृह अधीक्षकावरही आहे. या तरतुदीच्या अंमलबजावणीबाबत केंद्राने २०२४ आणि २०२५ मध्ये राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना सूचना दिल्या आहेत. त्याचबरोबर न्यायप्रविष्ट कैदी पुनरावलोकन समित्यांद्वारे पात्र प्रकरणांचा आढावा घेण्याची व्यवस्था आहे. आदर्श कारागृह नियमावलीतही कायदेशीर मदत आणि कच्च्या कैद्यांसाठी स्वतंत्र तरतुदी आहेत.

क्षमता वाढविणे हाच एकमेव उपाय आहे का?

नवीन कारागृहे उभारल्यास किंवा विद्यमान कारागृहांची क्षमता वाढविल्यास उपलब्ध जागांचा प्रश्न काही प्रमाणात सुटू शकतो. मात्र ८३ टक्क्यांहून अधिक कैदी न्यायप्रविष्ट असल्याने केवळ बांधकामातून दीर्घकालीन तोडगा निघेलच असे नाही. केंद्रानेही कच्चा कैद्यांच्या प्रकरणांचा आढावा, पात्र कैद्यांना कायद्यानुसार दिलासा आणि कायदेशीर मदत उपलब्ध करण्यावर भर दिला आहे. केंद्राचा 'सपोर्ट टू पुअर प्रिझनर्स' उपक्रम आर्थिक अडचणींमुळे दंड किंवा जामिनाची रक्कम भरू न शकणाऱ्या पात्र कैद्यांना मदत करण्यासाठी आहे. मात्र कारागृह हा राज्यसूचीतील विषय असल्याने या उपायांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे.

गर्दीमुळे कारागृह व्यवस्थेवर काय परिणाम होऊ शकतो?

केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या आदर्श कारागृह नियमावली-२०१६मध्ये कैद्यांची निवासव्यवस्था, आरोग्य, कल्याण, कायदेशीर मदत आणि कारागृह व्यवस्थापनाच्या विविध बाबींचा समावेश आहे. त्यामुळे मंजूर क्षमतेपेक्षा सातत्याने अधिक कैदी राहिल्यास उपलब्ध पायाभूत सुविधा आणि सेवांवरील मागणी वाढते. केंद्राने कारागृह आधुनिकीकरणासाठी सुरक्षा व तंत्रज्ञानाधारित पायाभूत सुविधा तसेच 'ई-प्रिझन्स'सारख्या प्रकल्पांनाही पाठबळ दिले आहे. महाराष्ट्रातील ताजी आकडेवारी पाहता कारागृहांमध्ये मंजूर क्षमतेपेक्षा सुमारे ४७ टक्के अतिरिक्त कैदी आहेत आणि एकूण कैद्यांपैकी ८३.३ टक्के कच्चे कैदी आहेत. त्यामुळे क्षमता वाढविण्याबरोबरच पात्र न्यायप्रविष्ट प्रकरणांचा नियमित आढावा, कायदेशीर मदत आणि उपलब्ध कायदेशीर तरतुदींची प्रभावी अंमलबजावणी हेही कारागृहांवरील ताण कमी करण्यासाठी महत्त्वाचे ठरते.

संपादकीय

ही तर दरोडेखोरांची समृद्धी !

वेगवान, सुरक्षित आणि नियंत्रित प्रवासाचे स्वप्न दाखवत उभारण्यात आलेल्या समृद्धी महामार्गावर प्रवाशांची लूटमार आणि त्यातून दरोडेखोरांची दहशत निर्माण होत असेल, तर हजारो कोटी रुपये खर्चून राज्यात उभारलेल्या या सर्वांत महत्त्वाकांक्षी महामार्गाच्या सुरक्षा व्यवस्थेचेच ते वस्त्रहरण ठरते. या महामार्गावर गुरुवारी रात्री घडलेल्या अशा तीन घटनांचे तपशील हादरवून टाकणारे आहेत. एका घटनेत महामार्गावर धारदार वस्तू टाकत गाडीचे चाक पंक्चर करण्यात आले आणि नंतर त्यातील कुटुंबीयांना मारहाण करून १८ लाखांचा ऐवज लुटण्यात आला; दुसऱ्या घटनेत कारचा पाठलाग करत रस्त्यात गाडी अडवण्यात आली आणि उद्योजकाच्या गळ्यातील सोनसाखळी हिसकावत मारहाण करण्यात आली, तर तिसऱ्या घटनेत रुग्णाला मुंबईला उपचारासाठी घेऊन जात असलेल्या सहप्रवाशांना मारहाण करत दागिने आणि रोकड लुटण्यात आली. ज्या पद्धतीने हे सारे घडले, ते गंभीर आहे. रस्त्यावर धारदार आणि टोकदार वस्तू टाकून टायर पंक्चर करायचे आणि गाडी थांबताच दबा धरून बसलेल्या टोळीने हल्ला करायचा ही 'मोडस ऑपरेंडी' सर्वाधिक घातक आहे. या महामार्गावर लहान वाहने ताशी शंभर ते एकशेवीस किलोमीटरच्या वेगाने धावतात. अशा वेगात टायर अचानक पंक्चर अथवा फुटल्यास वाहन सुरक्षितपणे थांबेलच असे नाही. चालकाचे नियंत्रण सुटून वाहन उलटू शकते, दुभाजकावर आदळू शकते किंवा मागून येणाऱ्या वाहनांच्या साखळी अपघातासारखे जीवघेणे प्रकार घडू शकतात. लूटमारीसाठी केलेले हे कृत्य अनेक निष्पाप प्रवाशांच्या जिवावरही उठू शकते. उद्या त्यातून एखादे कुटुंब उद्ध्वस्त झाले, तर त्याला 'अपघात' कसे म्हणायचे? म्हणून हा तपास केवळ दरोड्याच्या कलमांपुरता मर्यादित राहता कामा नये. वाहनचालकांच्या जिवाला हेतुपुरस्सर धोका निर्माण करण्याच्या अंगानेही कारवाई झाली पाहिजे. शिवाय 'समृद्धी' हा गावाशेजारचा खुला रस्ता नाही. तो 'ॲक्सेस कंट्रोल' महामार्ग आहे. ठरावीक प्रवेश आणि निर्गमन मार्ग, पथकर नाके, सीसीटीव्ही, नियंत्रण कक्ष, महामार्ग पोलिस, गस्ती वाहने आणि आपत्कालीन मदतव्यवस्था ही त्याची वैशिष्ट्ये असल्याचे उच्चरवाने सांगितले जाते. मग दहा-बारा जणांची टोळी महामार्गावर पोहोचते, दबा धरून बसते, वाहने थांबवते, प्रवाशांना मारहाण करत लूट करते आणि नंतर लाखोंच्या मालासह बिनदिक्कत पोबाराही करते, हे कसे? महामार्गाच्या कुंपणांना भगदाडे आहेत का? अनधिकृत प्रवेशमार्ग तयार झाले आहेत का? परिसरातील काही टोळ्यांनी महामार्गालगत अड्डे उभे केले आहेत का? की 'ॲक्सेस कंट्रोल' हा केवळ पथकर वसुलीपुरता असून गुन्हेगारांसाठी मात्र महामार्गाचे दरवाजे सताड उघडे आहेत? लुटारूंचा असा धुमाकूळ सुरू असताना महामार्ग पोलिस आणि संबंधित यंत्रणांना त्याची साधी कुणकुणही कशी लागत नाही? गस्ती वाहने नेमकी कुठे होती? घटना घडल्यानंतर नियंत्रण कक्षाला किती वेळात माहिती मिळाली? पुढील-मागील टोलनाके सतर्क करण्यात आले का? सीसीटीव्ही चित्रण तातडीने तपासले का? संशयित वाहने, मोबाइल लोकेशन आणि फास्टॅगच्या नोंदी यांचा माग काढला का? आज वाहन क्रमांक ओळखणारे कॅमेरे, डिजिटल टोल नोंदी, मोबाइल नेटवर्क आणि क्षणात संदेश पोहोचविणारी संपर्कयंत्रणा उपलब्ध आहे. एवढे तंत्रज्ञान हाताशी असूनही दरोडेखोर सहज पसार होत असतील, तर यंत्रणा कशी सुस्त आणि बेभरवशी आहे तेच ठळकपणे अधोरेखित होते. प्रशासनाने या प्रश्नांची उत्तरे दिली पाहिजेत. समृद्धी महामार्गावरील दरोड्याची ही पहिली घटना नाही. मार्चमध्येही सिन्नर परिसरात एका कुटुंबाला शस्त्रांचा धाक दाखवून लुटण्यात आले होते. कालांतराने त्यातील संशयितांना नाशिक ग्रामीण व ठाणे ग्रामीण पोलिसांच्या संयुक्त कारवाईत पकडण्यात आले. म्हणजेच धोका यंत्रणेला ठाऊक होता. तरीही त्याच पट्ट्यात पुन्हा घटना घडत असतील, तर आधीच्या गुन्ह्यातून कोणताही धडा घेतला गेला नाही, असेच म्हणावे लागेल. या संपूर्ण महामार्गाचे सुरक्षा ऑडिट, कुंपण व अनधिकृत प्रवेशमार्गांची तपासणी, रात्रीची अधिक कार्यक्षम गस्त, ठराविक अंतरावर मदत पथके आणि नियंत्रण कक्षाला उत्तरदायी करणारी प्रतिसादमर्यादा निश्चित करावी लागेल. 'ॲक्सेस कंट्रोल' ही पाटीवरील जाहिरात नाही; ती प्रवाशांच्या जिवाची सरकारी हमी आहे. ती देता येत नसेल, तर पथकर वसूल करण्याचा नैतिक अधिकारही यंत्रणेला उरत नाही. दरोडेखोरांना मोकळे रान आणि प्रवाशांसाठी जीवघेणा सापळा असा प्रकार सुरू राहिला तर या महामार्गाला कोणत्या अर्थाने 'समृद्धी' म्हणावे?

चीनच्या 'वॉटर बॉम्ब'चा सामना भारत कसा करणार ?

नेपाळमध्ये हिमस्खलनामुळे माजलेला भीषण हाहाकार आपण अनुभवला. चीनने बांधलेले महाकाय धरण कधी नैसर्गिक कारणांनी फुटले तर काय ?

डॉ. विजय दर्डा
चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड, लोकमत समूह

नेपाळमध्ये आलेल्या संकटात आप्तांचे जीव गमावलेल्या आणि उद्ध्वस्त झालेल्या कुटुंबांबद्दल प्रत्येकाच्या मनात सहवेदना असेल. मन व्यथित आहे. हृदय सद्गदित आहे. या संकटाने केलेल्या नुकसानातून नेपाळ कधी आणि कसा बाहेर पडेल, याचा अंदाज करणेही मुश्कील आहे.

नेपाळचा एक अख्खा भूप्रदेश पाण्याच्या अजस्त्र लाटेने शब्दशः गिळंकृत करावा, असे तिबेटमध्ये नेमके काय घडले? हिमनदीचा मोठाच्या मोठा कडा तुटल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे तयार झालेल्या सरोवरात अचानक बेहिशेबी पाणी आले. नैसर्गिक बांध फुटले आणि नेपाळमध्ये हाहाकार माजला. भूकंपाच्या धक्क्यांमुळे हे झाले असेही सांगितले गेले; परंतु अमेरिकन भूगर्भशास्त्रीय सर्वेक्षणामध्ये भूकंपाचे पुरावे नोंदले गेलेले नाहीत. याचा अर्थ, हा अनर्थ केवळ हिमस्खलनामुळे ओढवला का?

जे काही घडले, ते चीनच्या कब्जातील तिबेटमध्ये. चीन तंत्रज्ञानाच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत सक्षम देश आहे. हिमालयाच्या या अत्यंत दुर्गम अशा प्रदेशात नैसर्गिक उलथापालथी नेहमीच होत असतात. या संपूर्ण प्रदेशावर चीनची अवकाशातून नजर असणार हे नक्की. एखादे नैसर्गिक सरोवर फुटणार असते तेव्हा त्याचेही संकेत आधी मिळतात. चीनला असे संकेत मिळाले असू शकतील. मात्र, चीनने नेपाळला त्याची कल्पना दिली नाही. असे का, यावर प्रश्न उपस्थित झाले, तेव्हा चीनने या शक्यतेचा साफ इन्कार केला.

चीनच्या उपग्रहाने काही बदल नोंदवले होते किंवा नाही, याविषयी मात्र चीनने अवाक्षर काढलेले नाही. नेपाळ उघडपणे बोलत नाही. परंतु, 'जलसंकट तिबेटमधून आले, त्यामुळे त्यावर लक्ष ठेवता आले नाही' असे म्हणून अधिकाऱ्यांनी अप्रत्यक्षपणे चीनकडे बोट दाखवले आहे.

या पार्श्वभूमीवर मला एक चिंता सतावते आहे. तिबेटमध्ये उभ्या राहत असलेल्या जगातील सर्वांत मोठ्या धरणाची भिंत फुटली, तर काय होईल? हे धरण बांधले जात आहे, अशी माहिती गतवर्षी मिळाली तेव्हाही मी या विषयावर लिहिले होते. आता पुन्हा तोच प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

भारतीय सीमेपासून या धरणाचे अंतर केवळ ३० ते ४० किलोमीटर आहे. आपण जीला ब्रह्मपुत्रा म्हणतो त्याच नदीवरल्या धरणात किती पाणी जमेल हे चीनने अजून सांगितलेले नाही. परंतु, तज्ज्ञांचा अंदाज कित्येक कोटी क्यूसेकचा आहे. समजा, कधी हे धरण फुटले, तर काय होईल? चीनने जाणूनबुजून भारतीय प्रदेशात पाणी सोडले तर काय होईल? - आपण भारतीय सत्शील असल्याने अशा शंका सार्वजनिक चर्चेत येत नाहीत.

हे धरण अत्यंत संवेदनशील अशा हिमालयीन प्रदेशात आहे, जेथे भूगर्भीय हालचाली होत राहतात. जानेवारी २०२५मध्ये येथे ७.१ रिश्टर स्केलचा भूकंप झाला होता. अशा एखाद्या भूकंपाच्या धक्क्याने कोट्यवधी क्यूसेक पाणी भरलेल्या धरणाची भिंत फुटली तर केवळ अरुणाचल प्रदेशातच नव्हे, तर आसामसह पूर्वेकडच्या इतर राज्यांमध्ये आणि बांगलादेशपर्यंत हानी पोहोचेल. बांगलादेशनेही या प्रकल्पाविषयी चीनकडे चिंता व्यक्त केली आहे. ब्रह्मपुत्रा भारतात प्रवेश करते, त्या ठिकाणी हे धरण उभे राहत असून, नदी तेथून हजारो फूट खाली येते. चीनने अजूनपर्यंत या धरणाविषयीचे आकडे गुप्त ठेवले आहेत. या धरणाचा आराखडा काय आहे, भारत-बांगलादेशात त्यामुळे काय परिणाम होतील, हेही कोणाला ठाऊक नाही.

नदीचा प्रवाह किंवा त्यापासून उत्पन्न होणाऱ्या संकटांच्या बाबतीत त्या-त्या वेळी माहितीच्या आदान-प्रदानाचा कोणताही समझोता भारत आणि चीनमध्ये झालेला नाही. चीन आपल्याला माहिती देणार नाही. परंतु, एक दिलासा देणारी बातमी अशी की, चीनकडून येणाऱ्या पाण्याचा प्रवाह नियंत्रित करण्यासाठी भारत अरुणाचल प्रदेशमध्ये अकरा हजार मीटर क्षमतेचा अपर सियांग प्रकल्प उभा करतो आहे. अर्थात, चीनने पाणी अडवले तर काय? हीसुद्धा दुसरी चिंता आहे.

वर्तमान जगात मैत्रीशिवाय दुसरा पर्याय असू शकत नाही. कोणताही शक्तिशाली देश कोणत्याही छोट्या देशाला दडपून टाकू शकत नाही. अमेरिका-इराण युद्धाच्या बाबतीतही आपण हे पाहत आहोत. अजस्त्र ताकद कमावलेला चीन कधी अरुणाचल प्रदेश, कधी डोकलाम, तर कधी लडाखमध्ये खोडी काढत असतोच. परंतु, चीनला दोष न देता भारताला इतके सक्षम व्हावे लागेल, की कुणी आपला केसही वाकडा करू शकणार नाही.

जयशंकर रशियात, डोबाल चीनमध्ये

गत सप्ताहात परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर रशियाला, तर राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोबाल चीनमध्ये पोहोचले. या दोन्ही दौऱ्यांना १२-१३ सप्टेंबरला दिल्लीत आयोजित करण्यात आलेल्या ब्रिक्स संमेलनाचा संदर्भ होता. जयशंकर यांनी थेट पुतिन यांच्याशी संवाद साधला आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा एक व्यक्तिगत संदेशही त्यांना दिला. ब्रिक्ससाठी पुतिन आणि शी जिनपिंग हे दोघेही दिल्लीत येण्याची शक्यता आहे.

गतवर्षी सप्टेंबरमध्ये शांघाय सहयोग संघटनेच्या बैठकीत चीनच्या तियानजीन शहरातून आलेल्या नरेंद्र मोदी, पुतिन आणि शी जिनपिंग यांच्या एकत्रित छायाचित्राने अमेरिकेचा तिळपापड केला होता. आता दिल्लीत पुन्हा संधी आहे!

vijaydarda@lokmat.com
डॉ. विजय दर्डा यांचे समग्र लेखन वाचण्यासाठी स्कॅन करा :

अन्वयार्थ

दुधातल्या भेसळीला चाप, ही नव्या दिशेने जाण्याची संधी !

भेसळमुक्त दूध अभियानामुळे शास्त्रीय व शाश्वत पशुपालनाला चालना मिळेल, नफा गुणवत्तेशी जोडला जाऊन दुग्ध व्यवसायाला नवीन दिशाही मिळू शकेल.

डॉ. व्यंकटराव घोरपडे
सेवानिवृत्त सहायक आयुक्त, पशुसंवर्धन, सांगली

'शुद्ध पनीरला येणार अच्छे दिन', 'एफडीएचा दणका, बनावट दुधाला चाप, दुभती जनावरे झाली महाग', 'गुणवत्तापूर्ण दूध उत्पादनावर भर' अशा एक ना अनेक संबंधित शीर्षकांच्या बातम्या अलीकडे वाचायला मिळू लागल्या आहेत. कारण आहे अन्न आणि औषध प्रशासनाच्या (एफडीए) आयुक्तांनी सुरू केलेले भेसळमुक्त दूध अभियान!

सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून हे अभियान यापूर्वीच सुरू व्हायला हवे होते. कडक निर्बंध, धाडी आणि नियमित तपासण्या सुरू झाल्यामुळे भेसळयुक्त दूध, कृत्रिम दूध बाजारात येणे कमी झाले. पण पूर्णपणे बंद झाले असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. ग्राहकांना शुद्ध दूध मिळणे, भेसळमुक्त दूध मिळणे, हा त्यांचा अधिकार आहे.

दूध उत्पादक पशुपालकांना या दिवसांमध्ये मागील वर्षाच्या तुलनेत मिळणारा दोन ते चार रुपये जादा दर हा या अभियानाचा परिणाम आहे. सहकारी दूध संघाकडील दुधाची मागणीदेखील वाढताना दिसत आहे. पनीर, तूप, चीज यांसारख्या दुग्धजन्य पदार्थांची गुणवत्ता सुधारून त्यांची बाजारपेठ विस्तारताना दिसत आहे. पशुपालक चांगल्या जातीच्या गायी-म्हशींमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी पुढाकार घेतील. संतुलित आहार, वैरण, पशुखाद्य यामध्ये विशेष गुंतवणूक करण्यासाठी अनेक उत्पादक उद्योजक पुढाकार घेतील यात शंका नाही. एकंदरीत शास्त्रीय व शाश्वत पशुपालनाला चालना मिळून नफा गुणवत्तेशी जोडला जाऊन दुग्ध व्यवसायाला नवीन दिशा मिळू शकते.

पशुसंवर्धन विभाग पूर्वीपासूनच उच्च वंशावळीच्या गायी-म्हशी पैदाससाठी भ्रूणप्रत्यारोपण, आयव्हीएफ, लिंग वर्गीकृत रेत मात्रा यांसह निरनिराळ्या योजना मोठ्या प्रमाणामध्ये आखत आहेत. नियमित लसीकरण, पशुपालकांचे प्रबोधन आणि पशुपालकांचा व्यावसायिक दृष्टिकोन यामुळे राज्यात पशुधन आजारी पडण्याचे व दूध उत्पादन घटण्याचे प्रमाण खूप कमी झाले आहे. तुकाराम मुंढे पशुसंवर्धन सचिव असताना त्यांनी भारतीय पशुवैद्यकीय परिषद अधिनियम १९८४ अन्वये खात्याची पुनर्रचना करून राज्यातील सर्व दवाखान्यांचे प्रमुख हे पशुवैद्यकीय पदवीधर राहतील, याची तजवीज केली. त्याप्रमाणे कार्यवाहीदेखील सुरू झाली आहे. पशुधनाच्या लसीकरणासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभी करून पदवीधर पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांना लसीकरणाच्या जबाबदारीतून मुक्त करून त्यांना दुग्ध व दुग्धजन्य पदार्थांच्या गुणवत्ता नियंत्रणासाठी काही अधिकार प्रदान केले तर सध्याच्या मोहिमेस बळकटी मिळेल.

दुग्ध व्यवसाय विभाग हा पशुसंवर्धन विभागात विलीन करण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी बाकी आहे. तसे झाल्यास उपलब्ध अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून एफडीएमध्ये कमी असणाऱ्या मनुष्यबळावरदेखील तोडगा निघू शकतो. एफडीएकडे सध्या नमुने तपासण्यासाठी फक्त तीनच प्रयोगशाळा आहेत. मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या, तर पशुसंवर्धन विभागाच्या रोग अन्वेषण प्रयोगशाळांचादेखील नमुने तपासणीसाठी वापर चांगल्या पद्धतीने करून घेता येईल.

पशुसंवर्धन विभाग हा फक्त दूध उत्पादनाशी निगडित नाही. इतरही अनेक बाबी पशुसंवर्धन विभागाच्या अखत्यारीत येतात. त्यामध्ये अंडी, मांस उत्पादन त्यासाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधा, संगोपन, आरोग्य व्यवस्थापन हेदेखील पशुसंवर्धन विभाग हाताळत असतो. अनेकवेळा कुक्कुटपालनात वापरण्यात येणारी औषधे, लसी, संप्रेरके, प्रतिजैविके याबाबत अनेक अफवा पसरल्या जातात किंवा त्यांच्या वापरामध्ये गैरप्रकार होतात. अशा तक्रारींची चौकशी, नियंत्रण पशुवैद्यकीय दवाखान्यांकडे सोपवल्यास अनेक बाबी सुकर होऊ शकतील. लोकांना प्राणिजन्य आजारापासून दूर ठेवण्यात या धोरणाचा उपयोग होऊ शकेल. या सर्व बाबी डोळ्यांसमोर ठेवूनच प्रत्येक जिल्ह्यात उपायुक्त पशुसंवर्धन व दुग्धविकास यांच्या अधिनस्त सहायक आयुक्त पशुसंवर्धन (गुण नियंत्रण व नियमन) या पदाची निर्मिती केली गेली आहे. या व इतर पदांना योग्य अधिकार प्रदान करून त्याची अंमलबजावणी केली तर दुधासह इतर सर्व प्राणिजन्य उत्पादनेदेखील भेसळमुक्त आणि गुणवत्तापूर्ण मिळतील. सोबत पशुपालक आणि संबंधितांच्या उत्पन्नातदेखील वाढ होऊ शकेल. त्यासाठी गरज आहे ती सर्व संबंधितांच्या इच्छाशक्तीची आणि दूरदृष्टीची.

vyankatrao.ghorpade@gmail.com

जगभर

कुदळ, फावडं घेऊन लोक सोन्याच्या शोधात...

केनियातील चेपोरोर हे एक अतिशय दुर्गम गाव. तेथीलच मानसे लोमाचार हा ३३ वर्षीय मेंढपाळ. शेळ्या चरत असताना काही दिवसांपूर्वी त्याला तेथील दुर्गम भागात जवळपास तीन ग्रॅम सोनं सापडलं. सोनं सापडताच त्याचे डोळे चमकले. त्या परिसरात आणखी 'शोध' घेतला आणि 'खोदकाम' केलं तर आणखी बरंच सोनं सापडेल असं त्याला वाटलं..

पण त्याआधी त्यानं हे सोनं ३६ हजार केन्याई शिलिंग, म्हणजेच सुमारे २८० डॉलरमध्ये विकलं. एव्हाना या बातमीची कर्णोपकर्णी इतकी चर्चा झाली की आसपासची गावंच्या गावं कुदळ-फावडी घेऊन चेपोरोरकडे धावली! गेल्या काही दिवसांपासून अक्षरशः हजारो लोक सोन्याच्या शोधात या भागात दाखल झाले आहेत.

कधीकाळी झुडपं आणि चराऊ जमीन असणाऱ्या या परिसराचं चित्र आता बदललंय. जागोजागी मातीचे ढिगारे आणि मोठमोठे खड्डे दिसत आहेत. स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या अंदाजानुसार, एका टप्प्यावर या गावात तब्बल १० हजार लोक सोन्याच्या शोधासाठी आले होते.

वेस्ट पोकोट काउंटीचे डेप्युटी कमिशनर सॅम्युअल कियारी यांच्या म्हणण्यानुसार, दोन मोठ्या सोन्याच्या शोधांनंतर या भागात गर्दी वाढली. काही तरुणांना मोठ्या प्रमाणात सोनं सापडलं आणि त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी काही महिलांनाही त्याच परिसरात सोनं मिळालं.

मानसे लोमाचार या मेंढपाळाला मिळालेलं सोनं मात्र निव्वळ योगायोग होता. हरवलेली शेळी शोधत असताना त्याची भेट नदीकाठी सोनं शोधणाऱ्या काही महिलांशी झाली. तोही त्यांच्यात सहभागी झाला आणि त्यातूनच या परिसरात सोनं असल्याचं त्याच्या लक्षात आलं.

या शोधानं अनेकांच्या मनात नवी आशा निर्माण केली आहे. शेतीतून मिळणाऱ्या अनिश्चित उत्पन्नावर

गुजराण करणाऱ्या कुटुंबांसाठी सोन्याचा एखादा छोटासा तुकडाही मोठा आधार ठरू शकतो.

मुलांच्या शाळेची फी भरता यावी आणि आपल्या लहान भावंडांचं शिक्षण सुरू ठेवता यावं, यासाठीही अनेक जण इथे सोनं शोधत आहेत. शेकडो लोक एकत्र काम करत असून, कुदळ आणि फावड्यांनी खडकाळ जमीन खोदली जात आहे. काही जण माती नदीकाठी नेतात. तिथं अनेक महिला गढूळ पाण्यात बसून माती चाळतात. या मातीमध्ये सोन्याचा एखादा छोटासा कण सापडेल, अशी त्यांना अजूनही आशा आहे. अनुभवी कामगार खोल खड्ड्यांमध्ये उतरून माती खोदतात आणि दगड फोडतात.

सोन्याच्या या शोधामुळे गावात आर्थिक हालचालीही वाढल्या आहेत. स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या मते, परिसरात २०० हून अधिक दुकानं आणि छोटे व्यवसाय सुरू झाले आहेत. बाहेरून आलेल्या लोकांना पाणी, अन्न, ब्रेड, दूध आणि इतर आवश्यक वस्तू विकून काहीजण कमाई करत आहेत. सोन्याच्या या आशावादी चित्रामागे मात्र अनेक गंभीर समस्या आहेत. परिसरात स्वच्छ पिण्याचं पाणी नाही. आंघोळीसाठीही पुरेसं पाणी उपलब्ध नाही. नळाद्वारे पाणीपुरवठा आणि स्वच्छतागृहांची सुविधाही मर्यादित आहे.

जंगल आणि डोंगराळ भागात अचानक हजारो लोक आल्यामुळे स्थानिक यंत्रणेवर मोठा ताण निर्माण झाला आहे. परिसरात बहुतांश लोक पुरुष असल्यामुळे लैंगिक हिंसाचाराची भीतीही व्यक्त केली जात आहे. चेपोरोरची ही सोन्याची शर्यत त्यामुळे केवळ सोन्याच्या शोधाची कहाणी राहिलेली नाही. आर्थिक अडचणींशी झुंजणाऱ्या हजारो लोकांच्या आशेची ती कहाणी बनली आहे.

करनीती

आजच रिटर्न भरा, उद्या दंड भरावा लागेल !

अर्जुन (काल्पनिक पात्र): कृष्णा, आज ३१ ऑगस्ट आहे. ऑफिसमध्ये गर्दी आहे, पोर्टल स्लो आहे आणि प्रत्येक व्यापारी फाइल घेऊन धावताना दिसतोय. या एका दिवसामुळे एवढी धावपळ का?

कृष्ण (काल्पनिक पात्र): अर्जुना, ३१ ऑगस्ट २०२६ ही आयटीआर भरण्याची अंतिम तारीख आहे. ही तारीख टॅक्स ऑडिट लागू नसलेल्या करदात्यांसाठी, तसेच आयटीआर-३, आयटीआर-४ आणि आयटीआर-५ भरणाऱ्यांसाठी आहे.

अर्जुन : आयटीआर दाखल करण्यापूर्वी करदात्याने काय तपासले पाहिजे?

कृष्ण : १. व्याज, लाभांश, शेअर्स व म्युच्युअल फंडांची विक्री, मालमत्तेचे व्यवहार तसेच TDS/TCS ची माहिती रिटर्नशी जुळते आहे का, हे तपासा.

२. GSTR-१ आणि GSTR-3B मधील वर्षभराची उलाढाल आणि आयटीआरमधील उलाढाल जुळते आहे का, हे तपासा. दोन्हीमध्ये मोठी तफावत असल्यास ती विभागाच्या तपासणीत येऊ शकते.

३. रिटर्न भरताना कर भरायचा बाकी असेल, तर तो कर आणि लागू असल्यास व्याज आधी भरावे. त्यानंतर चलनाची माहिती रिटर्नमध्ये भरावी. कर बाकी ठेवून रिटर्न भरल्यास तो त्रुटीयुक्त ठरू शकतो.

४. नवीन कर पद्धत ही आपोआप लागू होते. ज्या करदात्याला व्यवसाय किंवा व्यावसायिक उत्पन्न आहे आणि जुनी कर पद्धत निवडायची आहे, त्याने फॉर्म १०-IEA अंतिम तारखेपूर्वी भरला पाहिजे. अंतिम तारीख निघून गेल्यानंतर त्या वर्षासाठी जुनी कर पद्धत निवडता येणार नाही.

- **उमेश शर्मा,** चार्टर्ड अकाउंटंट

समकालीन महत्त्वाचे मुद्दे मांडणारी, नवी चर्चा सुरू करणारी वाचक-पत्रे या स्तंभामध्ये प्रसिद्ध केली जातील. आपली पत्रे येथे पाठवा : **janman@lokmat.com**

जेन झी

माझ्या कष्टांचं चिज होत नाही ना, मग मी प्रयत्नच सोडतो...

मोठ्या गोष्टी करता येत नसल्यानं मग आज 'छोटीशी खुशी' म्हणून एखादी कॉफी किंवा पेस्ट्री विकत घेऊ, अशी अनेकांची वृत्ती पाहायला मिळते.

राही श्रु. ग.
सिनिअर रिसर्च फेलो
जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ

"**तुम्ही** जितकं कमी खाता-पिता, जितकी कमी पुस्तकं विकत घेता, जितकी नाटकं कमी पाहता आणि जितका कमी विचार करता, प्रेम करता, गाता, रंगकाम करता तितकी तुम्हाला जास्त बचत करता येईल आणि तुमचा खजिना मोठा मोठा होत जातो. या तुमच्या साठ्याला ना कधी वाळवी लागेल, ना त्याला आगीची भीती राहील. तुम्ही जितके 'कमी' होत जाल, स्वतःला जितकं कमी व्यक्त कराल, तितका तुमचा साठा वाढत जाईल. तितकी तुमची परात्मता वाढत जाईल आणि हा तुमचा दुरावलेपणा अभेद्य होत जाईल."

- **कार्ल मार्क्स,** १८४४

सतत खर्च करत राहणं, वस्तू विकत घेत राहणं याला आपण चंगळवाद आणि भांडवलशाहीचं मूळ मानतो. मात्र ज्यांच्या हातात भरपूर पैसा आहे, तो केवळ बचत म्हणून, गुंतवणुकींमध्ये साठत साठत त्याचं 'भांडवल' होत राहत असेल तर? मार्क्स म्हणतो, यांत्रिकपणे पैसा कमावणं आणि मग तो गुंतवत राहणं हीदेखील माणसाला परात्मतेकडे ढकलणारी यंत्रणा आहे. आपला भवताल, आपल्या आजूबाजूचे लोक, आपल्यासोबत काम करणारे लोक, आपले कष्ट आणि त्यातून होणारी निर्मिती अशा साऱ्यापासून माणसाने दुरावणं, याला कार्ल मार्क्सने 'परात्मता' असं नाव दिलं.

जागतिकीकरण, खासगीकरण आणि नवउदारमतवादामुळे ज्यांच्यापर्यंत आपले हात पोहोचू शकतात अशा वस्तूंचा जणू पूर आला. बाजार दुथडी भरून वाहू लागले आणि खर्चासाठी खिशात १ रुपया

असो किंवा १०००, सर्वांसाठी चकचकीत वस्तूंचे पर्याय गल्लीगल्लीतल्या किराणा दुकानांमध्ये दिसू लागले. १-२ रुपयांची शॅम्पूची पाकिटं, ५-१० रुपयांची फेस क्रीम, ५-१० रुपयांची वेफर्सची पाकिटं बाजारात आली तशा प्रत्येक घराबाहेरच्या कचरापेट्या रंगीबेरंगी प्लॅस्टिकच्या वेष्टनांनी भरून जाऊ लागल्या. याचा पर्यावरणीय अर्थव्यवस्थेवरचा परिणाम याची स्वतंत्र चर्चा होऊ शकते. मात्र जगभरातल्या जेन झींच्या अस्थैर्यामुळे सध्या चर्चेत आहे, 'लिटिल ट्रीट इकॉनॉमी'.

कायम पगारी नोकऱ्यांचा अभाव असताना, स्थिर रोजगार नसताना गुंतवणुकींच्या बाबतीतली आधीच्या पिढ्यांची ध्येयं जेन झींना पेलवणार नाहीत, असं बहुतेकांनी स्वीकारलं आहे. आपण कधीच घर विकत घेऊ शकणार नाही, मग आज 'छोटीसी खुशी' म्हणून एखादी कॉफी किंवा पेस्ट्री विकत घेऊ, अशी अनेकांची वृत्ती पाहायला मिळते.

ली आणि यू यांच्या यावरच्या पेपरचं नावच 'गिव्हिंग अप' आहे. या लिटिल ट्रीट अर्थशास्त्राच्या मुळाशी कुठेतरी हा हार मानण्याचा विचार दिसतो. आपल्या कष्टांना योग्य असा मोबदला मिळत नाही, हे सतत दिसत राहतं, तेव्हा जेन झींमधला एक मोठा वर्ग शांतपणे प्रयत्न सोडून देतो. या 'लिटिल ट्रीट' वास्तवात धोकाही आहे. प्रत्येक छोट्या मेजवानीने मिळणारा तात्कालिक आनंद जेन झीला व्यवस्थात्मक अस्थैर्याला आव्हान देण्याऐवजी ते स्वीकारण्याचं कण कण बळ देत राहू शकतो. या भूमिगत अस्थैर्यावरचे उपाय बाजारकेंद्रित असण्याची गरज नाही, ते कदाचित गाणी म्हणण्यात, चित्र रंगवण्यात आणि मित्रांबरोबर गप्पा मारतानादेखील सापडतील.

raheeshrutiganesh@gmail.com

तिरकस आणि चौकस — गजानन घोंगडे

हे पत्र लोकमत मीडिया प्रा. लिमिटेडच्या वतीने मुद्रक व प्रकाशक **बालाजी मुळे** यांनी प्लॉट नं. ए - ८१८ इंडस्ट्रियल एरिया, एम.आय.डी.सी., महापे, नवी मुंबई येथे मुद्रित करून 'लोकमत', पृथ्वी पार्क, सेक्टर ३०, सानपाडा, नवी मुंबई कार्यालय - ४००७०५ येथून प्रसिद्ध केले. ● दूरध्वनी क्र : ०२२ ४६०४१७८४
● **मुंबई कार्यालय :** लोकमत मीडिया प्रा. लिमिटेड, तिसरा मजला, पारिजात हाउस, प्लॉट नं. १०७६, आपटे इंडस्ट्रियल इस्टेट, लक्ष्मीनरसिंग पपन मार्ग, डॉ. ई मोझेस रोडसमोर, गांधीनगर, वरळी, मुंबई, ४०००१८. ● दूरध्वनी क्र : ०२२- ४६०३५९३०, ०२२- ४७५०७९४६ ● **ठाणे कार्यालय :** वेस्टर्न व्ह्यू, श्री गजानन महाराज चौक, वारकरी भवनाजवळ, ठाणे,
फोन : २५४४११०५, २५३८१७७४ ● **नवी मुंबई कार्यालय :** पृथ्वी पार्क, सेक्टर ३०, सानपाडा, नवी मुंबई ४००७०५. फोन : ०२२ ४६०४१७८४ ● संस्थापक संपादक : **स्व. जवाहरलाल दर्डा** ● मानद संपादिका : **श्रीमती उषाताई दर्डा** ● चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड : **डॉ. विजय दर्डा** ● एडिटर इन चिफ : **राजेंद्र दर्डा** ● समूह संपादक : **विजय बाविस्कर**
● संपादक : **अतुल कुलकर्णी*** (*पी. आर. बी. कायद्यानुसार संपादकीय जबाबदारी यांची आहे.) 'लोकमत'मधील लेखांचे हक्क राखून ठेवले आहेत. लोकमत ® हे चिन्ह लोकमत मीडिया प्रायव्हेट लि. चे. व्यापारचिन्ह आहे.

इमरान से सुलूक

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और भूतपूर्व क्रिकेट कप्तान इमरान खान के साथ उनके मुल्क का निजाम वही सुलूक कर रहा है, जो वह अपने रहनुमाओं और अजीम हस्तियों के साथ हमेशा से करता आया है। हालांकि, इमरान के साथ मानवीय व्यवहार करने और उन्हें उचित इलाज मुहैया कराने की विश्व के दिग्गज पूर्व कप्तानों की अपील को अनसुना करना शहबाज शरीफ सरकार के लिए मुश्किल होता जा रहा है। परिजनों के आरोप हैं कि इमरान की आंखों की रोशनी खत्म होती जा रही है और हुकूमत उन्हें सही इलाज कराने की सुविधा नहीं दे रही। ऐसे में, पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स में खेले जा रहे टेस्ट मैच के दौरान इमरान के बेटों के जो इंटरव्यू प्रसारित हुए, उसने करोड़ों पाकिस्तानियों तक अपनी पहुंच बनाई है और अब पूर्व कप्तान जावेद मियांदाद ने जिस तरह से एक पॉडकास्ट में हुकूमत से भावुक अपील की है, वह भी शहबाज सरकार के लिए मुसीबत बनने वाली है। इमरान व मियांदाद पाकिस्तानी क्रिकेट के आधार स्तंभ रहे हैं और सियासत से परे उनके लिए आम पाकिस्तानियों के दिल में आज भी आकर्षण है।

इमरान खान की सेहत को लेकर तरह-तरह की खबरें आती रही हैं। इनमें से ज्यादातर सोशल मीडिया की कयासबाजियां होती हैं, पर जिस तरह से दुनिया के 20 से अधिक पूर्व क्रिकेट कप्तानों ने उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई है, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह बात छिपी हुई नहीं है कि उनकी बहनों और पार्टी के आला पदाधिकारियों तक को जेल में आसानी से मिलने नहीं दिया जाता और सामान्य मुलाकात के लिए भी उन्हें अक्सर अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। यह बर्ताव अमानवीय है और इस्लामाबाद को तमाम वैश्विक मंचों पर बचाव के लिए मजबूर करेगा, जहां वह मानवाधिकारों की बात करेगा। यह गौर करने वाली बात है कि इमरान की बहन डॉ उज्मा और उनके निजी डॉक्टर की याचिका पर पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने इसी पखवाड़े यह साफ-साफ कहा था कि इमरान को इस्लामाबाद स्थित शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में भर्ती कराया जाए, मगर जिस तरह से उन्हें किसी अन्य निजी अस्पताल ले जाया गया और दो दिन के भीतर ही बिल्कुल 'सेहतमंद' करार देकर वापस जेल भेज दिया गया, इससे संदेह गहरा गया है।

जब तक पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों का राजनीतिक चरित्र नहीं बदलेगा, तब तक वहां इमरान खानों और शेख हसीनाओं की नियति यही होगी।

पाकिस्तान में न्यायपालिका की जो स्थिति है, उसे देखते हुए उससे किसी निर्णायक हस्तक्षेप की उम्मीद बेमानी है, पर चूंकि इमरान का मामला अंतरराष्ट्रीय सुर्खियां बटोरता है, इसलिए उसके आदेशों की अवहेलना घरेलू तौर पर शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर की स्थिति कमजोर करेगी। यह सभी जानते हैं कि पिछले आम चुनाव में तमाम पाबंदियों के बावजूद इमरान खान समर्थित उम्मीदवारों ने काफी बेहतर प्रदर्शन किया था और फौजी मिलीभगत से ही मौजूदा गठबंधन सत्ता में आ सका। ऐसे में, अगर इमरान खान के पक्ष में घरेलू माहौल बन गया, तो बहुत आश्चर्य नहीं होगा। विडंबना यह है कि जिस इमरान खान से पाकिस्तानियों के साथ-साथ इस उप-महाद्वीप के अमन-पसंद लोगों ने यह उम्मीद लगाई थी कि वह नई किस्म की सियासत करेंगे, जिससे दक्षिण एशिया में साझेदारी का माहौल बनाने में मदद मिलेगी, उन्होंने उसके ठीक उलट आचरण किया। बतौर प्रधानमंत्री उन्होंने भी अपने सियासी विरोधियों से निजी खुन्नस ही निकाली थी। इसलिए जब तक पाकिस्तान, बांग्लादेश का राजनीतिक चरित्र नहीं बदलेगा, वहां इमरान खानों और शेख हसीनाओं की नियति यही होगी।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 31 अगस्त, 1951

उत्तरदायी शासन

सी श्रेणी में दस राज्य हैं। उनमें विंध्य प्रदेश ही इतना बड़ा राज्य है, जिसके पृथक अस्तित्व का कोई औचित्य हो सकता है और जिसके आर्थिक साधन न्यूनाधिक उत्तरदायी शासन प्रणाली का व्यय-भार उठाने में समर्थ हो सकते हैं। राज्यों के एकीकरण के सूत्रधार स्वर्गीय सरदार पटेल ने तो विंध्य प्रदेश को भी उत्तर प्रदेश अथवा मध्य प्रदेश में विलीन करने का विचार किया था, किन्तु संबंधित पक्षों में मतैक्य के अभाव में उन्होंने इस विचार को स्थगित कर दिया था। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच इस बारे में खींचातान थी और खुद विंध्य प्रदेश के भी कुछ लोगों ने उसके विलीनीकरण का विरोध किया था। अतः स्वर्गीय सरदार पटेल ने सारे विवाद को शान्त करने के लिए विंध्य प्रदेश को केन्द्रीय सरकार के शासनाधीन रखना मुनासिब समझा।

भारत के देशी राज्यों के एकीकरण के कार्य को सरकारी प्रवक्ताओं ने सरदार पटेल की चमत्कारिक और महान सफलता घोषित किया था। किन्तु अब उनका ख्याल बदल गया मालूम देता है और अब तक की धारणाओं के विरूद्ध वे यह कह रहे हैं कि छोटे राज्यों में भी व्यय-साध्य उत्तरदायी शासन प्रणाली जारी की जा सकती है। भारत के गृहमंत्री श्री राजगोपालाचार्य ने तो यहां तक कह डाला है कि बड़ी इकाइयों की अपेक्षा छोटी इकाइयों का शासन ज्यादा उत्तमता के साथ चलाया जा सकता है। यदि उनके इस कथन को एकान्तिक सत्य मान लिया जाये तो यह स्वीकार करना होगा कि छोटे-छोटे राज्यों को बड़े राज्यों में विलीन करना एक बड़ी भूल थी और देश के मौजूदा भाग्य विधाताओं को बड़ी शासनिक इकाइयों को पुनः छोटी इकाइयों में विभक्त करके और उनमें अलग-अलग विधान सभाओं और मंत्रिमंडलों की स्थापना करके उसका परिमार्जन कर देना चाहिए। जिन छोटे राज्यों को विलीन किया गया है, उनकी जनता इस परिवर्तन पर संभवतः प्रसन्न ही होगी!

रियासती मंत्री श्री गोपालस्वामी आयंगर ने सी श्रेणी के राज्यों में उत्तरदायी शासन प्रणाली जारी करने के उद्देश्य से संसद के सामने एक विधेयक पेश किया है। सरकार का पहले सी श्रेणी के छोटे राज्यों में विधान सभायें और मंत्रिमण्डल स्थापित करने का विचार नहीं था, किन्तु जब इन राज्यों के प्रतिनिधियों ने दबाव डाला तो उसने अपने पूर्व रुख में परिवर्तन कर लिया।

महिलाओं की मजबूती के खुले कई रास्ते

बैंक खाते से लेकर ड्रोन तक सिर्फ एक दशक में भारतीय महिलाओं ने काफी लंबी यात्रा तय की है। अपने आर्थिक फैसले खुद करने की क्षमता आजादी का नया रूप है।

यहां स्कैन करें

वसुंधरा राजे | पूर्व मुख्यमंत्री, राजस्थान

साल 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने कुछ धार्मिक रस्में निभाई थीं, जैसा कि कोई भी आस्थावान भारतीय करता है। उस समय पवित्र कलश को ले जाने के लिए किसी पुरोहित या महात्मा को चुनना सबसे स्वाभाविक विकल्प होता, लेकिन परंपरा से हटकर मोदी जी ने रवीना जाधव को चुना, जो एक दलित लड़की थी और झुग्गी बस्ती में रहती थी। यह कोई बहुत प्रचलित या दिखावे के लिहाज से किया गया काम नहीं था, बल्कि सही काम था।

नरेंद्र मोदी के लिए महिलाओं की गरिमा और सम्मान, उन्हें सशक्त बनाने की पहली सीढ़ी रही है। महिला सशक्तीकरण उनके लिए कोई दान या एहसान नहीं है। इसका मतलब है, किसी महिला को यह विश्वास दिलाना कि उसे अपनी जिंदगी और अपना भविष्य खुद तय करने का पूरा अधिकार है। इसका मतलब देश-समाज में ऐसा माहौल बनाना है, जहां आत्मविश्वास से भरपूर एक लड़की जागरूक नागरिक बनकर आगे बढ़ सके। मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने गुजरात में कन्या केलवणी योजना शुरू की थी, जिसका उद्देश्य लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना था। वह खुद गांवों में जाते थे और माता-पिता से अपनी बेटियों को स्कूल भेजने की अपील करते थे। समय के साथ अलग-अलग रूप में कई राज्यों, यहां तक कि विरोधी पार्टियों की सरकारों ने भी इस योजना को अपनाया, उनमें थोड़े बदलाव किए और नए नाम दिए। कच्छ में भूकंप के बाद जब पुनर्निर्माण किया गया, तब मोदी ने यह सुनिश्चित किया कि नए बने घर पति और पत्नी, दोनों के नाम पर दर्ज हों।

साल 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके 'विजन' का असली विस्तार सामने आया। उन्होंने महिलाओं के लिए योजनाएं ही शुरू नहीं कीं, बल्कि देश के आर्थिक बदलाव के केंद्र में उन्हें रखा। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत पहली बार देश में करोड़ों महिलाओं के बैंक खाते खुले। आज जन-धन खातों में 56 प्रतिशत खाते महिलाओं के हैं। इसी तरह, मुद्रा योजना के लाभार्थियों में 68 प्रतिशत महिलाएं हैं। इस योजना के तहत लाखों स्त्रियों को बिना किसी गारंटी के कर्ज मिला, जबकि पहले महिलाओं को बैंक के दरवाजे से ही वापस लौटा दिया जाता था।

एक महिला के लिए अपने नाम से बैंक खाता होना और जरूरत पड़ने पर कर्ज की सुविधा होना बहुत बड़ी ताकत है। बिना किसी से अनुमति लिए अपने आर्थिक फैसले खुद करने की क्षमता, आजादी का एक नया रूप है। मैंने इस बदलाव को 8 मार्च, 2018 को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर खुद महसूस किया था। उस दिन प्रधानमंत्री राजस्थान के झुंझुनू आए थे। वहीं से उन्होंने 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान' और देश के प्रमुख पोषण अभियान की भी शुरुआत की। उस कार्यक्रम में मौजूद एक लाख से भी अधिक लोगों की भीड़ में लगभग आधी महिलाएं थीं।

आज नवजात लड़कियों का लिंग अनुपात साल 2014-15 के 918 से बढ़कर 929 हो गया है। वहीं, माध्यमिक स्तर पर लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात 75.51 प्रतिशत से बढ़कर 83.4 प्रतिशत हो गया है। अब बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का ध्यान लड़कियों की स्टेम क्षेत्रों, यानी विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग व गणित में भागीदारी बढ़ाने और उन क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण देने पर भी है, जिनमें परंपरागत रूप से पुरुषों का वर्चस्व रहा है। इससे भी आगे बढ़कर उन्होंने एक ऐसी कल्पना को साकार किया, जिसके बारे में बहुत कम लोगों ने सोचा था- 'नमो ड्रोन दीदी योजना'। इसके तहत देश के 15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों को कृषि ड्रोन दिए गए और गांव की महिलाओं को ड्रोन पायलट और उद्यमी बनाया जा रहा है। बैंक खाते से लेकर ड्रोन तक सिर्फ एक दशक में भारतीय महिलाओं ने काफी लंबी यात्रा तय की है।

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में महिलाओं को सशस्त्र सेनाओं में स्थायी कमीशन मिला। उन्हें राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश मिला और युद्धक भूमिकाओं में भी शामिल किया गया। फाइटर जेट के कॉकपिट से लेकर लोकसभा तक, जो दरवाजे दशकों से बंद थे, अब खुल चुके हैं। उनके नेतृत्व में ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ, जिसमें लोकसभा व राज्य विधानसभाओं की एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान किया गया। यह एक ऐसा कदम है, जिसकी प्रतीक्षा यह गणराज्य आजादी के बाद से ही कर रहा था।

तथ्यों और जबरन बनाए गए राजनीतिक नैरेटिव के बीच का अंतर नजरअंदाज करना मुश्किल है। कुछ नेता माइक्रोफोन के पीछे खड़े होकर पितृ-सत्ता को खत्म करने की बातें लगातार करते हैं, पर उन्हीं की पार्टी की सरकारों में ऐसे मंत्रिमंडल होते थे, जिनमें एक भी महिला नहीं होती थी। विपक्ष के नेता राहुल गांधी महिलाओं के अधिकारों पर भाषण देते हैं, जबकि उनकी अपनी पार्टी की सरकारों में फैसले लेने वाली जगहों पर महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने में मुश्किलें आती रहती हैं।

भारत जैसे देश में प्रतीकों का बहुत महत्व है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के लिए प्रतीकवाद हमेशा वास्तविक उद्देश्य और काम से जुड़ा रहा है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, 2020 पर उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया, जो पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स कुछ समय के लिए सात ऐसी महिलाओं को सौंप दिए, जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्रों में असाधारण काम किया था। आज माध्यमिक स्कूलों में पढ़ाई छोड़ने वाली लड़कियों की दर घटकर महज सात प्रतिशत रह गई है और वे लड़कों की तुलना में कम संख्या में स्कूल छोड़ती हैं। इसी तरह, प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत स्वीकृत घरों में 97 प्रतिशत घर पूरी तरह या संयुक्त रूप से महिलाओं के नाम हैं। ये बदलाव यूं ही नहीं हुए हैं। ये उन पौधों के फल हैं, जिनको वर्षों पहले लगाया गया, लगातार सींचा और संभाला गया है। देश प्रधानमंत्री मोदी को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जानता है, जिन्होंने दशकों पहले स्त्री शक्ति पर तब विश्वास किया, जब बहुत से लोग इसके बारे में सोचते भी न थे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्पष्ट विश्वास है कि भारत तब तक वह राष्ट्र नहीं बन सकता, जैसा वह बनना चाहता है, जब तक कि उसकी महिलाओं को अपनी पूरी क्षमता हासिल करने के लिए अवसर, सम्मान और स्वतंत्रता नहीं दी जाती।

(ये लेखिका के अपने विचार हैं)

मध्यवर्ग को फिर परेशान करने लगी महंगाई

यहां स्कैन करें

आलोक जोशी | वरिष्ठ पत्रकार

सन् 1974 में आई सुपरहिट फिल्म *रोटी कपड़ा और मकान* का एक गाना- *और बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई*, शायद फिल्म से भी ज्यादा हिट हुआ। इसकी यह पंक्ति तब से आज तक किसी न किसी रूप में बार-बार सामने आती ही रहती है। इसकी सबसे बड़ी वजह शायद यही है कि महंगाई आम मध्यवर्गीय इंसान की सबसे बड़ी चिंता बनी हुई है। सबसे ज्यादा चुभने वाली महंगाई होती है आटे-दाल की, पर जब राजनीति हो, तो सबसे ज्यादा बात होती है चीनी और प्याज की। इस वक्त यही दोनों सुर्खियों में दिख रहे हैं। हालांकि, किस्सा पेट्रोल-डीजल से होते हुए सोने-चांदी और तेल तक चला जाता है।

रिजर्व बैंक की नजर से देखें, तो खुदरा महंगाई दर दो से छह प्रतिशत के बीच रहने का मतलब है कि कीमतें बढ़ने की रफ्तार काबू में है या बर्दाश्त के लायक है, मगर यह आंकड़ा पूरी कहानी नहीं कहता। खासकर, आम आदमी की नजर से या घर की रसोई संभालने वाले पुरुष या गृहिणी की नजर से देखने वाली बात यह है कि खाने-पीने की चीजों के दाम किस रफ्तार से बढ़ रहे हैं? इसे ही 'खाद्य मुद्रास्फीति' कहते हैं और संकट के समय इसका आंकड़ा प्रायः महंगाई के सामान्य आंकड़े से काफी ऊपर लहराता दिखता है। अभी, जुलाई में महंगाई का आंकड़ा करीब 4.45 प्रतिशत रहा, जबकि खाने-पीने की महंगाई 5.52 प्रतिशत पर पहुंच चुकी थी। यानी, जब रिजर्व बैंक को महंगाई अच्छी तरह काबू में दिख रही हो, तब भी आपकी रसोई को ऊंचे दामों की तपिश परेशान कर रही हो सकती है।

सरकार के पास अनेक उपाय हैं और उसने उनका इस्तेमाल शुरू भी कर दिया है। सभी जानते हैं कि महंगाई सरकार को महंगी पड़ सकती है।

अर्थव्यवस्था और देश की आर्थिक नीतियां चलाने वालों का यही विरोधाभास अक्सर हमारी जिंदगी पर असर डालता है। पिछले हफ्ते रक्षाबंधन के ठीक पहले दिल्ली के बाजार में प्याज के दाम 70 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए थे। हालांकि, इसके बाद सरकार ने 'कांदा एक्सप्रेस' चलाकर आपूर्ति बढ़ाने का इंतजाम किया, तो दाम आधे होने के आसार दिखने लगे। मराठी में प्याज को 'कांदा' कहा जाता है।

चीनी की कहानी कुछ अलग जरूर है, लेकिन नतीजा वही है। पिछले एक महीने में चीनी के दाम में 15 से 20 प्रतिशत का उछाल आया है। हालांकि, सरकार ने चीनी के दाम काबू में करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। दस लाख टन कच्ची चीनी के ड्यूटी-फ्री आयात को मंजूरी मिल चुकी है। चीनी के व्यापारियों या डीलरों पर 400 टन की स्टॉक सीमा और थोक खरीदारों पर भी पाबंदी लगा दी गई है कि पंद्रह दिन की जरूरत से ज्यादा का स्टॉक न रखें। यही नहीं, चीनी मिलों में गन्ने की पेराई भी अक्तूबर में ही शुरू करवाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि, इस सबका कितना असर होगा, यह कहना बहुत मुश्किल है।

चर्चा और सुर्खियों में प्याज और चीनी आगे रहते हैं, मगर दाम देखेंगे, तो लहसुन, गुड़ और दूसरी सब्जियां भी पीछे नहीं हैं। यही नहीं, दूध, अंडे और मुर्गे जैसी चीजों पर भी महंगाई का असर दिख रहा है। बहुत से विश्लेषक इसे इथेनॉल से जोड़कर देख रहे हैं और लगातार सरकार की इथेनॉल नीति पर सवाल उठा रहे हैं। यह पहली बार नहीं है कि कोई सरकार इस तरह की परिस्थिति का सामना कर रही है। गेहूं, चीनी, प्याज और दूसरे कई उत्पादों के सवाल पर पिछली कई सरकारें कई बार अपने ही फैसलों को उलट चुकी हैं या एकदम उनके विपरीत फैसले ले चुकी हैं। खासकर, 2004 से 2008-09 के बीच, पहले गेहूं, फिर चीनी के निर्यात और बाद में उन्हीं को ऊंचे दाम पर वापस खरीदने के मामले में गंभीर राजनीतिक विवाद खड़े हो चुके हैं।

इधर सोने-चांदी के दाम भी फिर से बढ़ते दिख रहे हैं। त्योहारी मौसम के ठीक पहले यह भी शुभ संकेत नहीं है, पर यह कहानी भारत की कम और दुनिया की ज्यादा है। अमेरिका-ईरान युद्ध की आशंका जब तक बनी रहेगी, तब तक कि सोने के दाम बढ़ने का सिलसिला थमना मुश्किल है। इसमें भारत अलग से कुछ कर नहीं सकता।

जहां तक भारत का सवाल है, तो सरकार के पास अनेक उपाय हैं और उसने उनका इस्तेमाल शुरू भी कर दिया है। सभी समझते हैं कि अब महंगाई का और बढ़ना जनता से ज्यादा सरकार को महंगा पड़ सकता है। राजनीति में ऐसा जोखिम कौन लेना चाहेगा?

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

चाह गई, चिंता मिटी

कबीर कहते हैं, चाह गई, चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। जिनको कछु न चाहिए, वे साहन के साह। बिल्कुल उल्टी बात लगती है; जिसके पास कुछ नहीं, वह शहंशाह कैसे होगा? यह संतों का नजरिया है कि असली शहंशाह वही है, जिसकी चाह मिट गई।

चाह आपको खुद से बाहर ले जाती है। कभी सोचा आपने? हर चाह की पूर्ति बाहर कहीं से होती है। कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई पद या कोई घटना आपको खुश कर सकती है। चाह जितना भटकाती है, कुछ और नहीं भटकाता। इसलिए जैसे ही चाह खत्म हुई, वैसे ही चिंता भी मिट जाती है। चिंता चाह की जुड़वां बहन है। वह चाह के पीछे भागती रहती है। चिंता आदमी का सबसे बड़ा शत्रु है; चिता तो एक ही बार जलाती है, चिंता हर पल जलाती रहती है।

चाह होती है सुविधा की, संपत्ति की, सुख की; लेकिन इसकी एक खूबी है- जिसे चाहा है, उसे पाते ही वह बात व्यर्थ हो जाती है। न पाओ तो सार्थक बनी रहती है। इसलिए ओशो त्याग करने के लिए नहीं कहते। वह कहते हैं कि जो भी पाना चाहो, उसे पा लो। पाते ही तुम्हें स्वयं पता चलेगा कि यह बात व्यर्थ हो गई। बिना पाए अगर तुम मानकर चलोगे, तो उसके सपने देखते रहोगे। सभी लोग कुछ न कुछ पाना चाहते हैं। हाथ में घड़ी नहीं होती, तो उन्हें घड़ी की फिक्र होती है कि वह मिल जाए, तो बड़ा आनंद आएगा। फिर चार-छह दिन बाद आदमी पाता है कि बात खत्म हो गई। अब कुछ और चाहिए, जो मिले तो आनंद आए।

जो भी पा लिया है, उसे गौर से देखिए कि जब आपने नहीं पाया था, तब आप उससे कितनी आशा बांधे हुए थे और अब जब उसे पा लिया है, तब कितनी आशा फलीभूत हुई है। उस चीज में कोई खराबी नहीं है, बल्कि मन के स्वभाव में गड़बड़ी है। मन इतना छोटा है कि खुद के साथ कभी संतुष्ट नहीं रह सकता। उसे कुछ ऐसा चाहिए, जो असाध्य है, बड़ी मुश्किल से मिलता है, तब फिर उसे मजा आता है और मन एक मशीन है, जो एक के बाद दूसरी चाहतें पैदा करता जाता है। जो चाह पूरी हुई, उसके साथ क्या हुआ, इसे देखने का वक्त ही नहीं है। जब एक चीज व्यर्थ हो जाती है, तब हम तत्काल दूसरी चीज में संलग्न हो जाते हैं। देखने का मौका नहीं मिल पाता। हम कभी लौटकर यह नहीं देखते कि सभी चीजें, जो हमने चाहीं, वे सब बेकार हो गईं।

चाह आपको खुद से बाहर ले जाती है। हर चाह की पूर्ति बाहर से होती है। कोई व्यक्ति, वस्तु, पद या कोई घटना आपको खुश कर सकती है। चाह जितना भटकाती है, कुछ और नहीं भटकाता।

अगर यह दिखाई पड़ जाए, तो आपकी चाह ही बेकार हो जाएगी। आप कहोगे कि अब तो एक ही चीज बेकार है, चाह। बाकी सब चीजें तो ठीक ही हैं, चाह आपको नचा रही है। जिस दिन यह घटना घटेगी, उस दिन आप शहंशाह होंगे। न रहेगी चाह, न होगी चिंता और फिर आपका मन होगा बेपरवाह।

अमृत साधना

राजनाथ सिंह | रक्षा मंत्री

आजादी का अर्थ केवल स्वतंत्र रूप से अपनी बात कहना नहीं है, बल्कि अपनी स्वतंत्रता के साथ-साथ जिम्मेदारियों को समझना भी है। स्वतंत्र भारत के नागरिक के रूप में हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं और यह बात विशेषकर हमारे युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

यह सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग

भारतीय रेलवे को देश की आम जनता की जीवन-रेखा कहा जाता है। करोड़ों यात्री रोजाना ट्रेन से सफर करते हैं, जिनमें बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है, जिन्हें कन्फर्म टिकट, साफ-सुथरे शौचालय, समय पर ट्रेन और पर्याप्त सीट जैसी सुविधाओं के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे में, रेलवे के आलीशान 'सैलून' को लेकर उठा विवाद केवल एक कोच की बुकिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सरकारी संसाधनों के इस्तेमाल और वीआईपी संस्कृति की बहस से भी जुड़ता है।

हाल में रेलवे बोर्ड ने निजी लोगों के उपयोग वाले सैलून कोच की बुकिंग बंद करने का निर्णय किया था। यह सुविधा अब केवल रेलवे के उच्च अधिकारियों के आधिकारिक दौरों और उपयोग के लिए ही सीमित कर दी गई है। यह वह सुविधा थी, जो राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से 2019 से आम लोगों के लिए उपलब्ध कराई जा रही थी, लेकिन जुलाई 2026 में एक निजी पार्टी द्वारा लगभग 3.09 लाख रुपये में सैलून बुक करके उसमें पूजा-अनुष्ठान किए जाने का वीडियो वायरल हुआ, तो लोग हैरान रह गए।

सैलून कोई सामान्य रेल डिब्बा नहीं है। इसमें वातानुकूलित शयन कक्ष, अलमारी, लिविंग व डाइनिंग एरिया, रसोई, फ्रिज और दूसरी सुविधाएं होती हैं। सवाल यह भी है कि जब रेलवे ने निजी यात्रियों के लिए इसकी बुकिंग बंद कर दी है, तो क्या इसका इस्तेमाल बड़े अधिकारियों के लिए जारी रहना चाहिए? यदि जनता के लिए यह सुविधा नियम, सुरक्षा या संसाधनों के कारण अनुचित है, तो वही कारण अधिकारियों के संदर्भ में भी होने चाहिए।

यह तर्क दिया जा सकता है कि रेलवे अधिकारियों को निरीक्षण, ट्रैक-निगरानी तथा आकस्मिक परिस्थितियों में दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए विशेष व्यवस्था की जरूरत होती है, लेकिन निरीक्षण के लिए आलीशान सैलून ही एकमात्र विकल्प नहीं है। रेलवे के पास सामान्य एसी कोच, निरीक्षण कार और अन्य आधिकारिक व्यवस्थाएं हैं। आधिकारिक नियमों में भी विशेष कोच और सैलून का उल्लेख है तथा इनके संचालन पर किराया, सुरक्षा और खाली दूरी की ढुलाई जैसे शुल्कों के प्रावधान हैं। सबसे बड़ा सवाल खर्च का है। सैलून केवल एक डिब्बा नहीं, बल्कि उसके रखरखाव, सफाई, विद्युत व्यवस्था, वातानुकूलन, स्टाफ व परिचालन से जुड़ा लगातार खर्च भी है।

जब रेलवे को हर साल सुरक्षा उपायों, आधुनिकीकरण, ट्रैक सुरक्षा, पुल, सिगनल और नई ट्रेनों के लिए भारी निवेश करना पड़ता है, तब इन पर बेतहाशा धन बर्बाद करने की क्या जरूरत है?

विभूति बुपक्या, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम
रेलवे सैलून

विकसित भारत में बेहतर सुविधाएं जरूरी

भारतीय रेलवे ने राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से साल 2019 में सैलून को आम यात्रियों को मुहैया कराने की शुरुआत की थी। हालांकि, इसका शुरुआती उपयोग बेहद सीमित रहा। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, पूर्वोत्तर रेलवे में इस सुविधा के शुरू होने के बाद केवल दो निजी बुकिंग हुई थीं। अब रेलवे ने इस सुविधा को बंद करने का फैसला किया है। यह फैसला रेलवे को तो राजस्व-हानि पहुंचाएगा ही, देश की छवि निखारने का एक अच्छा अवसर भी खत्म कर देगा।

निजी खर्चे से रेल सैलून की व्यवस्था 'विकसित भारत' के लक्ष्य के अनुकूल ही कहा जाना चाहिए था। अब हमारा देश कोई 1947 या उससे पहले का पिछड़ा और गुलाम तो है नहीं, आजादी के बाद उसने काफी तरक्की की है और अपनी शासन-व्यवस्था में कई क्षेत्रों में अहम मुकाम हासिल किए हैं। इसी क्रम में लोगों की आय में बढ़ोतरी हुई है और सामान्य आदमी के जीवन-स्तर में काफी सुधार आया है। इसीलिए भारत में विदेशी पर्यटकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जैसे-जैसे देश की तरक्की होती जाएगी, लोगों का जीवन-स्तर ऊपर उठता जाएगा, वैसे-वैसे विदेशी सैलानी भी हमारे देश में अधिक रुचि लेंगे और उनकी संख्या बढ़ेगी। यह हमारे देश की अर्थव्यवस्था और रोजगार के लिहाज से भी काफी जरूरी है। विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए जो सबसे जरूरी बात है, वह है- सुविधाओं के मामले में देश को बेहतर बनाना। अगर यहां की सुविधाएं और आवागमन के साधन बेहतर स्थिति में होंगे, तभी विदेशों से, खासकर विकसित, अमीर देशों के पर्यटक यहां आना पसंद करेंगे। इसके लिए सबसे जरूरी यातायात के साधन के रूप में अपनी रेलगाड़ियों को तैयार रखना होगा।

इस लिहाज से सैलून कोच का विचार बहुत ही अच्छा था। इस सुविधा को बंद करना रेलवे की नकारात्मक छवि ही प्रस्तुत करता है। इससे रेलवे के साथ ही देश की अर्थव्यवस्था और रोजगार को भी नुकसान पहुंचेगा। रेलवे के पास सामान्य एसी कोच, निरीक्षण कार और अन्य सुविधाएं तो हैं, पर सैलून की बात ही कुछ और है। रेलवे के आधिकारिक नियमों में भी विशेष कोच और सैलून की व्यवस्था का उल्लेख है तथा इनके संचालन पर किराया, सुरक्षा और दूरी की ढुलाई जैसे शुल्कों के प्रावधान हैं। सैलून केवल एक कोच नहीं है, बल्कि परिचालन के लिहाज से यह भारतीय रेल की शान है। इसलिए सरकार को सैलून सेवा की बहाली पर गौर करना चाहिए, जिससे देश में पर्यटकों की आवक तो बढ़े ही, दुनिया में भारत व हमारी रेल की अच्छी छवि बने।

विभा चौधरी, गृहिणी

मन को सही जगह कैसे लगाएं

आज किसी एक काम को मन लगाकर करना कठिन हो गया है। मोबाइल नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, ईमेल और एक साथ कई काम करने की आदत, हमारा ध्यान भटकाते रहते हैं। जब कई सारे विकल्प सामने हों तो सबसे बेहतर है कि आप किसी एक जरूरी काम को चुनिए और उसी पर ध्यान दीजिए। धीरे-धीरे आपका दिमाग भी सीखने लगेगा कि हर चीज पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है।

जेम्स क्लियर
अमेरिकी लेखक और वक्ता। निरंतर सुधार पर जोर। 'एटॉमिक हैबिट्स' उनकी चर्चित किताब है।

फोकस का अर्थ है किसी एक काम, विचार या लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करना। जब हम किसी एक चीज पर ध्यान देते हैं, तो उस समय के लिए हमें बाकी चीजों को 'न' कहना पड़ता है। एकाग्रता केवल किसी काम को चुनना नहीं है। यह दूसरे विकल्पों से कुछ समय के लिए ध्यान हटाने की क्षमता है।

लेखक टिम फेरिस कहते हैं, 'क्या नहीं करते, यही तय करता है कि आप क्या कर सकते हैं।' जब कोई काम बहुत जरूरी होता है, तो हम पूरा ध्यान उस पर लगा लेते हैं। लेकिन, जब कई आकर्षक विकल्प सामने होते हैं, तब हमें फैसला करना पड़ता है।

मल्टीटास्किंग का भ्रम

तकनीकी रूप से, हम एक साथ दो काम कर सकते हैं। खाना बनाते हुए टीवी देखना या फोन पर बात करते हुए किसी ईमेल का जवाब देना संभव है। जो चीज संभव नहीं है, वो यह कि एक समय में हम दो कामों को पूरी एकाग्रता से नहीं कर सकते। टीवी देखते हुए ई-मेल का जवाब देना गौण हो जाता है। ई-मेल का जवाब देते समय टीवी देखना। इस स्थिति में मन एक काम से दूसरे काम पर स्विच करता रहता है। यही बदलाव हमारी ऊर्जा और समय की कीमत वसूलता है।

किसी ई-मेल के बीच फोन आ जाए या किसी अन्य कारण से काम रुक जाए, तो दोबारा उसी मानसिक स्थिति में लौटने में समय लगता है। इसे 'स्विचिंग कॉस्ट' कहते हैं। स्विचिंग कॉस्ट उस व्यवधान को कहते हैं, जो तब पैदा होता है, जब हम अपना ध्यान एक काम से हटाकर दूसरे काम पर लगाते हैं। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंफोर्मेशन मैनेजमेंट में छपे एक अध्ययन में पाया गया कि सामान्य व्यक्ति हर पांच मिनट में एक बार अपना ई-मेल चेक करता है। हर बार ई-मेल देखने के बाद पिछले काम पर दोबारा ध्यान केंद्रित करने में औसतन 64 सेकंड लगते हैं।

ध्यान को सही दिशा कैसे दें?

1 अपनी प्राथमिकताएं सीमित करें

हमारे सामने मौजूद सभी विकल्प खराब नहीं होते, लेकिन अच्छे विकल्प भी हमारी सबसे महत्वपूर्ण चीजों से हमारा ध्यान चुरा सकते हैं। हम अक्सर ऐसे कामों में समय लगाने का तर्क आसानी से खोज लेते हैं-'यह भी जरूरी है', 'इसे भी थोड़ा कर लेता हूं' आदि। नतीजा, हमारी ऊर्जा कई दिशाओं में बंट जाती है और कोई भी महत्वपूर्ण काम हम उतने ध्यान से नहीं कर पाते, जितनी उसे जरूरत है।

2 अपनी प्रगति मापिए

जिस चीज को हम मापते हैं, उस पर हमारा ध्यान अधिक बना रहता है। पढ़ने के पन्ने गिनना हो, व्यायाम की संख्या दर्ज करना हो या किसी लक्ष्य पर बिताए गए घंटे नोट करना, हमें इस तरह स्पष्ट फीडबैक मिल जाता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं या नहीं। यह अपने बारे में फैसला सुनाना नहीं, बस अपनी वास्तविक स्थिति समझना है।

3 क्रिया पर ध्यान दें

अक्सर हम सफलता को किसी एक घटना के रूप में देखते हैं-वजन कम हो जाए, किताब प्रकाशित हो जाए या कोई बड़ा पुरस्कार मिल जाए। लंबे समय तक सफलता हासिल करने वाले लोग रोज की प्रक्रिया को महत्व देते हैं। अच्छा लेखक बनने के लिए लिखने की आदत विकसित करनी होगी। स्वस्थ रहने के लिए नियमित व्यायाम और बेहतर खानपान अपनाना होगा। कारोबार बढ़ाने के लिए रोजाना ग्राहकों, उत्पाद और रणनीति पर काम करना होगा। बड़े परिणाम अक्सर छोटी-छोटी कोशिशों का नतीजा होते हैं।

एकाग्रता बढ़ाने के व्यावहारिक तरीके

दिन का एक 'एंकर टास्क' तय करें : हर दिन एक ऐसा काम चुनिए, जिसे पूरा करना अनिवार्य हो। बाकी काम पूरे हो सकते हैं या टल सकते हैं, लेकिन यह एक काम नहीं टलना चाहिए। यही आपका दिन का मुख्य आधार बनेगा।

समय नहीं, ऊर्जा पर जोर दें: हमारी मानसिक ऊर्जा दिन भर एक जैसी नहीं रहती। यदि सुबह आपका दिमाग सबसे अधिक सक्रिय रहता है, तो जरूरी काम सुबह करें। काम के लिए समय के साथ मानसिक ऊर्जा होना भी जरूरी है।

सुबह की शुरुआत जरूरी काम से : दिन की शुरुआत ईमेल और संदेशों से करने पर हम तुरंत दूसरों के एजेंडे पर काम करने लगते हैं। संभव हो,तो सुबह का कुछ समय अपने सबसे महत्वपूर्ण काम के लिए सुरक्षित रखें।

फोन को दूर रखिए: फोन साथ होने मात्र से भी ध्यान बार-बार उसकी ओर जा सकता है। काम के समय फोन दूर रखना या नोटिफिकेशन बंद करने से एकाग्र होने में मदद मिल सकती है।

स्क्रीन पर सिर्फ जरूरी चीज : कंप्यूटर पर काम करते समय फुल-स्क्रीन मोड का इस्तेमाल करें। दूसरे ऐप, आइकन और नोटिफिकेशन जितने कम दिखाई देंगे, ध्यान भटकाने वाले संकेत भी उतने कम होंगे।

शुरुआत ही सबसे महत्वपूर्ण है : एकाग्र होने की क्षमता एक दिन में हासिल नहीं की जा सकती। यह रोज के निर्णयों और आदतों से धीरे-धीरे मजबूत होती है। जब दुनिया आपका ध्यान अलग-अलग दिशाओं में खींच रही हो, तब सबसे प्रभावी होता है कि आप एक काम चुनिए और उसी पर ध्यान दीजिए। धीरे-धीरे आपका दिमाग भी सीखने लगेगा कि हर क्षण हर चीज पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। jamesclear.com

विविध

सांसों का अभ्यास सदमों से उबारेगा

किसी प्रिय को खोना, डरावनी घटना या अन्य कोई आघात, दिमाग पर लंबे समय तक असर डाल सकता है। चिंता, बेचैनी, नींद में कमी या दूसरों से दूरी के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। नए शोध के अनुसार लयबद्ध ढंग से सांस लेने व छोड़ने का अभ्यास तंत्रिका तंत्र को शांत रखता है।

जब कोई व्यक्ति गहरे सदमे से गुजर रहा होता है, तो उसका असर केवल विचारों तक सीमित नहीं रहता। हमारा पूरा तंत्रिका तंत्र भी इससे प्रभावित हो सकता है। आघात के कारण शरीर हर पल खतरे का एहसास करता है और 'फाइट या फ्लाइट' मोड में बना रहता है। शांत बैठना या सही सोच पाना कठिन हो जाता है।

हालिया वैज्ञानिक अनुसंधानों ने यह साबित किया है कि 20 मिनट सांसों का नियंत्रित ढंग से अभ्यास मानसिक आघात से उबरने, तन और मन में संतुलन स्थापित करने और मानसिक मजबूती हासिल करने में मदद कर सकता है।

शोध क्या कहते हैं?

- **सैनिकों और दिग्गजों पर असर :** इराक और अफगानिस्तान युद्ध से लौटे मानसिक तनाव से पीड़ित सैनिकों पर किए गए एक अध्ययन में केवल एक हफ्ते के सांसों के अभ्यास से उनके चिंता के स्तर में भारी गिरावट देखी गई। यह लाभ एक साल बाद भी बना रहा।
- **पारंपरिक थेरेपी के बराबर प्रभावी :** पालो अल्टो वेटरन्स हॉस्पिटल के अन्य शोध में सांस का नियमित अभ्यास करना कॉग्निटिव प्रोसेसिंग थेरेपी जितना प्रभावी पाया गया।
- **किशोरों और युवाओं पर अध्ययन :** यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, लॉस एंजिल्स द्वारा हाई स्कूल की छात्राओं पर किए गए शोध में पाया गया कि जिन लड़कियों ने बचपन में सबसे ज्यादा प्रतिकूल परिस्थितियों और आघात का सामना किया था, वे इस अभ्यास के बाद खुद को दूसरों से अधिक जुड़ा हुआ और सुरक्षित महसूस करने लगीं।

बेचैनी में कमी

मानसिक आघात और पुरानी यादें शरीर की शारीरिक क्रियाओं में दर्ज हो जाती हैं। सांसों का नियंत्रित और लंबा प्रवाह (खासकर, सांस छोड़ने की अवधि सांस लेने से दोगुनी हो) शरीर की वेगस नस को सक्रिय करता है। इससे मस्तिष्क को संकेत मिलता है कि अब कोई खतरा नहीं है। इस तरह अतीत की यादें कम परेशान करने लगती हैं।

कैसे करें शुरुआत

- आंखें बंद करें, जिस अवस्था में आराम से बैठ सकते हैं बैठें।
- 4 सेकंड तक सांस लें और फिर 8 सेकंड तक धीरे-धीरे सांस बाहर छोड़ें।
- केवल 5 मिनट तक इस प्रक्रिया को दोहराने से तंत्रिका तंत्र शांत होने लगता है। हालंकि, शोध में सांस के अभ्यास से जुड़ी 20 मिनट की प्रक्रिया कराई गई थी।

अपना आज बीते कल से बेहतर बनाएं

समय के साथ हमारी सोच और क्षमताओं में निखार आता है। यह बदलाव अपने आप नहीं हो जाता। इसके लिए हमें हर दिन अपनी सेहत, सोच और व्यक्तित्व को बेहतर बनाने का चुनाव करना पड़ता है। लगातार की गई छोटी-छोटी कोशिशें ही समय के साथ बड़ा असर पैदा करती हैं।

जन्म से लेकर पांच वर्ष की उम्र तक मानव दिमाग का विकास सबसे तेज गति से होता है। इस उम्र तक मस्तिष्क का लगभग 85 प्रतिशत हिस्सा विकसित हो चुका होता है। इसके बाद विकास की रफ्तार धीमी जरूर पड़ती है, लेकिन हमारा सीखना व आगे बढ़ना कभी बंद नहीं होता।

अक्सर हम व्यक्तिगत विकास को करियर तक सीमित कर देते हैं। हालांकि, खुद को बेहतर बनाने की कोई सीमा नहीं है। जीवन को अधिक आनंद के साथ जीना भी व्यक्तिगत विकास का हिस्सा है। सबसे जरूरी है-कोशिश करते रहना। खुद को बेहतर बनाने की कोशिश हमारा आत्म-विश्वास बढ़ाती है, प्रदर्शन सुधारती है और संतुष्टि बढ़ाती है। जब आप किसी एक क्षेत्र में सुधार की आदत डालते हैं, तो धीरे-धीरे उसका असर दूसरे क्षेत्रों पर भी दिखता है। सवाल है, आखिर लोग हर दिन खुद को बेहतर क्यों नहीं बनाते?

बहाने ही बहाने

हम मेहनत करने के बजाय, काम करने से बचाने वाले बहाने बनाने लगते हैं-

- आखिर मुझे इससे मिलेगा क्या?
- मैं सफल हूं, तो क्या सुधार करूं?
- मुझे पहले से सब पता है।
- रिटायरमेंट की उम्र में क्या मेहनत करूं?
- मेरे पास इसके लिए समय ही नहीं है।
- जब कोई मुझे कहेगा, तब कर लूंगा।
- मैं इतनी मेहनत नहीं कर सकता।
- इसका फायदा कई साल बाद मिलेगा।
- यह बात मुझ पर लागू ही नहीं होती।
- मैंने काम कर दिया है। अब कोई और करे।
- आप मेरी आलोचना ही क्यों करते हैं?
- अगर मैं इसमें असफल हो गया तो?
- मुझे अपनी जिंदगी जैसी है, पसंद है।

इस तरह के अनेक बहाने हो सकते हैं, लेकिन इनका परिणाम एक ही होता है। हम खुद को बेहतर नहीं बना पाते।

इन कोशिशों से बनेगा बेहतर कल

इसके लिए सबसे पहले ध्यान, मेहनत और स्पष्ट इरादे की जरूर होगी। इन बातों को अपनाएं-

- नया सीखना बंद न करें। व्यस्त होने के बावजूद थोड़ा समय निकालें। नए मौकों के बारे में जानें।
- करियर के साथ-साथ सेहत, रिश्ते, चरित्र, सोच और जीवनशैली भी महत्वपूर्ण हैं।
- पहल करें। खुद आगे बढ़कर सीखें।
- जीतने पर ही नहीं, सीखने पर ध्यान दें।
- छोटे-छोटे सुधारों का लक्ष्य रखें।
- असफलता से सीखें और आगे बढ़ें।
- पुरानी आदतों को चुनौती दें।
- दूसरों के दृष्टिकोण को भी समझें।
- यह मानें कि अभी बहुत कुछ सीखना है।
- ईमानदारी से अपनी समीक्षा करते रहें।
- अपनी और दूसरों की गलतियों से सीखें।
- दूसरों की अच्छी खूबियों से सीखें।
- कोई कमी बताए, तो उसका बुरा न मानें।

franksonnenbergonline.com

खुद से करें हमेशा ये दो सवाल

- अगली बार मैं यह काम और बेहतर कैसे कर सकता हूं?
- मैं कैसा इंसान बन रहा हूं?

मकसद सबसे अच्छा बनना नहीं, कल से बेहतर बनना है। कोई और आपको अपना स्तर ऊंचा उठाने के लिए मजबूर नहीं करेगा। यह फैसला आपको खुद लेना होगा।

हो सकता है कि आज आपको अपने भीतर कोई बड़ा बदलाव महसूस न हो, लेकिन लगातार किए गए छोटे और सही प्रयास समय के साथ बड़ा असर पैदा करते हैं। ठहर जाने को मामूली बात समझना भूल है। दुनिया लगातार आगे बढ़ रही है। जब आप रुकते हैं, तो आपके पीछे छूटने का खतरा बढ़ता जाता है। कोशिश न करना भी कोई तटस्थ फैसला नहीं है। यह धीरे-धीरे जीवन यों ही गुजार देने का तरीका बन जाता है।

एकदा पहचान

एक बार एक गर्भवती शेरनी शिकार की तलाश में भेड़ों के एक झुंड पर झपटी। झपटने के उत्साह और भागदौड़ में शेरनी ने एक बच्चे को जन्म दिया व खुद वहीं दम तोड़ दिया।

वह नवजात शेर का बच्चा भेड़ों के झुंड के बीच बड़ा होने लगा। वह भेड़ों के साथ रहता, उन्हीं की तरह घास खाना और मिमियाना भी सीख गया। वह खुद को पूरी तरह से एक भेड़ ही मानता था।

वह शेर का बच्चा डरपोक था, क्योंकि उसने भेड़ों से केवल डरना और भागना ही सीखा था। एक दिन, एक बूढ़े शेर ने उस भेड़ों के झुंड पर हमला किया। उसने देखा कि झुंड के बीच एक जवान शेर भी भेड़ों की तरह डर से मिमिया रहा है। यह देखकर बूढ़े शेर को अचरज हुआ। उसने भेड़ों का पीछा छोड़ दिया और उस युवा शेर को दबोच लिया।

शेर कांपने लगा और गिड़गिड़ाते हुए बोला, 'मुझे मत मारो, मुझ पर दया करो! मैं तो छोटी सी भेड़ हूं।'

बूढ़ा शेर मुस्कुराया और उसे खींचते हुए पास की एक साफ पानी की झील के किनारे ले गया। उसने युवा शेर से कहा, 'रोना बंद करो और इस पानी में हम दोनों के चेहरे देखो।'

युवा शेर ने पानी में अपनी परछाई देखी। उसने देखा कि उसका चेहरा भेड़ जैसा नहीं, बल्कि उस बड़े शेर जैसा था! उसी पल उसके अंदर एक गहरी समझ कौंधी। उसे एहसास हुआ कि वह भेड़ की संगत में रहने के कारण खुद की पहचान भूल बैठा था। उसकी मिमियाहट गायब हो गई। उसने अपनी जिंदगी की पहली दहाड़ लगाई, जिससे पूरा जंगल गूंज उठा।

ओशो कहते हैं कि हममें से अधिकांश लोग उस शेर के बच्चे की तरह ही जी रहे हैं। समाज, डर और दूसरों की धारणाओं के बीच रहते-रहते हम यह भूल जाते है कि हमारे भीतर असीम क्षमता और दिव्यता छिपी है।

रोजनामचा

पं. राघवेन्द्र शर्मा
ज्योतिषाचार्य

स्कैन करें
भविष्यफल और व्रत-त्योहार जानने के लिए

मेष : संयत रहें। धैर्यशीलता बनाए रखें। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान पर जा सकते हैं। परिवार की सेहत का ध्यान रखें। खर्च बढ़ेंगे। परिश्रम अधिक रहेगा।

वृष : मन परेशान रहेगा। संयत रहें। आत्मविश्वास में कमी आएगी। किसी राजनेता से भेंट हो सकती है। कारोबार के लिए यात्रा से लाभ के अवसर मिलेंगे।

मिथुन : आत्मविश्वास तो भरपूर रहेगा। आत्मसंयत रहें। बेकार के क्रोध से बचें। परिवार की सेहत का ध्यान रखें। रहन-सहन अव्यवस्थित रहेगा। खर्च भी बढ़ेंगे।

कर्क : आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। नौकरी में परिवर्तन के साथ तरक्की के अवसर मिलेंगे। आय में वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र में परिवर्तन हो सकता है।

सिंह : आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। धैर्यशीलता बनाए रखने में कमी आ सकती है। नौकरी में कार्यक्षेत्र में बदलाव हो सकता है। परिश्रम अधिक रहेगा। सेहत का ध्यान रखें।

कन्या : मन परेशान रहेगा। कारोबार में बदलाव के योग बन रहे हैं। परिवार व किसी मित्र का सहयोग मिलेगा। खर्चों में वृद्धि होगी। नौकरी में कार्यभार में वृद्धि होगी।

तुला : आत्मविश्वास में कमी रहेगी। मन परेशान भी रहेगा। माता-पिता की सेहत का ध्यान रखें। भागदौड़ अधिक रहेगी। रहन-सहन कष्टमय हो सकता है।

वृश्चिक : मन में उतार-चढ़ाव रहेंगे। धर्म-कर्म में रुचि बढ़ेगी। नौकरी में तरक्की के अवसर मिलेंगे। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। आय में वृद्धि होगी। सेहत का ध्यान रखें।

धनु : मन अशांत रहेगा। आत्मविश्वास में कमी रहेगी। किसी मित्र के सहयोग से नए कारोबार की शुरुआत हो सकती है। भागदौड़ अधिक रहेगी। स्थान परिवर्तन हो सकता है।

मकर : मन अशांत रहेगा। धैर्यशीलता बनाए रखें। माता की सेहत का ध्यान रखें। खर्च बढ़ेंगे। लेखनादि कार्यों से मान-सम्मान की प्राप्ति होगी। आय भी बढ़ेगी।

कुंभ : वाणी में मधुरता रहेगी। धैर्यशीलता बनाए रखें। कारोबार के लिए किसी मित्र के साथ यात्रा पर जा सकते हैं। लाभ के अवसर मिलेंगे।

मीन : मन प्रसन्न रहेगा। संतान सुख में वृद्धि होगी। किसी मित्र के सहयोग से कारोबार में परिवर्तन हो सकता है। यात्रा लाभप्रद रहेगी। संपत्ति में वृद्धि होगी।

व्रत और त्योहार | पंचांग | पं. ऋभुकांत गोस्वामी

31 अगस्त, सोमवार, **शक संवत्** : 09 भाद्रपद (सौर) 1948, **पंजाब पंचांग** : 15 भाद्रपद मास प्रविष्टे 2083, **इस्लाम** : 17 रबि-उल्लावल, 1448, **विक्रमी संवत्** : भाद्रपद कृष्ण तृतीया तिथि प्रातः 08.52 बजे तक पश्चात चतुर्थी तिथि , चंद्रमा मीन राशि में रात्रि 03.24 मिनट तक उपरांत मेष राशि में। **सूर्य दक्षिणायन**। सूर्य उत्तर गोल। वर्षा ऋतु। प्रातः 07.30 बजे से प्रातः 09 बजे तक राहुकालम्। पंचक समाप्त रात्रि 03.24 मिनट। भद्रा प्रातः 08.52 मिनट तक। श्रीगणेश चतुर्थी व्रत। कज्जली तीज। गंडमूल विचार।

वास्तु सलाह | आचार्य मुकुल रस्तोगी

बेटी की नौकरी में बाधाएं अगर आ रही हैं, तो करें ये वास्तु उपाय :

- बेटी को रसोई में पीतल के बर्तनों का उपयोग बढ़ाने के लिए कहें और स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल कम करें। इससे गुरु को ऊर्जा प्राप्त होगी। उनका सम्मान बढ़ेगा। स्टील के बर्तनों का कम उपयोग करने से शनि के कारण आ रही समस्या में कमी आएगी।
- बेटी को हर शनिवार एवं मंगलवार हनुमान जी के दर्शन करने के लिए कहें एवं हनुमान चालीसा पढ़ें। उनको नीम की कंघी एवं नीम के दातुन का उपयोग करना चाहिए।
- शनिवार को पुराने पहने हुए जूते-चप्पल किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर दें। ऐसा करने से नौकरी के रास्ते खुलते हैं। घर की उत्तर दिशा में एक ताला खोल कर रख दें।

वर्ग पहेली : 8437

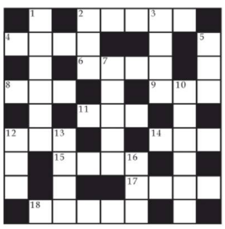

बाएं से दाएं
2. जिसे निश्चित समय तक पूरा करना हो; जो समय से बंधा हो (5)
4. संगी; साथी; सहकर्मी; सहयात्री (4)
6. नापने और तोलने की क्रिया; परिमाण; तौल (4)
8. अखंडित, अभंजित; दृढ़; मजबूत (3)
9. अनुचित रूप से और अकारण; निष्प्रयोजन; फिजूल में; बेमतलब; बिना किसी बात के (3)
11. दालों के आटे से बनाई गई पतली मसालेदार चपाती जिसे भून कर या तल कर पकाया जाता है; पर्पट (3)
12. बीघे का चौथा भाग; भूमि का एक पुराना नाप (3)
14. योग्य; लायक; विद्वान; पंडित (3)
15. कमजोरी; तथ्यहीनता; तर्कहीनता (4)
17. घर्षण करना; पीसना; परिश्रम कराना (4)
18. भार ढोने वाला; कुली; भारिक; मोटिया (5)

ऊपर से नीचे
1. उत्साह न रहना; काया शिथिल होना; दिल बैठ जाना; हिम्मत पस्त होना (3,3)
2. झेलना; सहन करना; फल भोगना (3)
3. परिवर्तित करना; बदलाव होना (4)
5. लकड़ी/लोहे का चौकोर पिटारा; बड़ा डब्बा (3)
7. दूसरों के साथ किया जाने वाला उपकार (5)
10. साख नष्ट होना; स्थिति विपरीत होना (2,4)
12. कंचन; स्वर्ण; धतूरा (3)
13. चुनौती; उच्च स्वर में युद्ध का आह्वान (4)
16. तारा; नक्षत्र; पार उतारने वाला (3)

हरीश चन्द्र सन्सी, विविधा विधा, दिल्ली
(उत्तर अगले अंक में)

वर्ग पहेली : 8436

1 अं	2 त	रि	म	■	3 स	4 म	झा	5 ना
■	द	■	■	6 प	■	धु	■	ग
7 अ	नु	ज	■	रि	■	8 र	ह	ना
■	रू	■	9 प्र	मा	णि	त	■	य
10 उ	प	11 ला	■	ण	■	12 म	13 स्त	क
छ	■	14 भ	र	वा	ना	■	र	■
15 ल	बा	दा	■	च	■	16 म	ही	न
कू	■	य	■	क	■	■	न	■
17 द	र	क	ना	■	18 अ	व	ता	र

सुडोकू : 8391

*कठिन

	7		3			5		
								8
			6				2	9
				1		8		
	6	5	2		8	7	4	
		3		5				
4	8				2			
2								
		1			9		8	

खेलने का तरीका : दिमागी खेल और नंबरों की पहेली है यह। ऊपर नौ-नौ खानों के नौ खाने दिए गए हैं। आपको 1 से 9 की संख्याएं इस तरह लिखनी हैं कि खड़ी और पड़ी लाइनों के हरेक खाने में 1 से 9 की सभी संख्याएं आएं। साथ ही 3×3 के हरेक बक्से में भी 1 से 9 तक की संख्याएं हों। पहेली का हल हम कल देंगे।

सुडोकू : 8390

3	8	4	1	2	5	7	6	9
5	6	9	7	4	3	2	8	1
1	2	7	8	6	9	5	4	3
2	7	1	5	9	4	6	3	8
8	4	3	2	7	6	1	9	5
9	5	6	3	1	8	4	2	7
4	3	8	6	5	7	9	1	2
7	9	2	4	8	1	3	5	6
6	1	5	9	3	2	8	7	4

चिंतन

दुनिया में बढ़ता भारत का रुतबा

उज्बेकिस्तान की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च राज्य सम्मान 'ओली दाराजली दोस्लिक' से सम्मानित किया जाना केवल एक व्यक्ति को मिला सम्मान नहीं है, बल्कि यह बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत की बढ़ती स्वीकार्यता और उसके साथ मजबूत होते कूटनीतिक रिश्तों का संकेत है। मोदी को मिला यह 36वां अंतरराष्ट्रीय सम्मान है। यह दिखाता है कि दुनिया में भारत का रुतबा लगातार बढ़ता जा रहा है। ताशकंद में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव के बीच हुई बातचीत का महत्व इसलिए भी अधिक है, क्योंकि इसमें औपचारिक कूटनीति से आगे बढ़कर यूरेनियम, परमाणु ऊर्जा, रक्षा, व्यापार और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे ठोस मुद्दों पर चर्चा हुई। भारत को अपनी बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए विश्वसनीय और दीर्घकालिक साझेदारों की आवश्यकता है। ऐसे में मध्य एशिया के देशों के साथ ऊर्जा सहयोग भारत की रणनीतिक जरूरत बन चुका है। इसी तरह रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष सहयोग, हथियारों के संयुक्त उत्पादन और नई तकनीक विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ना भारत की बदलती रक्षा नीति को दर्शाता है। भारत अब केवल हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहना चाहता। वह तकनीक, उत्पादन और अनुसंधान में साझेदारी बढ़ाकर अपनी सामरिक क्षमता मजबूत करना चाहता है। उज्बेकिस्तान के साथ रक्षा सहयोग इस दिशा में उपयोगी साबित हो सकता है। सबसे बड़ी चुनौती हालांकि व्यापार की है। दोनों देशों ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को पांच अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है, जबकि वर्तमान व्यापार एक अरब डॉलर से कुछ अधिक है। लक्ष्य महत्वाकांक्षी है, लेकिन इसे हासिल करने के लिए केवल घोषणाएं पर्याप्त नहीं होंगी। भारत को मध्य एशिया तक अपनी व्यापारिक पहुंच आसान करनी होगी। परिवहन, बैंकिंग, भुगतान व्यवस्था, निवेश और बाजार तक पहुंच से जुड़ी अड़चनों को दूर करना होगा। व्यापार बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी भी जरूरी होगी। भारत-उज्बेकिस्तान संबंधों का एक और महत्वपूर्ण पहलू आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद के खिलाफ साझा चिंता है। मध्य एशिया की भौगोलिक स्थिति उसे अफगानिस्तान और व्यापक क्षेत्र में पैदा होने वाली अस्थिरता से सीधे जोड़ती है। भारत भी आतंकवाद को अपनी सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा मानता है। इसलिए दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग केवल द्विपक्षीय विषय नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता से जुड़ा मामला है। मध्य एशिया का क्षेत्र ऊर्जा संसाधनों से समृद्ध होने के साथ यूरोप और एशिया के बीच महत्वपूर्ण भौगोलिक कड़ी भी है। ऐसे समय में जब दुनिया बड़े शक्ति केंद्रों के बीच नए समीकरण बनते देख रही है, भारत के लिए जरूरी है कि वह अपने पड़ोस से आगे बढ़कर मध्य एशिया में भी आर्थिक और रणनीतिक उपस्थिति मजबूत करे। प्रधानमंत्री मोदी को मिला सम्मान इस बढ़ते प्रभाव का प्रतीक जरूर है, लेकिन सम्मान तभी सार्थक होगा जब उससे व्यापार बढ़े, ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हो, रक्षा सहयोग जमीन पर उतरे और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क बढ़े। उज्बेकिस्तान के साथ बढ़ता सहयोग इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दुनिया में भारत का रुतबा बढ़ रहा है, लेकिन इस रुतबे को स्थायी शक्ति में बदलने के लिए कूटनीतिक उपलब्धियों को आर्थिक ताकत, तकनीकी क्षमता और रणनीतिक आत्मनिर्भरता में बदलना होगा। यही नए भारत की असली वैश्विक पहचान होगी।

पर्यावरण

ज्ञानेन्द्र रावत

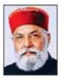

खतरनाक संकेत है वन क्षेत्र में आ रही कमी

देश-दुनिया में यह मान्यता है कि वनों का होना हमारे स्वच्छ पर्यावरण, जीवन, स्वास्थ्य और मानवता का आधार है। पारिस्थितिकीय तंत्र में भी वनों की अहम भूमिका है। यही वह अहम वजह है जिसके कारण देश-दुनिया में आजकल वन क्षेत्र बढ़ाने की होड़ लगी हुई है। इसके पीछे संयुक्त राष्ट्र की 27 अप्रैल 2017 को जारी वनीकरण सम्बंधी वह योजना है। उसके तहत उसने वैश्विक स्तर पर 26 लक्ष्य निर्धारित किए थे, जिसके तहत समूची दुनिया में साल 2030 तक तीन फीसदी जंगल का दायरा बढ़ाना था। इस योजना के तहत जंगल बढ़ाने का दायरा फ्रांस के कुल क्षेत्रफल के दोगुणे से भी अधिक था। बीते नौ सालों में उस लक्ष्य के केवल सात फीसदी की ही पूर्ति कर पाने में कामयाबी मिली है। खेदजनक यह है कि उनमें से दो लक्ष्य तो पूरी तरह अस्तित्व में आए ही नहीं। दुनिया के 48 देशों में जहां कुल वनों का 51 फीसदी हिस्सा वनाच्छादित है, वहां बीते 10 सालों में वन क्षेत्र में तकरीबन चार करोड़ हैक्टेयर से भी ज्यादा की कमी आई है। सबसे अधिक केवल एक साल यानी अकेले 2025 के दौरान ही दुनिया ने करीब 43 लाख हैक्टेयर यानी 1.06 करोड़ एकड़ वन खो दिये। यह लगभग 42,933 वर्ग किलोमीटर वाले डेनमार्क जैसे देश के बराबर है। अगर हम फुटबाल मैदानों की बात करें तो डेनमार्क में लगभग 60 लाख फुटबाल मैदान समा सकते हैं। इसका अर्थ यह कि धरती ने एक साल में 43,000 वर्ग किलोमीटर हरियाली खो दी। मैरीलैंड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों के अध्ययन से यह खुलासा हुआ है कि दुनिया में हर मिनट 11 फुटबाल मैदानों जितने बड़े वन खत्म हो रहे हैं। यह नुकसान एक दशक पहले की तुलना में 46 फीसदी से भी ज्यादा है। चिंतनीय यह कि अब वनीकरण का निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचने में केवल चार साल का ही समय बचा है। ऐसी हालत में यह सवाल बहस का मुद्दा बन गया है कि आखिर वह कौन से कारण रहे जिसके चलते वन संरक्षण की दिशा में दुनिया क्यों पिछड़ती जा रही है? यह भी गौरतलब है कि 2030 तक सतत विकास लक्ष्य हासिल करने के लिए वनावरण के दायरे को बढ़ाने और उपलब्ध वनों को सहेजने की दिशा में दुनियाभर में प्रगति संतोषजनक नहीं है। दरअसल 2021 के जलवायु शिखर सम्मेलन में 100 से भी अधिक देशों ने वादा किया था कि 2030 तक वे वनों की कटाई पूरी तरह रोक देंगे, लेकिन मौजूदा रफ्तार को देखते हुए दुनिया इस लक्ष्य से 70 फीसदी पीछे चल रही है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 1.6 अरब लोगों के लिए जंगल, भोजन,पानी,ईंधन और रोजगार के स्रोत हैं। हालांकि बढ़ते शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, भूमि उपयोग में बदलाव, दावानल,वनोन्मूलन और जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों के कारण वनों का अस्तित्व खतरे में है। वनों के विनाश में केवल वनों की आग की ही अहम भूमिका नहीं है, इंसानी जरूरतें भी वन विनाश का बड़ा कारण है। जबकि वन न केवल सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जरूरी हैं बल्कि वे जैवविविधता के संरक्षण, खाद्य व आजीविका की सुरक्षा,गरीबी उन्मूलन, आक्सीजन की निरंतरता,मृदा संरक्षण, कार्बन अवशोषण और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भी जरूरी हैं। भारत में दावा बराबर वन क्षेत्र में बढ़ोतरी का किया जा रहा है लेकिन हकीकत में वन क्षेत्र में मामूली बढ़ोतरी के बावजूद देश में जगह-जगह जारी विकास परियोजनाओं,खनन, प्राकृतिक दवाबों के कारण पुराने बड़े वनों के घनत्व में काफी कमी और मैंग्रोव वनों में गिरावट दर्ज की गयी है। हमारा कुल वन क्षेत्र 7,15,342.61 वर्ग किलोमीटर यानी 21.76 फीसदी है जबकि वृक्ष आवरण 1,12,014.34 वर्ग किलोमीटर यानी कुल 3.41 फीसदी है। कुल वन क्षेत्र के मामले में हमारे देश का दुनिया में 99वें वां नम्बर है। इसके पीछे सड़क निर्माण, वह भी बड़े-बड़े हाई-वे निर्माण, बांध निर्माण, खदानें और शहरीकरण जैसे विकस कार्यों की अहम भूमिका के चलते पुराने वनों का घनत्व लगातार गिरता जा रहा है। हकीकत यह है कि हर साल तकरीबन 22 लाख से ज्यादा पेड़ों की बलि विकास यज्ञ में दी जा रही है। दरअसल आंकड़ों के जाल के तहत भारत में आधिकारिक आंकड़े कुल वन आच्छादन में भले स्थिरता दर्शाते हैं, किंतु प्राकृतिक वनों की गुणवत्ता और जैव विविधता का स्तर कम होने की प्रवृत्ति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उसमें आये-दिन कमी आ रही है।वास्तविक चुनौती प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्रों की संरचना, उनकी जैविक विविधता और उनकी पुनरुत्पादक क्षमता को सुरक्षित रखने की है। जबतक ऐसा नहीं होगा, यह संकट गहराता ही चला जाएगा।

(लेखक पर्यावरणविद् हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

आर्थिकी

सतीश सिंह

दो समानांतर धरातलों पर अर्थव्यवस्था

भारतीय अर्थव्यवस्था इस समय मजबूती और अनिश्चितता के दो समानांतर धरातलों पर आगे बढ़ रही है। घरेलू उपभोग, सेवा क्षेत्र, औद्योगिक उत्पादन, सरकारी पूंजीगत व्यय और बैंक ऋण में तेजी विकास को सहारा दे रही है। ऊंची थोक महंगाई, वैश्विक युद्ध, कच्चे तेल की कीमतों में अस्थिरता, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की संरक्षणवादी व्यापार नीतियां और बाधित वैश्विक आपूर्ति-शृंखलाएं विकास के लिए जोखिम पैदा कर रही हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की वास्तविक रियल जीडीपी वृद्धि 7.3 प्रतिशत रही। देश की सफलता केवल विश्व की सबसे तेज बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बने रहने में नहीं, बल्कि इस वृद्धि को रोजगारपरक, महंगाई-नियंत्रित, समावेशी बनाने में निहित है।

भारतीय अर्थव्यवस्था इस समय मजबूती और अनिश्चितता के दो समानांतर धरातलों पर आगे बढ़ रही है। घरेलू उपभोग, सेवा क्षेत्र, औद्योगिक उत्पादन, सरकारी पूंजीगत व्यय और बैंक ऋण में तेजी विकास को सहारा दे रही है। दूसरी ओर, ऊंची थोक महंगाई, वैश्विक युद्ध, कच्चे तेल की कीमतों में अस्थिरता, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की संरक्षणवादी व्यापार नीतियां और बाधित वैश्विक आपूर्ति-शृंखलाएं विकास के लिए जोखिम पैदा कर रही हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (रियल जीडीपी) वृद्धि 7.3 प्रतिशत और चौथी तिमाही की वृद्धि 7.8 प्रतिशत रही।

भारतीय रिजर्व बैंक ने अगस्त 2026 में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 6.7 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान व्यक्त किया है। इसका अर्थ है कि अर्थव्यवस्था की रफ्तार मजबूत बनी हुई है, लेकिन पिछले वर्ष के मुकाबले कुछ नरमी आ सकती है। यह संभावित नरमी कमजोरी से अधिक वैश्विक अनिश्चितता, महंगाई और लागत संबंधी दबाव का परिणाम है। जुलाई 2026 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित खुदरा महंगाई 4.45 प्रतिशत रही। यह रिजर्व बैंक के 6 प्रतिशत के ऊपरी सहनशीलता स्तर से नीचे है, लेकिन 4 प्रतिशत के लक्ष्य से अधिक है। खाद्य पदार्थों, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि सीधे परिवारों की क्रयशक्ति को प्रभावित करती है। गरीब और निम्न-मध्यम वर्ग अपनी आय का बड़ा हिस्सा भोजन और आवश्यक वस्तुओं पर खर्च करता है; इसलिए खाद्य महंगाई उसके लिए औसत आंकड़े से अधिक कष्टकारी होती है। इसके विपरीत, जुलाई में थोक महंगाई 9.78 प्रतिशत रही, जो जून के 9.87 प्रतिशत से मामूली कम है। नई आधार-वर्ष शृंखला के अंतर्गत ईंधन एवं बिजली की महंगाई 20.05 प्रतिशत और विनिर्मित उत्पादों की महंगाई 8.29 प्रतिशत रही। विश्लेषण से पता चलता है कि औद्योगिक कच्चे माल, धातु, रसायन, वस्त्र, प्लास्टिक और विद्युत उपकरणों पर लागत का दबाव बना हुआ है। खुदरा और थोक महंगाई का यह अंतर चेतावनी देता है। उत्पादक बढ़ी हुई लागत को कुछ समय तक अपने लाभांश में समाहित कर सकते हैं, लेकिन लगातार ऊंची थोक महंगाई अंततः उपभोक्ताओं के जेब तक पहुंच सकती है। इससे रिजर्व बैंक के लिए ब्याज दरों में नरमी की गुंजाइश सीमित हो सकती है। अगस्त की मौद्रिक नीति में रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए खुदरा महंगाई का अनुमान 5 प्रतिशत रखा है। औद्योगिक क्षेत्र से उत्साहजनक संकेत मिल रहे हैं। जून 2026 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 7.3 प्रतिशत बढ़ा। विनिर्माण उत्पादन में 7.8 प्रतिशत और बिजली एवं गैस उत्पादन में 10.6 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई, जबकि खनन की वृद्धि 1 प्रतिशत रही। इससे स्पष्ट है कि औद्योगिक सुधार व्यापक है, लेकिन सभी क्षेत्रों में समान नहीं है। कमजोर खनन उत्पादन भविष्य में कुछ उद्योगों की इनपुट उपलब्धता को प्रभावित कर सकता है। सेवा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख इंजन बना हुआ है। डिजिटल सेवाएं, वित्त, संचार, पर्यटन, विमानन, परिवहन, खुदरा व्यापार और पेशेवर सेवाएं आर्थिक गतिविधियों को गति दे रही हैं। मई 2026 के प्रायोगिक सेवा उत्पादन सूचकांक में 27.4 प्रतिशत वृद्धि दर्ज हुई, हालांकि नई एवं परीक्षणाधीन शृंखला और

आधार प्रभाव के कारण इस आंकड़े की व्याख्या सावधानी से की जानी चाहिए। सेवा क्षेत्र की मजबूती रोजगार और निर्यात के लिए अनुकूल है, परंतु उच्च कौशल वाली सेवाओं और अपेक्षाकृत कम उत्पादकता वाले अनौपचारिक रोजगार के बीच बड़ा अंतर बना हुआ है। आर्थिक गतिविधियों की मजबूती बैंक ऋण में भी दिखाई देती है। 15 जुलाई 2026 तक बैंक ऋण की सालाना वृद्धि 17.7 प्रतिशत रही, जबकि एक वर्ष पहले यह 9.9 प्रतिशत थी। सेवा और खुदरा क्षेत्रों में ऋण प्रवाह मजबूत है। एमएसएमई ऋण में निरंतर वृद्धि तथा बड़े उद्योगों के ऋण में सुधार निजी निवेश के धीरे-धीरे पुनर्जीवित होने का संकेत देता है। कृषि ऋण भी स्थिर गति से बढ़ रहा है।

डोनाल्ड ट्रंप की 'अमेरिका फर्स्ट' नीति ने वैश्विक व्यापार को अधिक संरक्षणवादी बना दिया है। अप्रैल 2025 में व्यापक जवाबी शुल्क नीति लागू करने के बाद अमेरिका ने भारत पर भी ऊंचे शुल्क लगाए थे। फरवरी 2026 के भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते के ढाँचे के अंतर्गत भारत पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क हटाया गया तथा पारस्परिक शुल्क 25 से घटाकर 18 प्रतिशत किया गया। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जुलाई 2026 में वैश्विक वृद्धि 2026 के लिए 3 प्रतिशत और 2027 के लिए 3.4 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। भारत की वृद्धि का अनुमान 6.4 प्रतिशत है, जिससे वह प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज बढ़ने वाले देशों में बना हुआ है। अमेरिका और यूरो क्षेत्र की वृद्धि भारत से काफी नीचे है। कुछ आसियान अर्थव्यवस्थाएं प्रौद्योगिकी और डेटा-सेंटर निवेश से लाभ उठा रही हैं, परंतु उनकी रफ्तार भी भारत से कम रहने का अनुमान है। भारत का लाभ विशाल घरेलू बाजार और युवा आबादी है, जबकि कमजोरी प्रति व्यक्ति आय, उत्पादकता, महिला श्रम भागीदारी और गुणवत्तापूर्ण रोजगार के मोर्चे पर है। रूस-यूक्रेन युद्ध, पश्चिम एशिया का तनाव और अमेरिका-ईरान टकराव ऊर्जा, उर्वरक, खाद्यान्न और समुद्री व्यापार के लिए जोखिम हैं। आईएमएफ का भी मानना है कि युद्ध के कारण वैश्विक महंगाई में कमी नहीं आ रही है।भारत को विकास की गति बनाए रखने के लिए महंगाई नियंत्रण और वृद्धि समर्थन के बीच संतुलन बनाना होगा। खाद्य महंगाई का टिकाऊ समाधान केवल ब्याज दर बढ़ाना नहीं, बल्कि सिंचाई, भंडारण, कोल्ड-चेन, परिवहन, बाजार सूचना और कृषि आपूर्ति सुधारना है। पेट्रोलियम आयात पर निर्भरता घटाने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा, जैव ईंधन, सार्वजनिक परिवहन और ऊर्जा दक्षता को तेज करना होगा। 'चीन-प्लस-वन' रणनीति का लाभ लेने के लिए लॉजिस्टिक्स लागत घटाने, बिजली आपूर्ति सुधारने, भूमि एवं श्रम नियम सरल करने तथा अनुबंध प्रवर्तन मजबूत करने की जरूरत है। मुक्त व्यापार समझौतों के साथ घरेलू एमएसएमई को तकनीक, गुणवत्ता प्रमाणन और सस्ता वित्त उपलब्ध कराया जाना चाहिए। बैंक ऋण को उपभोग से अधिक उत्पादन और रोजगारोन्मुख निवेश की ओर मोड़ना होगा।

सामाजिक सुरक्षा, कौशल विकास और महिला रोजगार में सुधार घरेलू मांग को अधिक समावेशी और स्थायी बना सकता है। भारतीय अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति आशावादी अवश्य है, लेकिन जोखिममुक्त नहीं। तेज विकास, औद्योगिक उत्पादन, मजबूत सेवा गतिविधि और बढ़ता बैंक ऋण इसकी आंतरिक शक्ति हैं, ऊंची थोक महंगाई, संरक्षणवादी व्यापार नीतियां, युद्ध और अस्थिर आपूर्ति-शृंखलाएं इसकी बड़ी चुनौतियां हैं। भारत की सफलता केवल विश्व की सबसे तेज बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बने रहने में नहीं, बल्कि इस वृद्धि को रोजगारपरक, महंगाई-नियंत्रित, क्षेत्रीय रूप से संतुलित और सामाजिक रूप से समावेशी बनाने में निहित है।

(लेखक आर्थिक स्तंभकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया haribhoomi@gmail.com पर दे सकते हैं।

निंदा का परित्याग

संकलित

दर्शन

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में निर्वहन के लिए व्यक्ति के सामाजिक गुणों का अत्यंत महत्व है। गुणी व्यक्ति को प्रत्येक जगह सम्मान की प्राप्ति होती है। संसार के प्रत्येक प्राणी में कुछ गुण तो कुछ अवगुण पाए जाते हैं, परंतु कुछ लोग हैं जो दूसरे के अवगुणों को ही देखते हैं। वे किसी भी सकारात्मक पक्ष में नकारात्मकता देखने के अभ्यस्त हो जाते हैं। प्रायः ऐसे लोगों में निंदा की प्रवृत्ति पाई जाती है। वे ऐसा करके खुद को समाज में श्रेष्ठ एवं दूसरे को नीचा साबित करना चाहते हैं। निंदा एक नशे की भांति है, जो एक बार इसका आदी हो गया, वह दिन-प्रतिदिन इसके पाश में जकड़ता चला जाता है। मनीषियों ने निंदा को दुर्व्यसन के समान माना है, जो निंदा करने वाले व्यक्ति को अंदर ही अंदर नैतिक रूप से समाप्त करती रहती है। एक बार एक आचार्य अपने शिष्यों को शिक्षा प्रदान कर रहे थे। शिक्षा प्राप्ति के दौरान एक शिष्य अन्य शिष्यों की ओर संकेत करते हुए आचार्य से कहने लगा कि 'वे अपना कार्य सही से नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है इन लोगों को कार्य करना ही नहीं आता।' आचार्य बोले, 'तुमको छोड़ अन्य सारे शिष्य सही से कार्य कर रहे हैं।' इस पर शिष्य असहज हो गया। उसने आचार्य से पूछा, 'वह कैसे?' आचार्य बोले, 'क्योंकि वे लोग अपने कार्य में संलग्न हैं, किंतु तुम अपने कार्य पर ध्यान न देकर, दूसरों के कार्य की निंदा करने में अपने समय की बर्बादी कर रहे हो।'

मुनि के शाप से देवराज इंद्र से छिन गया था स्वर्ग

संकलित

प्रेरणा

एक दिन दुर्वासा मुनि विष्णु जी के पास पहुंचे। उस समय विष्णु जी ने दुर्वासा मुनि को अपनी दिव्य माला उपहार में दी। विष्णु जी से मिलकर दुर्वासा मुनि लौट रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में देवराज इंद्र दिखाई दिए। इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर सवार थे और दुर्वासा मुनि पैदल थे। इन दोनों ने एक-दूसरे को देख लिया। उस समय दुर्वासा जी ने सोचा कि विष्णु जी ने जो माला दी है, वह मेरे किसी काम की नहीं है। ये माला इंद्र को दे देता हूं। इंद्र स्वर्ग के राजा हैं तो उनके गले में ये माला शोभा देगी। ऐसा सोचकर दुर्वासा मुनि ने विष्णु जी की माला इंद्र को उपहार में दे दी। देवराज इंद्र ने दुर्वासा जी से वह माला ले ली। उस समय देवराज इंद्र का अहंकार जाग गया। वह अपने ऐरावत हाथी पर बैठे हुए थे, स्वर्ग के राज-पाठ का घमंड था। इसी घमंड की वजह से इंद्र ने सोचा कि ये सामान्य सी माला मेरे काम नहीं आएगी। ये सोचकर इंद्र ने वह माला अपने ऐरावत हाथी के ऊपर डाल दी। ऐरावत ने अपनी सूंड से वह माला पकड़ी और पैरों से कुचल दी। ये सब दुर्वासा मुनि ने देख लिया, अपने उपहार का ऐसा अपमान देखकर वे क्रोधित हो गए। गुस्से में उन्होंने इंद्र से कहा कि आज तूने अपने राज-पाठ और पद के घमंड में मेरे उपहार का अनादर किया है, मैं तुझे शाप देता हूं, तेरा सारा वैभव चला जाएगा और तू स्वर्गहीन हो जाएगा। इसके बाद असुरों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया और देवता पराजित हो गए। इंद्र को स्वर्ग से जाना पड़ा था।

अंतर्मन

उत्तराखण्ड में खड़गे की रैली के बाद शुद्धिकरण यज्ञ पर सियासी बवाल

आज की पाती

प्याज की बढ़ती कीमत महंगाई का एक और झटका

अगर देश में कोई भी खाने की चीज, वो भी गरीब से गरीब के लिए भी रोजमर्रा में प्रयोग होने वाली हो, महंगी हो जाए तो सरकारों को उसकी कीमत कम करने के उपाय प्राथमिक आधार पर करने चाहिए। विकास के वादे और दावे तब तक खोखले माने जा सकते हैं, जब तक देश में पैदा होने वाली चीजें महंगी हों। अब तो सरकारों को प्याज की बढ़ती कीमतों के लिए कुंभकर्णी नींद से जाग जाना चाहिए, क्योंकि अब देश के कुछ राज्यों में इसकी कीमत 50 रुपए प्रति किलो से ऊपर हो चुकी है। वैसे प्याज की कीमतें इससे पहले भी बढ़ती थी और इस पर खूब राजनीति भी होती आई है। प्याज पर ही नहीं, बल्कि हर तरह की महंगाई को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़े जाते हैं। लेकिन महंगाई के समाधान के लिए किसी भी राजनीतिक पार्टी की सरकार ने आज तक गंभीरता नहीं दिखाई।

- संजय पटेल, चिरमिरी

ट्रेंड

मिशन शक्तिसैट

मिशन शक्तिसैट 108 देशों की छात्राओं को एक साथ ला रहा है और उन्हें सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के बारे में सीखने के साथ-साथ विज्ञान, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के नए क्षेत्रों को जानने का मौका भी दे रहा है।

-अन्नपूर्णा देवी, केंद्रीय महिला विकास मंत्री

शुद्धिकरण

हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के साथ जो कुछ भी हुआ, वह "शुद्धिकरण" के नाम पर उनके प्रति छुआछूत का मामला है और भारतीय संविधान के तहत छुआछूत एक दंडनीय अपराध है। तब से बीस दिन बीत चुके है - लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

- राहुल गांधी, सांसद, कांग्रेस

प्रोटॉन बीम थेरेपी

असम में कैंसर के इलाज का एक नया दौर शुरू हो रहा है। गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में प्रोटॉन बीम थेरेपी के लिए 600 करोड़ की मंजूरी मिलने के साथ, असम सरकारी अस्पतालों में यह अत्याधुनिक इलाज सुविधा देने वाला पहला राज्य बन जाएगा।

- हिमंत बिस्वा सरमा, सीएम, असम

मोदी का सम्मान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान के सर्वोच्च राजकीय सम्मान 'ओली दराजली दोस्तलिक' से सम्मानित होने पर हार्दिक शुभकामनाएं। यह सम्मान दोनों देशों के बीच अटूट मित्रता, आपसी विश्वास और सांस्कृतिक साझेदारी का प्रतीक है।

- डॉ. मोहन यादव, सीएम, मध्यप्रदेश

करंट अफेयर

अमेरिका ने कई अफगानियों को मध्य अफ्रीकी गणराज्य भेजा

अमेरिका ने शनिवार को कई लोगों को मध्य अफ्रीकी गणराज्य निर्वासित किया, जिनमें एक अफगान नागरिक भी शामिल है, जिसके भाइयों ने अमेरिकी सेना के साथ मिलकर काम किया था। यह जानकारी उसके वकील और एक मानवाधिकार संगठन ने दी। इस अफगान नागरिक की उम्र 20 वर्ष के आसपास है। उसके वकील अल्मा डेविड ने बताया कि एक अमेरिकी न्यायाधीश ने तालिबान द्वारा उत्पीड़न की आशंका के कारण उसे अफगानिस्तान निर्वासित किए जाने से सुरक्षा प्रदान की थी। 'द एसोसिएटेड प्रेस' को प्राप्त हुए अदालती दस्तावेजों के अनुसार, अफगानिस्तान में उसके परिवार को तालिबान की ओर से धमकियां मिली थीं, क्योंकि उसके भाइयों ने अमेरिकी सेना के समर्थन में काम किया था। डेविड ने बताया कि इस अफगान नागरिक का एक भाई अमेरिका में रहता है और उसने अफगान राष्ट्रीय सेना में सेवा की थी। तालिबान के 2021 में सत्ता पर कब्जा करने से पहले अफगान राष्ट्रीय सेना अमेरिकी सेना के साथ मिलकर काम करती थी। उन्होंने बताया कि उसका एक अन्य भाई अमेरिका में प्रशिक्षित पायलट था, जिसकी तालिबान ने हत्या कर दी थी।

ऑफ बीट

क्या वजन से स्वास्थ्य का आकलन हो सकता है

हमें पढ़ाया गया है कि दुबलेपन का सेहत से और अधिक वजन का बीमारी से संबंध होता है। लेकिन विज्ञान एक ज़्यादा बारीक कहानी कहता है–जहां वजन एक कहीं ज़्यादा जटिल तस्वीर में सिर्फ एक आंकड़ा भर है। तो अगर अकेले वजन ही यह नहीं दर्शाता कि हम कितने स्वस्थ हैं, तो और क्या दर्शाता है? शरीर का वजन स्वास्थ्य के सबसे ज्यादा मापे जाने वाले पैमानों में से एक है। समाज इस पर बहुत जोर देता है और किसी व्यक्ति के वजन की आलोचना को अक्सर स्वास्थ्य संबंधी चिंता के रूप में देखा जाता है। तो वजन असल में कितनी सार्थक स्वास्थ्य जानकारी प्रदान करता है? सीधे शब्दों में कहें तो, व्यक्ति का वजन शरीर द्वारा ग्रहण की जा रही कैलोरी पर निर्भर करता है। समय के साथ वजन में बदलाव कैलोरी की खपत की ओर इशारा कर सकता है। अगर उनका वजन बढ़ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वे जितनी कैलोरी जला रहे हैं, उससे ज़्यादा सेवन कर रहे हैं। वहीं, अगर उनका वजन घट रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वे जितनी कैलोरी ले रहे हैं, उससे ज़्यादा जला रहे हैं। शायद यह समझना ज़्यादा उपयोगी होगा कि वजन हमें स्वास्थ्य संबंधी कौन-सी जानकारी नहीं देता।

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से hbcgpati@gmail.com पर भेज सकते हैं।

Last Day To Join Private Channel. Closing entry for new members Now.

♦ **Indian Newspaper**

1) Times of India
2) The Hindu
3) Business line
4) The Indian Express
5) Economic Times

And more Newspapers

♦ **InternationalNewspapers channel**

[Europian, American, Gulf & Asia]

♦ **Magazine Channel**

National & International

[Genaral & Exam related]

♦ **English Editorials**

[National + InternationalEditorials]

Click here to join

♦ Lifetime validity at just 19 Rupees 📍

Trust me... this will be your best purchase of 2026